साप्ताहिक

पृथ्वी पर हम सब समय माया के यात्री हैं

समय माया

प्रधान संपादक- अजमेरा एस.पी. कुमार

Website: www.samaymaya.com
Email: samaymaya@gmail.com
samaymaya@rediff.com

Cell: +91 9300755803, 9425125569
Phone Fax: +91 731 2530859

(C) All Copyrights reserved with chief editor, do not publish any matter without prior written permission

In case of any dispute, may be solved only in Indore Court Jurisdiction

वर्ष 5 अंक 45 | प्रति सोमवार इंदौर, 11 जून से 17 जून 2012 | पृष्ठ 12 | मूल्य 2/- रुपए

ओबामा ने सत्ता संभालते ही भारत को बहुत कोसा

पुनः न चुनें, अमेरिकी ओबामा को राष्ट्रपति

हर क्षेत्र में असफलताओं के झंडे गाढ़े बेरोजगारी बढ़ाई, बहुराष्ट्रीय कम्पनी की कठपुतली बन नाचते रहे

अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के आने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई, कर्ज ले-लेकर अर्थव्यवस्था चलाई जा रही है। शासकीय कर्मचारियों और अधिकारियों को वेतन बढ़ाने के विपरीत घटा दिया गया।

ओबामा ने राष्ट्रपति बनने के बाद 200 से ज्यादा अमेरिकी बैंक दिवालिया हो गए। इन बैंकों के दीवाले निकलने से सबसे ज्यादा काला धन भारत के 1 लाख से ज्यादा पूंजीपतियों, सत्ताधीशों, राजनेताओं, अधिकारियों का ही डूबा, जो कि 20 लाख करोड़ से ज्यादा था, जिसका 10 प्रतिशत भी अंतरिम भुगतान नहीं मिला। बेशक सब डुबाकर भी मुंह सा आवाज तक नहीं निकाल सके। आखिर ये नुकसान भी तो राष्ट्र का ही था। अमेरिका में अनेकों उद्योगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और बंद कर दिए गए। स्वाभाविक था लाखों अमेरिकी बेरोजगार हो गए। नए उद्योगों के अभाव में पुराने कई उद्योंगों, ऋण क्षेत्र में से मंदी के चलते लाखों लोगों को नौकरी से हटा दिया गया, जो ओबामा के लिए अभिषाप है। अधिकांश युरोपीय राष्ट्रों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजावादी व्यवस्था में केवल लाभ कमाने के लिए जनता का शोषण हर प्रकार से किया जाता है। अमेरिका में सभी उद्योगों, जिसमें उत्पादन सेवाएं आदि सभी कुछ निजी क्षेत्र की बहुराष्ट्रीय क़ंपनियों के हाथ में है।इसके विपरित इन लुटेरी, डकैत, जालसाज कम्पनी के शोषण और लूट अमेरिका जैसा राष्ट्र दिवालियेपन की कगार पर आ खड़ा हुआ है, जबकि इन्हीं क़ंपनियों के विदेश व्यवसाय के लिए कभी ओबामा दबाव डालता है तो कभी हिलेरी क्लिंटन भारत आकर वैश्याओं के मिलने और सहायता देने के बहाने बंगालिन बाघिन ममता बनर्जी पर देशी विदेशी सीधा फुटकर व्यवसाय में निवेश के लिए दबाव बनाने की रणनीति पर कार्य करती है। जो पैसा इन बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने अमेरिका की मंदी के चलते भारत के बहुधर्मी, सदाबहार बाजार में लगाना चाहती हैं।

(शेष पेज 5 पर)

काले धन को वापस लाने वालों के लिए रु. का अवमूल्यन

रुपए के अवमूल्यन से काली पूंजीलाने वालों की भारी कमाई

यह काला धन बढ़ाएगा भारी महंगाई, अमीरों गरीबों में गहरी होगी खाई

भारतीय रु. का पिछले 6 माह से लगातार अवमूल्यन हो रहा है। इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय कारण नहीं है। यह हमारे भूतपूर्व राज्यपाल और वर्तमान के हमारे महाधूर्व, भ्रष्टाचारी, गांधी के तीन बंदरों की तरह भ्रष्टाचार पर मैं कुछ कहूंगा। मैं चुप रहूंगा, मैंने कुछथ नहीं सुना, की जो भूमिक अदाकर रहे हैं। वो प्रधानमंत्री मनमोहनसिंह और वित्तमंत्री प्रणव मुखर्जी की उस चाल का परिणाम है, जिसेमें पिछले 6 माह से ज्यादा समय रु. विदेशों में जमा भारत के काले धन पर संसद में खेल पत्र लाने की घोषणा की थी, उस समय से ही रु. का अवमूल्यनकर विदेशों में जमा भारतीय रुपए को जो वहां डालर में जमा किया गया। काले धन वाले भारतीय राजनेताओं, आईएएस, आईपीसी, आईएफएस (विदेश सेवा), आईआरएस (राजस्व सेवा) के साथ ही बड़े औद्योगिक घरानों और पूंजीपतियों को वह पैसा देश में वापस लाने के लिए कह दिया गया ताकि उनके विदेशों में जमा अमेरिकी डॉलर भारत में रु. में परिवर्तित करते समय बढ़ा हुआ मूल्य मिलता रहे और उसका 5 से 10 प्रतिशत कमीशन इन धुर्तें के खाने में भी जमा हो जाए।

विदेशों में जमा काले धन के बारे में जब सीबीआई ने स्वीकार

किया कि रु. 72 लाख करोड़ से ज्यादा धन जमा है अर्थात यह आंकड़ा भी 5 से 10 प्रतिशत तो नहीं होगा। क्योंकि वह भी न्यूनंतम ही बताए हैं, पूरा 100 प्रतिशत होगा, सच तो नहीं बताया जा सकता। फिर काला धन जमा तो मात्र स्विस बैंक में ही नहीं विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की बैंकों में है। जहां की अर्थव्यवस्थाएं स्थिर ढंग से चल रही है। अधिकांश भारतीय काला धन रुपए को डॉलर में परिवर्तन शीलता के आधार पर ही वर्षों से जमा किया जाता रहा है। दुनिया में काले धन को जमा करने के लिए बेशक स्विजरलैंड का ही नाम लिया जाता है। जबकि भारतीय का सबसे ज्यादा काला धन अमेरिका की 200 से ज्यादा दिवालिया हुए बैंकों में भी डूबा जो कि लगभग 200 लाख करोड़ रुपए था, इसलिए सारे पूंजीपति, उद्योगपति, राजनीतिज्ञों, अधिकारियों, व्यापारियों को अमेरिका जाना काफी पसंद आता है। फिर इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, कनाडा से लेकर छोटे-छोटे देशों नार्थ थाइलैंड जैसे आवासिक छोटी अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी कहीं न कहीं सुनिश्चित तरीके से बैंकों में या व्यवसाय में विनियोजित है।

(शेष पेज 7 पर)

सिर्फ कमीशन डकारने-रक्षा संस्थान कुछ नहीं बनाते

राष्ट्रवादी होते तो श्रेष्ठ सेना होती दुनिया की

हमारे लोह अयस्क से बने हथियार खरीदते हैं... हम हथियारों के सबसे बड़े आयातक

हमारे राष्ट्र को आजाद हुए 65 वर्ष बीत गए। हमारे बाद भी चीन आजाद हुआ। चीन के पास जल, थल और वायुसेना का अधिकांश सामान अपने ही राष्ट्र में बनाता है। इसके विपरीत भारत जो दुनिया के, जिसमें अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन को लोहा और लौह अयस्क की मिट्टी तक निर्यात करता है, वहीं मिट्टी से लोहा निकालकर हमारे ही राष्ट्र को मोबाइल जिसमें 1 तोला भी लोहा नहीं है हमें सोने के भाव निर्यात कर देता है।

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्वीटरजलैंड, रूस जैसे 5 देशों की अर्थ्रव्यवस्था, वहां हमारे निर्यात, किए गए लोहे से बनाए गए लड़ाकू विमानों से लेकर, मिसाइलों, राइफलों, टैंकों यहां तक कि वहां के समयबाधित विमान वाहक पोतों को हम खरीदरकर चला रहे हैं। जबकि हमारे पास पर्याप्त मानव श्रमिक हैं। लोहा और सभी कच्चा माल है। पर हम स्वयं कुछ भी नहीं बनाते, जो बनाते हैं। उसे हमारी रक्षा सेनाएं जिसमें जल, थल, वायु सेना के स्तर का नहीं होता। इसलिए ट्रेट्रा ट्रकों से लेकर पनडुब्बियां, लड़ाकू वायु यान तक जो कि उनके यहां समय बाधित होकर कबाड़ में पटक दिए जाते हैं। हम उन्हें या हमारी रक्षा सेनाएं चाहे तो यह जल, वायु सेना मोटे कमीशन डकारने के लिए वहां के कबाड़े को बड़ी शान से खरीदते हैं और दंभ भरते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं। हमारे वायु सेना में मिग-21 जैसे लड़ाकू जहाज को कि 1970 के पहले ही रूसी वायुसेना ने कबाड़े से खड़ेकर दिए थे। हम 2012 तक उन्हीं को उड़ा रहे हैं और जानबूझकर उनके वायुसेना के विमान चालकों को उस फ्लाइंग कफन अर्थात उड़ते कफन में बैठा कर मौत के मुंह में धकेल रहे हैं।

(शेष पेज 3 पर)

आंदोलन का भरपूर सदुपयोग कर रही सरकारें-विरोध - नौटंकी

अन्ना-रामदेव का आंदोलन, बकवास

पूंजीवाद का पोषक, पहले आतंकवाद हथियार था, अब आंदोलन अपने कुकर्मों से जनता व मीडिया का ध्यान बांटने की

अन्ना रामदेव एंड कम्पनी में कोई भी किसी भी विषय मूलरूप से अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ नहीं है। जिसे सत्ताधीशों की धूर्तता, जालसाजियों और लूट के स्त्रोतों का अंदाजा हो। केवल भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार चिल्लाने, लोकपाल और कालाधन लाने के मुद्दे को चिल्लाने से कुछ नहीं होगा।

मुख्य मुद्दों से दूर भ्रष्टाचार क्यों और कैसे हुआ न तो इनके पास सोच है, न समझ, जितने कानून उतनी ज्यादा लूट और भ्रष्टाचार होगा। कानूनों की आड़ में अधिकारों के दम पर सत्ता में बैठा प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी सभी शासकीय पदों पर बैठे अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, संत्री, सब ही अपनी शक्तियों का उपयोग कर वसूली और भ्रष्टाचार करेंगे ही, क्या अरविंद केजरीवाल जब आयकर विभाग में था तो क्या अवैध वसूली अपने पद और शक्ति के आधार पर नहीं की। कानूनों के आधार पर जहां

जैसा लपेटे में आया, कानून के दम पर और पद की शक्ति के आधार पर वसूली की ही गई। बाबा अन्ना कितने पढ़े-लिखे है। कितनी जानकारी अर्थशास्त्र और कानून की है। वहीं योग गुरु बाबा रामदेव ने स्वयं योग की आड़ में धन योग सिद्ध किया कि नहीं। उनके योग की कक्षाएं और प्रशिक्षण मुफ्त में होता है। जब भगवा वस्त्र धारण कर लिए तो धन योग की सिद्धि क्यों? कहां से आया 1400 करोड़ रुपए की विशाल सम्पत्ति, फिर कितना आयकर, विक्रय कर चुकाया। इनकी कम्पनियों की बनाई हुई आयुर्वेदिक औषधियां दूसरी जानी-मानी भारत की आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं से क्यों दुगुनी तिगुनी महंगी है। यदि सचमुच में ही गरीबों और देश की जनता के हित चिंतक हैं तो भगवाधारी स्वादु योगी, अपने प्रातांजलि पीठ की सदस्यता शुल्क, वार्षिक शुल्क और आजीवन सदस्य के रूप में हजारों रुपए की वसूली करते हैं।

(शेष पेज 2 पर)

साप्ताहिक समय माया

संपादकीय

पूंजीवादी, शोषण से सबको बनायेंगे गुलाम

भारत की वर्तमान सत्ता में बैठे घोर लालची गिद्धों की फौज तात्कालिक मोटे कमीशन और रिश्वत जो अरबों और हजारों करोड़ डकारती हैं, बहुराष्ट्रीय देशी-विदेशी कं. के इशारे पर नाच कर जो विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक को हांकते हैं। पहले सत्ताधीशों को विकास के नाम पर लाखों-करोड़ रु. के ऋण पिलाती है, उनकी जानबूझकर तरीके से निगरानी इसीलिए नहीं करती कि सत्ताधीश और विकास कार्यों को संपन्न करने वाले अधिकारी उसे हजम कर जाये फिर ऋण वसूलने का दबाव बनाती है, फिर उस ऋण की आड़ में अपने नियम कानून बनवाकर वहां विश्व व्यापार संगठन का जाल फैलाती है, धीरे-धीरे वहां के व्यापार-व्यवसाय पर कब्जा जमाती है और बिजली, पानी, सड़कें, दूरसंचार, परिवहन से लेकर खाद्य व्यवसाय से लेकर खेतों तक पर कब्जा जमाती है, जैसा कि मेक्सिको से लेकर अमेरिका और अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में सारी सेवाओं को बड़ी-बड़ी पूंजीपतियों की बहुराष्ट्रीय कं. ने किया, वहां पानी के स्त्रोतों पर कब्जा जमा कर पानी भी इतना महंगा बेचना शुरू कर दिया कि आखिर मेक्सिकों में मारा-पीटी कर भगाना, पट्टा, वर्तमान में अमेरिका और यूरोप में बड़े-बड़े राष्ट्रों से लेकर जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ग्रीस से लेकर अनेकों छोटे राष्ट्रों तक ने न केवल विश्व व्यापार संगठन से नाता तोड़ लिया वरन अनेकों राष्ट्रों ने यूरोप की साझा मुद्रा से संबंध तोड़ लिये, क्योंकि वे इन पूंजीवादी शोषण से भारी त्रस्त हो चुके थे, जब अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे अनेकों यूरोपीय राष्ट्रों को इस पूंजीवादी शोषण की कहानी तरीके से समझ आई जब वह अर्थव्यवस्था न केवल पटरी से उतर चुकी थी वरन युवाओं को बेरोजगारी की भीषण समस्या से भी दो-चार होना पड़ रहा है।

भारत में कहावत है, घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध, यह कहावत, समय माया पर भी सिद्ध होती है, समय माया पूंजवादी शोषण के विरुद्ध और विश्व व्यापार संगठन के षड्यंत्रों के विरुद्ध अपने शैशव काल से ही जनहित में जो तथ्य प्रस्तुत करता रहा है, उसे यूरोपीय जनता के साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति को भी समझ आया, हमारी समय माया डाट कॉम की साइट से यूरोप में जो बेरोजगारी, शोषण और राष्ट्रों की अर्तव्यवस्था बिगड़ने से पूंजीवादी शोषण के सच को समझा गया, इसके विपरीत भारत के धूर्त सत्ताधीशों का गिरोह मोटे एकमुश्त कमीशन, दलाली, रिश्वतखोरी के चलते न केवल समझने को तैयार नहीं उन्हें ही वह राष्ट्रीय निगमों, विभागों, मंडलों को जिसमें राष्ट्र के राज्यों के विद्युत मंडलों को, राष्ट्र की लाखों कि.मी. सड़कों, रेलवे, राष्ट्र के प्राकृतिक जल स्त्रोतों, तेल, गैस स्त्रोतों, सिंचाई की नहरों, ताप, जल,विद्युत उत्पादन केंद्रों, दूरसंचार, डाकतार, परिवहन, साधारण रेत, गिट्टी, मिट्टी की खदानों से लेकर कीमतों धातुओं आभ्रक, स्वर्ण, रजत, हीरे, पन्ने से लेकर क्रोमोजाइट मोनोजाइट की खादानों तक को बड़े पूंजीपतियों को सौंपने और बेचने, गिरवी करने पर तुला है ताकि बदले में इन धूर्त गिद्ध सत्ताधीशों चाहे कांग्रेस का संप्रग हो या भाजपा का यूपीए गठबंधन हो, मोटा अरबों-लाखों करोड़ में कमीशन मिलता रहे।

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहां पूंजीपति को मोटा लाभ और जन शोषण का अवसर दिखेगा वो न केवल सत्ताधीशों वरन पूरा प्रशासनिक, न्यायिक कार्यपालिक तंत्र को खरीद और नियमित रिश्वत बांट कर अपनी जेब में लेकर चलता है, अपनी तरह से कानून बनवाकर जनता का घोर शोषण करता है, उसकी बला से बूढ़ा मरे या जवान, चांडालों की तरह हर जीवित और मृतों को लूटने से काम, जहां उसे घोर शोषण और निचोड़ने से भी आय और लाभ मिलना बंद, कंपनी, फैक्ट्री, व्यवसाय बंद, रोजगार व बेरोजगारी से मरे भूखे, उसे कोई चिंता नहीं। तो मुर्दों को भी नोंचकर अपने लाभ की व्यवस्था करेगा।

भारत में आजादी के उपरांत नेहरू-गांधी ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को इस घोषण शोषणकारी पूंजीवादी को इसीलिये नहीं अपनाया कि यह भारी दमनकारी थी। जिसके दमन के फलस्वरूप ही रूस, चीन, क्यूबा आदि अनेकों राष्ट्र में साम्यवादी अर्थव्यवस्था को जन्म दिया, जहां सब कुछ शासन का शासन ही जनता को मुफ्त बिजली, पानी, भोजन, सड़कें, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि जनता को देगा, बदले में जनता को शासन की इच्छानुसार कार्य संपादित करना होगा, पर इसका दोष यह था कि मजदूर दिल लगाकर कार्य संपादित नहीं करते थे। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर ही हमारे नेताओं ने सभी बड़े, बड़ी पूंजी निवेश वाले कार्यों,बीमा, बैंकिंग, परिवहन सेवाओं यथा रेलवे, बिजली, पानी, सड़कें, बांध, बड़े-बड़े भारी उद्योग, दूरसंचार, डाक-तार, खनन, बड़ी खदानें आदि को अपने हाथ में रखा, छोटे उद्योग खेती, व्यापार को निजी क्षेत्रों के लिये मुक्त रखा यह व्यवस्था 40 वर्ष तक न केवल सफलतापूर्वक चली, वरन विश्व में आई मंदियों का भी इस पर असर नहीं हुआ, भारी मंदी में भी हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति पथ तय करती रही, जनता भी समृद्ध हुई, जीवन स्तर भी उठा। अब जब हमारे सत्ताधीश मोटे कमीशन के लालच में पूंजीवाद की तरफ बढ़ रहे हैं तो सत्ताधीशों को कुछ वर्ष तो कमाई मिलेगी पर जैसे ही पूर्ण पूंजीवाद आयेगा सत्ताधीश भी इनकी कठपुतली बन फांके कसी पर आ जायेगा तब इसे उसकी औकात समझ आयेगी, जितने टुकड़े, जैसे टुकड़े पूंजीपति फेंकेगा ये चुपचाप खायेगा, अभी भी वक्त है कि सत्ताधीश, जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था में खरबों डकारकर विदेशों में भेजा है। पूंजीवादी व्यवस्था का हाल देख यूरोप का संभल जाये, अन्यथा यूरोप की तरह जनता सड़कों पर उतर करो या मरो का नारा देगी।

अन्ना रामदेव का आंदोलन बकवास

पेज 1 का शेष

आपकी आयुर्वेदिक औषधियां अन्य भारतीय आयुर्वेदिक औषधि निर्माताओं की तुलना में आधी कीमत पर क्यों? बेची जाती ताकि उसे आम गरीब जनता भी खरीद सके। साथ ही भारतीय विश्व की आदिकालीन प्राचीन तम आयुर्वेद पद्धति को पूरे विश्व में पुर्नस्थापित कर विश्व की जनता को भारत के मूल ज्ञान अस्तित्व का अहसास करवाकर श्रेष्ठता स्थापित की जा सके। जब आप स्वयं विक्रय कर, कस्टम एक्साइज और आयकर की चोरी में लिप्त हैं, स्वयं भ्रष्टाचारी हैं, तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन में आप कैसे सफल होंगे मूर्ख हैं तुम्हारे झंडे के नीचे आने वाले वाले लोग।अब इनकी एक महत्वपूर्ण सदस्य और पूर्व पुलिस अधिकारी किरण वेदी जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकपाल और कालेधन की वकालत कर रही हैं। तो बताओ जो पुलिस विभाग में जो अरबों रुपए प्रति माह की अवैध वसूली, जुए-सट्टे, चकले चलाने वालों, ड्रग माफियाओं, वैश्यावृत्ति के अड्डों, बड़े पूंजीपतियों, जालसाजो, माफियाओं, अवैध शराब बेचने वालों, जिस समय से दिल्ली पुलिस में थी उस समय भी 5 अरब रुपए की वसूली दिल्ली में चलने वाले अवैध वाहनों से की जाती थी। मटका चलाने वालों से भी अरबों में वसूली होती थी, उसका हिस्सा लेती थी या नहीं। जल ये पुलिस अधिकारी थी तब भी दिल्ली में 5 सट्टे जो दिन में सुबह 9 बजे, दिन में 12 बजे, 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात्रि 9 बजे और 11 बजे 3 स्थानों से खुलते थे कितनो को बंद करवाया। कितनी होटलों में अवैध जुए पकड़े, रेडलाइट एरया क्या बंद करवा पाई, होटलों में वैश्यावृत्ति और कॉल गर्ल के रैकेट चल रहे हैं। पिछले 50 वर्षों से कितनों को बंद करवाया, बस अवैध पार्किंग में खड़े वाहनों को उठवाने से क्रेन वेदी के रूप में भर लोकप्रिय हो पांई अर्था पुलिस का ये चेहरा को चमकाओ 100 से खाओ के सदा ही चर्चित रहता आया है। आप की ईमानदारी के इतिहास को बताएं। नारी प्रकृति से लालची और चालाक होती है, प्रकृति ने ये गुण उसे मां बनने के कारण दिया है। फिर उसे सत्ता मिल जाए तो देख सकती है स्व. इंदिरा गांधी के इतिहास को देखकर ब्याज और ऋण का दायित्व क़म या समाप्त कर दिया जाए। पर यह समानुपातिक हो, ऐसा नहीं कि केन्द्र सरकार उस ऋण से केवल कांग्रेसी सरकारों के ही ऋणों और ब्याज का दायित्व कम करे हर राज्य सरकार को समान अनुपात में बांटे, बचने पर राष्ट्र की सड़के जो जनता और राष्ट्र की जीवन रेखाएं हैं जो इन सत्ताधीशों ने अपने ही लोगों को बनाओ, चलाओ और लौटाओ में गिरवीकर दी है। उन्हें भी समानुपात में केन्द्र और राज्य के राजमार्ग के ठेकेदारों को बांटकर सड़के मुक्त की जाएं।

अन्ना रामदेव के आंदोलन नौटंकियों का सरकार ने हर कदम भरपूर लाभ लिया जब पिछले वर्ष अन्ना और रामदेव नौटंकी रामलीला मैदान पर चल रही थी, तब जानबूझकर उसमें पुलिस लाठीचार्ज करवाया गया बाद में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर पुलिस को लताड़ लगाई। इस पूरी नौटंकी का फायदा केन्द्र की सत्ताधीश धूर्त-गिद्ध कांग्रेसियों और उसकी यूपीए गिरोह ने भरपूर उठाकर जब जनता और मीडिया उसमें उलझा था। राष्ट्र में पूंजीपतियों को देश का पूरा खाद्य पदार्थों का कारोबार सौंपने 36 करोड़ को भूखा मारने और 5 से 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार करने खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिष्ठ जो 5 वर्ष से बना पड़ा था। 5 अगस्त 2011 से लागू कर दिया। चुपचाप अन्ना और रामदेव की नौटंकी को मीडिया पर प्रसारित करता दिखाता रहा और उसको वहां उलझाए रखा। पहले अपने कुकर्मों, भ्रष्टाचार से ध्यान हटाने के लिए कांग्रेस आतंकी हमलों का सहारा लेती थी। अब वही काम कांग्रेस के लिए अन्ना रामदेव एंड कम्पनी कर रही है। अभी पेट्रोल की कीमतों को एकदम 8 रुपए बढ़ाकर जनता का ध्यान बंटाने अन्ना रामदेव एंड कम्पनी फिर आंदोलन की नौटंकी कर रही है। दूसरी तरफ 36 रुपए से ज्यादा बढ़ गई है। इसकी आड़ में कालाधन भारत में लाकर उस पर भी भारी मुनाफा बटोरा जा रहा है। तीसरी तरफ कांग्रेस का भारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में बदलने के लिए खरबों रुपए की सड़कों, विद्युत मंडलों, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय जल आपूर्ति और प्रबंधन व्यवस्था को रेलों, भारत संचार निगम लि., डाकघर, जल संसाधनों वर्तमान में जीवित माया के जीवित रहकर भी अपनी मूर्तियों पर जनधन की बर्बादी से, जय ललिता 6000 जोड़ी जूतियां और सेंडिल देखकर और लाखों महिलाएं जो सत्ता में पद और शक्ति सम्पन्न है। उनकी नोंच-खसोट, भ्रष्टाचार को देखरर अब आप के पास सभी सम्पन्नताएं थी, जो जनता में लोकप्रियता प्राप्त करने के लालच में आप आंदोलन में कूद पड़ी। फिर भी स्वागत है।

अब अन्ना के लोकपाल बिल की बात करें तो भारत में पहले से ही बहुत सारे लिखित कानून हैं। उनका भी तरीके से सदुपयोग हो जाए उतना ही काफी है। क्योंकि लोकापल बन भी जाए तो उसके पदाधिकारी भी कोई देवपुरूष नहीं होंगे वे भी साधारण इंसान और हर मनुष्य काम, क्रोध, मद, मोह, माया का पुतला होता है, जिसे लोकपाल बनाकर बैठाया गया वह भी लूटेगा और भ्रष्टाचार करेगी ही। भ्रष्टाचार उसे भी लक्ष्मी समर्पित करेंगे और धन किसे नहीं चाहिए वो भी डकारकर जांच पूछताछ को कम से कम लंबित तो कर ही देगा माह दो माह से वर्षों तक फिर योगी या ढोंगी रामदेव का कालाधन वापस महंगाई लाना ही चाहिए। पर जितना काला धन आएगा महंगाई उतनी ही बढ़ेगी, क्योंकि जितना रुपया चलन में आएगा उसकी उतनी ही कीमत बढ़ेगी। काला धन जो सरकार 27 लाख करोड़ रुपए बता रही है। वह 10 से 15 प्रतिशत से ज्यादा तो नहीं बताएगी। यह वास्तविकता में 1000 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो सकता है और विश्व के हर देश की बैंक में यहां तक कि हमारे पड़ोसी शत्रु राष्ट्रों की जैसे चीन और पाकिस्तान बैंकों में भी होगा। क्योंकि जिन व्यापारियों का निर्यात आयात का कारोबार है, वो जान बूझकर भारत में आयकर विक्रयकर, कस्टम व एक्साइज ज्यादा न चुकाना पड़े अपना धन वहां की बैंकों में रखते हैं।

विदेशों में जमा भारतीयों का काला धन लाया अवश्य जाए, उसे राष्ट्रीय सम्पत्ति कर जिन सरकारी जन कल्याण कारी योजनाओं में निवेशकर ऋण के रूप में लिया गया है उसका चुकारा किया जाए ताकि वास्तविकता में सरकारों पर जिसमें प्राकृतिक नदियों, तालाबों आदि तक पूंजी पतियों द्वारा लाए विदेशी और देशी काले धन का निवेश सुनियोजित तरीके से इन शासकीय विभागों, निगमों आदि को पहले शासकीय कम्पनी में फिर उनमें अरबों रुपए का घाटा दिखाकर निजी कम्पनियों को बेचना और निजी हाथों में सौंपने का षड्यंत्र सम्पन्न कर रहे हैं।

जिस पूंजीवादी से अमेरिका और पूरे यूरोपीय देश बर्बाद हो चुके हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषण के विरुद्ध वहां की जनता आंदोलन कर भगा रही है। वहीं वालमार्ट और अनेकों बहुराष्ट्रीय कम्पनी को भारत के केन्द्र और राज्यों के धूर्त सत्ताधीश गिरोह मोटा धन हड़प कर उनके पैर जमाने में लगा है, जिसे अन्ना रामदेव एंड कम्पनी के आंदोलनों की नौटंकी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है।

धूर्त कांग्रेस और संप्रग गिरोह इन आंदोलनों को चलता बनाए रखने के लिए लोकपाल औव कालेधन के मुद्दे पर उल्टे सीधे बयान देकर आंदोलन की आग को जलता रखना चाहते हैं ताकि ये अपने कुकृतों और भ्रष्टाचार और पूंजीवादी व्यवस्था में परिवर्तन के कार्यों को सम्पन्न करता रख सके।

यही कारण है कि अन्ना रामदेव एंड कम्पनी या शिक्षा और गहरे ज्ञान का अभाव है अन्यथा मूर्खता की तो कॉर्पोरेट सेक्टर मीडिया और न्यायालयीन भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ नहीं बोलेंगे। ये तीनों ही अर्थात न्यायालयीन व्यवस्था जिसके बारे में पूर्व राष्ट्रपति स्व. के.आर. नारायणनन ने 25 जन 2001 को कहा था कि न्यायालय न्याय के मंदिर नहीं वरन् जुए के अड्डे हैं। जो जितना बड़ा दांव खेलेगा उसे उतना न्याय मिलेगा। सिद्ध करता है कि न्यायालयीन व्यवस्था ही भ्रष्टाचार के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जहां वर्षों तक फैसले ही नहीं होते। 25-25 वर्ष तक जिस भोपाल गैस कांड से समझा जा सकता है।

दूसरा है कार्यों रेट सेक्टर जिसमें अंबानी बंधु, टाटा, बिरला, भारती, सहारा जैसे सैकड़ों पूंजी पति धन खर्च करके कानून तक बनवा लेते हैं। बदलवा देते हैं या कानून खत्म ही करवा देते हैं। जैसे खाद्य अपमिश्रण और निवारण अधि. 1954 को समाप्त करवाकर अपने पक्ष में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 06 बनवा लिया गया। भूमाफियाओं और कालोनी माफियाओं ने लैंड सीलिंग एक्ट समाप्त कर दिया अब तो कहीं भी कॉलोनी काट कर चवन्नी का माल 4 रुपए प्रति वर्गफुट में बेचते हैं। देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस भंडार केजीबोसिन-6 जिसे ओएनजीसी ने खोया था, रिलायंस के हाथ में कैसे गया? जैसे कदम-कदम पर कार्पोरेट सेक्टर ने जाल साजियां की और कर रहा है और सत्ताधीश श्वान इन पूंजीपतियों के फेंके रिश्वत की हड्डियों के टुकड़े चूस मस्त हो रहे हैं। अब इनके विरुद्ध आंदोलन नहीं होगा तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा या कम होगा। फिर लोकपाल कानून के अधिकारी भी इन पूंजीपतियों के टुकड़े खोर हो जाएंगे को क्या होगा एक कानून और बन जाने से।

उपरोक्त तथ्य अन्ना रामदेव एंड कम्पनी के आंदोलन की यथार्थ स्थिति प्रगट करते हैं। जब दिशा ही ठीक नहीं है तो सत्ताधीशों को तो ऐसे नौटंकी बाजों की सदा ही आवश्यकता रहती है। फिर मुफ्त में जंतरमंचर पर मिले या रामलीला मैदान में, बस आंदोलन की आग में शब्दों का ही घी डालकर उकसाना है तो कांग्रेस में दिग्गी दानव जैसे बेलगाम श्वानों की कमी नहीं।

पहले कुक्रमों और भ्रष्टाचार को ढंकने और मीडिया व जनता का ध्यान बंटाने के लिए आतंकवाद हथियार था, अब बिना रक्त पात के और बिना कानूनी झंझटों से उलझे और उलझाए बिना आंदोलन हथियार बन चुके हैं। जनता और मीडिया का ध्यान बंटाने और कुक्रमों और भ्रष्टाचार महंगाई से लूट और वसूली रुपए की गिरती कीमतों और कालेधन पर लाभ कमाने के कुकृत्यों से जनता का व मीडिया का ध्यान बंटाने के।

कदम-कदम पर रेलवे यात्रियों और उनकी जेबों से बलात्कार

भारतीय रेलवेज लाखों यात्रियों का रेप वेज

ममता ने भले ही किराया नहीं बढ़ाया-लूट के अन्य रास्ते बढ़ाए

भारतीय रेलें पिछले 3 वर्षों से तृणमूल के खाते की ममता हीन सम्पत्ति बनी हुई है, जिसमें पिछले 8 वर्षों से तृतीय श्रेणी का किराया भले ही न बढ़ाया हो, पर निजी स्तर पर कमाई करने यात्रियों के साथ और उनकी जेब से बलात्कार करने के अन्य सैकड़ों विकल्प जरूर पैदा कर दिए गए हैं। अन्य देशभर के प्लेटफार्म पर ठंडा पानी तो दूर पानी ही नहीं मिलता है। यदि यात्रियों को प्यास बुझानी है तो रुपए 12 से 25 तक की 500 मि.ली. से लीटर भर की बोटलें जिसमें सामान्य नगर निगम के 10-20 पैसे के पानी को 14 से 25 रुपए तक में उपलब्ध होता है। अगर अपनी यात्रा में उसमें 2 ली. पानी भी पिया और उपयोग किया तो 50 रुपए का कम से कम जेब के साथ रेल्वेज बलात्कार करेगा। वह पानी 4-5 डिग्री तक भी ठंडा तो दूर 15 डिग्री तक भी ठंडा नहीं होगा। अब प्लेट फार्मों ट्राली पर गर्म दाल, चावल, पूड़ी-सब्जी, गर्म समोसा, कचोड़ी, भजिए, मंगोड़े, डोसे-इडली से लेकर चाय, काफी दूध तक नहीं मिलते हैं। ये सब खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 06 की भेंट चढ़ा दिए गए। इस प्रकार भारत के 9000 से ज्यादा प्लेट फार्म पर कार्यरत 2 लाख लोगों को बाहर भगाकर रोजगार बना दिया गया है। जो प्लेटफार्मों पर 5-10 ठेले मिलेंगे उन सब पर नकली, रसायनों से युक्त बने दूध की चाय, काफी और दूध मिलेगा। गर्म समौसा, कचोड़ी, डोसे, इडली संभार रोटी, चपाती, पापड़, दाल, चावल, सब भारतीय व्यंजन समाप्त कर दिए गए हैं। अब मात्र पैकेट बंद खाना जिसमें 3 रोटी, 50-70 ग्राम दाल, एक सब्जी, 50-100 ग्राम पके चावल जिन की कीमत मात्र 20 से ज्यादा नहीं होती है रुपए 60 से 80 के पैकेट में मिलेगी। वह भी मंत्री के रिश्तेदार ठेकेदार की या किसी बड़े पूंजीपति ठेकेदार की जो लाखों रुपए प्रतिमाह की मोटी रिश्वत हर महीने रेल मंत्रालय तक पहुंचाता है। घोर लालची भूखी बंगालन ममता बनर्जी ने किराया भले ही न बढ़ाया न बढ़ने दिया तो मात्र झूठी बात, वाहवाही लूटने के लिए। इसके विपरीत करोड़ों गरीबों विशेष तौर पर बिहारी, उड़िया, बंगाली, यूपी के गरीब मजदूरों और राष्ट्र के प्रतिदिन क्रम से 80 लाख यात्रियों के सुविधाओं के साथ बलात्कार कर मेहनत की कमाई को प्लेट

फार्मों पर लूटने की व्यवस्था अवश्य कर दी है। पूर्व में न केवल प्लेटफार्मों पर ठंडे पानी के कूलर्स चलते थे और डिब्बों में भी ठंडे पानी के मटकों की व्यवस्था की जाती थी, वह सब गायब हैं, हां रेलों के कर्मचारियों और अधिकारी इनकी खरीदी रखरखाव का करोड़ों रुपए जरूर एक तरफ हजम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे ठेकेदारों को प्लेटफार्मों और कोचों में ठंडे पानी के मटकों की व्यवस्था से वंचित कर हर यात्री से 50 से 100 रुपए लूटवाकर उनका फायदा करवा कर अपनी लूट की व्यवस्था कर रहे हैं।

प्लेटफार्मों से गर्म खाने चाय, दूध, काफी और फल फ्रूट्स आदि बेचने वाले लाखों विक्रेताओं को बेरोजगार बनाकर इसलिए ही हटवाया गया ताकि यात्री इनके माध्यम से ताजे व गर्म खाद्य पदार्थों को खरीदकर अपना पेट न भर सकेगा तो स्वभाविक है। वह 50 ग्राम बिस्किट नकली क्रीम और दूध की पैकेट रुपए 20 से 25 को खरीदकर अपना पेट भरेगा और समय पास कर इनकी चौगुनी से दसगुनी कमाई करवाएगा। ठेले वाले विक्रेता इन बड़े डकैत, ठेकेदारों से न केवल प्रतियोगिता करते थे कम कीमत और कम सामान बेंचने के लिए मजबूर भी करते थे। फिर पहले यात्रियों के पास खाद्य व पेय सामग्री के क्रय के विकल्प मौजूद थे। अब इन गरीबों को भगाकर इन हरामखोर रेलवे के जालसाज मंत्री और अधिकारियों ने ठेकेदारों की महीना खाकर उनके फायदे के लिए न केवल आवश्यक सुविधाओं, छोटे विक्रेताओं को समाप्त कर यथार्थ में यात्रियों के बलात्कार और वसूली का ठेका मंत्रियों के बलात्कार और वसूली का ठेका मंत्रियों, अधिकारियों के रिश्तेदार बड़े पूंजीपतियों ठेकेदारों को सौंप दिया। अब ये ठेकेदार जो खिलाएंगे-पिलाएंगे, वहीं यात्रियों को उनकी मुंह मांगी कीमतों पर अपनी तन-मन की भूख प्यास को शांत करने के लिए चुकाकर खाना पड़ता है। यह स्थिति जंक्शन स्तर के बाद महानगरों के रेल प्लेट फार्मों की है। छोटे स्टेशनों पर तो पानी से लेकर चाय, दूध, कचोड़ी, समौसे या अन्य क्षेत्रीय प्रचलित खाद्य पदार्थों की बिक्री अब दिवास्तान बन चुकी है।

इसके साथ रेले की व्ययवस्थाओं भी यात्रियों के साथ तन-मन-धन से शोषण उत्पीड़न और यात्रियों के बलात्कार में जुटी हुई है। द्वितीय श्रेणी के अनारक्षित श्रेणी के टिकिट पर रेलों में बैठने की तो दूर खड़े रहने की व्यवस्था भी ढंग से नहीं मिल सकती, यदि आप दरवाजे के आसपास खड़े हुए हैं तो हर आनेजाने वाला आपको धकियाता-मुकियाता, लतियाता चलेगा, यदि मादा यात्री है तो टीटी, पुलिसवालों से लेकर, यात्री, भिखारी, झाड़ू लगाकर मांगने वाले पुरती नजरों से बलात्कार करने से लेकर यदि मादाएं खड़ी हैं। किसी न किसी बहाने बदन छूते बदन रगड़ते हुए निकलेंगे। जबकि आपके पास द्वितीय श्रेणी कै वैद्य टिकिट है तो आपके पास बैठने का तो दूर सामान्य वर्ग के डिब्बे में दो पैरों पर खड़े होने का हक भी नहीं है। इसके साथ ही आपके पास आरक्षित श्रेणी का भी टिकिट, सीट पूर्णतः क़ंफर्म है, तो भी टीटीई आपको उठाकर भी दूसरे को सीट देकर पैसे अंदर कर लेता है। स्वामित्व है आरक्षण रद्द होने पर या इंतजार वालों से शायिकाएं सीट प्राप्त करने के लिए ऊपर नीचे वसूली की जाएगी। अर्थात तब भी यात्रियों की जेब से बलात्कार किया ही जाएगा, जबकि दोनों ही अव्यवस्थाओं में यात्री आरक्षण का पूरा भुगतान कर चुकने के बाद भी उसकी जेब वसूली की ही जाएगी।

दूसरी ओर इंतजार में और आरक्षण रद्द होने वाले यात्रियों के साथ चालक पटा और शोषण करते हुए तत्काल में क्यों और कैसे अधिक धन लेकर, ज्यादा धन देने वालों को आरक्षण दे दिया जाता है। इस प्रकार रेलवे अपने ही नियमों का उल्लंघन कर यात्रियों की जेब और मानसिक रूप अपनी रेप वेज की ही सत्य सिद्ध करता है।

राष्ट्रवादी होते तो श्रेष्ठ सेना होती दुनिया की

पेज 1 का शेष

अभी तक वायुसेना ने इस जहाज में बैठाकर 400 से ज्यादा विमान चालकों को मौत के मुंह में धकेल कर खोया है। वही हाल सुखोई 30 का है, जिसे रसियन वायुसेना ने 1985 से पहले ही अयोग्य और समय बाधितकर कबाड़ में खड़े कर दिए थे, उन्हें हमारा रक्षा मंत्रालय कमीशन के चलते खरीदे गए। यही हाल मिराज 2000सी हैरियर, मिग 22 से लेकर 23 तक, हेलिकॉप्टरों आदि का है जो वायुसेना उपयोग करती है।

हमारी हिन्दुस्तान एरोनाटिकल लि. सफेद हाथी बन अरबों रुपए की तनख्वाह डकार रहा है। उसने जो तेजस बनाया, उसमें भी कहीं की ईंट, अर्थात इंजन कहीं का एयर फ्रेम, उसे भी जोड़ कर अपने योग्य बनाने में इस हाल (हि.ए.सि.) को वर्षों गुजरे। यहां तक कि वो वायुसेना के विमानों का भी ढंग से रखरखाव करने में नाकाम रहा। जबकि हमारे पड़ोसी शत्रु चीन ने अमेरिकी एफ-16 जैसे विमानों की नकल तैयार कर अपने नाम दे दिए। हमने 65 वर्षों में क्या किया। बस विदेशी समय बाधित लड़ाकू विमानों का कबाड़ा खरीदकर येन-केन प्रकरण केवल चीफ बनाए हुए हैं, जिसके उदाहरण शांति काल में ही प्रशिक्षण व परीक्षण उड़ानों में ही मिग, सुखोई, मिराज जैसे लड़ाकू विमान यहां-वहां टपकते रहते हैं।

हमारे सत्ताधीश जो केन्द्रीय सत्ता में बैठकर रक्षा मंत्रालय चला रहे हैं। वो अच्छी तरह से अपनी औकात जानते हैं। इसलिए चीन, पाकिस्तान जैसे छोटे राष्ट्र हमारे हैलिकॉप्टर टपकाते रहते हैं। हमारे कमीशन खोर भ्रष्टाचार शूकरों की सत्ताधीश फौज सब जानकर भी, मौसम की खराबी, मानव जन्यत्रुटि, यांत्रिक खराबी बताकर, सच को छुपाकर अपने पड़ोसी शत्रुओं को मुंह तोड़ जवाब देने से कमजोरियों के चलते बचती है। इसके साथ ही ऐसे विमानों में लगने वाली युद्धक सामग्री को भी उन्हीं देशों से खरीदकर हर वर्ष मोटा कमीशन उकारती रहती है। इस प्रकार रूस, ब्रिटेन, फ्रांस की अर्थव्यवस्था को हम चलाते रहते हैं। हमारे रक्षा संस्थान इन विमानों का ढंग से गोला-बारूद, मिसाइलें, तक से नहीं बना पाते।

थल सेना की तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि विटजर तोपें जिस बोफोर्स तोप के नाम से जाना जाता है। हमारे रक्षा मंत्रालय ने स्विटजरलैंड से खरीदा, जितनी खरीदी की थी, उतनी ही है। हमारे जबलपुर स्थित गनकेरेज फैक्ट्री ने उससे ज्यादा उन्नत तोपें भी नही बनाई, उसका गोला-बारूद भी हमारी फैक्ट्रियां ढंग से नहीं बना पा रही है। उसके कमीशन की कहानी अभी भी जुबानी है। यही हाल है कि तोपों से लेकर ट्रकों तक का है। व्हीकल फैक्ट्री जलबपुर से ट्रकों को न लेकर टाट्रा ट्रक विदेश से कमीशन के चलते ही खरीदे गए। व्हीकल फैक्ट्री के इंजीनियरों, कर्मचारियों को वर्षों से रक्षा मंत्रालय ही वेतन बांट रहा है। तो फिर हमारी फैक्ट्रियों का क्या उपयोग हो रहा है। हमारे राष्ट्र में 39 आर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं। 40वीं नालंदा बिहार में बन रही है, जिसमें 10 महाराष्ट्र में, 6 म.प्र. में, 7 उ.प्र. में है।

जबलपुर स्थित सारी आर्डिनेंस फैक्ट्रीज जो अंग्रेजों ने बनाई थी अधिकांश उसी ढर्रे पर काम कर रही है। उनमें आधुनिकी करण आदि से कोई खास फेर बदल नहीं किया गया। फिर हमारी जल, थल, वायु सेना की आवश्यकताओं और वर्तमान युग की सैन्य आवश्यकताओं के अनुसार रक्षा साथ ही आने वाली भविष्य की अग्रिम चुनौतियों, अनुसंधान के लिए विस्तार मात्र इसलिए ही नहीं किए जा रहे हैं कैसे जनधन को हड़पा जाए। अगर सब कुछ रक्षा संस्थान ही बनाने लगेंगे तो फिर रक्षा मंत्रालय,सचिवों, मंत्रियों, सैन्य अधिकारियों के खरीदने के नाम पर विदेश यात्राएं कैसे होंगी, कैसे करोड़ का कमीशन उसके साथ सुरा सुंदरियोह का योग और भोग कैसे मिलेगा? इस लालच ने ही हमारे पड़ोसियों के हौंसले बुलंद किए और हम न केवल चीन, वरन् बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे राष्ट्रों से भी भयभीत रहते हैं। यहां तक कि हम अरबों रुपए की उन्नत एके 47, एके 56, से लेकर लाइट, हेवी मशीन गन्स तक जो हमारी सीमा सुरक्षा, राज्यों की पुलिस, वन विभाग, आबकारी तक रक्षक को लगती है। वो तब विदेशों से खरीदते हैं। बस एक ही लालच कमीशन, सुरा सुंदरी भोग, विदेश यात्राएं आदि मिलता रहे, जबकि आधा किलो लोहे की पिस्टल भारत में उसकी लागत हजारों में होती है। हम 10 से 1000 गुना कीमत में खरीदते हैं और इस जन धन की वसूली के लिए गरीबों को वक्त की रोटी भी नहीं मिलने देते। हमारे सत्ताधीशों धूर्तों के इस बारे में शर्म तो दूर सोचते भी नहीं।

वायु सेना के संबंध में हमारी स्थिति और भी बुरी है। हमारे राष्ट्र में वायुसेना के सारे विमान विदेशों से खरीदे गए होते तो उनके सारे कलपुर्जे विदेशों से ही आयात करने पड़ते हैं। यहां तक उसमें लगने वाले नट बोल्ड तक भी उसी निर्यातक से खरीदने पड़ते हैं। जिसने हमें अपना कबाड़ा बेचा होता है। अर्थात उनके यहां के जो जहाज समय बाधित होकर वर्षो से भंगार में खड़े होते हैं और उन राष्ट्रों की वायुसेना चाहे तो रूस हो, ब्रिटेन, फ्रांस जिनके मिग 21, मिग 23, जगुआर, सी हेरियर, मिराज फाल्कन, अभी तक नट बोल्ट से लेकर इंजन व कलपुर्जे उन्हीं देशों से आयात करने पड़ते हैं। भारत को सस्ते हथियार बेंचने वालों में रूस दूसरा इसराइल जिसकी आबादी मात्र 50 लाख है। भारत की 125 करोड़ की आबादी वाले राष्ट्र को बेंचता उसका सारा लोहा भारत के माध्यम से ही जाता है। तीसरा अमेरिका और चौथा है फ्रांस, जिसका मिराज 2000 है।

रूस से एके 47 से लेकर मिग 21, मिग 23, सुरकेई और जल सेना के लिए गोर्श कोब, सभी समय बाधित कचरा खरीदा गया। रूस की डूबती अर्थव्यवस्था को भारत ने रक्षा सामग्री का कचरा खरीद कर उबारा।

विश्व में भारत हथियारों का सबसे बड़ा खरीददार है, जो कि 10 प्रतिशत से कहीं ज्यादा खरीदी कर आयात करता है। दूसरे क्रम में दक्षिण कोरिया, तीसरा पाकिस्तान, चौथा चीन और पांचवा सिंगापुर है।

अपने राष्ट्र की तुलना अगर हम चीन से करें तो चीन ने पिस्टल से प्लेन तक सबकुछ बनाना शुरू कर दिया है और वह वर्तमान में विश्व का 6टा निर्यातक देश बन चुका है। इसके मूल में है, तो बनाने में क्या मिलेगा। कमई तो सत्ताधीशों की खरीदी के कमीशन से ही होगी। इसके विपरित अगर हम चाहते तो अपनी 39 फैक्ट्रियों में ही लगातार अनुसंधानकर्ता और विशेषज्ञों का तरीके से उपयोग करते तो पिस्टल से प्लेन तक हम भी निर्यात कर सकते थे। देश की जरूरतें तो आसानी से पूरी होती ही। रक्षा अनुसंधानों के मामलों में एक मात्र संस्थान है, डीआरडीओ अर्थात रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन-जो जल, थल और वायु तीनों सेनाओं के लिए अनुसंधान और विकास करता है। बहुत सारे तथ्यों को प्रकाशित करना राष्ट्रहित में नहीं होगा। इससे शत्रु राष्ट्रों को विशेष तौर पर घुसपैठ बढ़ाएंगे और आक्रमण के मौके ढूंढकर युद्ध की तैयारी में आ जाएंगे। पर सच यह है कि पाकिस्तान और चीन अपने आंतरिक मोर्चों पर नियंत्रण पाने में असफल रहे हैं। दोनों ही राष्ट्रों में आंतरिक बगावत कई क्षेत्रों में चल रही है।

साप्ताहिक समय माया

आईटीआर से रु. 2000 करोड़ से ज्यादा की हानि अधिकांश फर्जी

स्वकर निर्धारण क्यों? जब जनता से पूरा वसूला

अय्याशायुक्त ने खूब चेलियों को अपने आजू-बाजू सजाया

म.प्र. वाणिज्य कर विभाग में जो कि पिछले 50 से ज्यादा वर्षों से व्यापारियों उद्योगपतियों से विक्रय कर बनाम वाणिज्यिक कर वसूल रहा है। पाठकों को जानकर आश्चर्य होगा कि कौन सा अधिकारी कर्मचारी क्या करेगा, किसकी क्या जिम्मेदारियां है और कर्तव्य होंगे। स्पष्ट कोई कार्यपद्धति का विभागीय मैन्युल ही नहीं है। बस जिस आयुक्त से लेकर नीचे के अधिकारियों कर्मचारियों तक जो जैसा कह देता है करना पड़ता है। यहां तक कि कई बड़े-बड़े नीतिगत फैसलों में गजर नोटीफिकेशन हुए बिना भी कार्य और नीतियां तैयार कर दी जाती है।

भूतपूर्व वाणिज्यिक कर आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने बेशक विभागीय भ्रष्टाचार को जो निचले स्तर पर होता था समाप्त करने के लिए कई ठोस कदम उठाकर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया तो दूसरी तरफ भाजपा जिसे व्यापारियों की राजनीतिक पार्टी के रूप में देखा जाता है। हर वर्ष बजट सत्र में करारोपण नीतियां, दरों की घोषणा की जाकर आय व्यय के अनुमान लगाए जाते हैं कि भविष्य में किस वस्तु पर कितना वाणिज्यिक कर वसूला जाना है, स्वभाविक है एकल साझेदारी कम्पनी संयुक्त उपक्रम, बड़ी व्यापारिक कम्पनी ग्राहकों पर उसी दिन से वह बढ़ा हुआ कर का बोझ लादकर वसूली कर देती हैं। इसके विपरीत यदि कर कम किया जाता है तो फिर कम की हुई दरों को 1 अप्रैल से ही घटाया जाता है। अर्थात जनता और ग्राहकों से तो सभी व्यवसायी, विक्रेता पूरा वाणिज्यिक कर वसूल लेते हैं। पर विभागीय नीतियों में सभी प्रकार के व्यापारियों को स्वकर निर्धारण की छूट दी गई है। रुपए 40 लाख तक की बिक्री पर कोई कर नहीं लगता व्यापारी को जबकि वह जानबूझकर 40 करोड़ की बिक्री को भी रुपए 40 लाख ही खाते में दिखाकर कर जमा नहीं करता। जबकि जनता से अवश्य वसूल कर वह पूरा कर ही हजम कर जाता है। ये बेईमानी, एकल, साझेदारी, निजी कम्पनी से लेकर सार्वजनिक, शेयर होल्डिंग वाली, कम्पनी भी न केवल खुलकर करती है। वरन् उनके चार्टर्ड बनाम करार एकाउंटेंट भी करने की ही फीस कई गुना वसूल करते हैं। जबकि सीए की रिपोर्ट वाणिज्यिक कर अंतिम निर्णायक प्रमाणित दस्तावेज मान लेता है। इसके विपरीत बड़ी कम्पनी व्यापारियों पर आयकर छापामारी कार्रवाई करता है। तो सबसे पहले आयकर रिटर्न भरने वाले सीए की भी बारीकी से जांच कर उसे भी व्यापारी और कम्पनी के साथ आरोपी बनाती है। दूसरी ओर सरकार भी मानती है कि कुछ करारोपण का वह 40 प्रतिशत ही कर वसूली पाती है और जबसे स्वकर निर्धारण की प्रक्रिया अपनाई गई है यथार्थ शासकीय संयुक्त उपक्रम कम्पनी के वाणिज्यिककर की आगम आय को छोड़ दें तो वास्तविकता में केवल यर्थात वाणिज्यिककर का मात्र 10 से 15 प्रतिशत वाणिज्यिकर ही प्राप्त हो रहा है। यदि जो व्यापारी स्वकर में रिटर्न जमा कर मुक्त हो गए हैं, उनके 3 वर्ष के ही पुराने खातों की जांच करवा दी जाए तो रुपए 20000 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी पकड़ी जाएगी।

अब महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि जब व्यापारी ग्राहकों से वाणिज्यिक कर सरकार के नाम

से वसूलता है। वह कर जमा न करने तक उसका दूष्टी होता है न कि मालिक तो फिर उस स्वकर निर्धारण की छूट क्यों? दूसरा रुपए 40 लाख जो हाल ही में रुपए 60 लाख किया गया है। बिक्री पर कोई वाणिज्यिक कर नहीं, आखिर क्यों जबकि उसने ग्राहकों को वह छूट न देकर उसने कर के नाम से वसूली की है। तीसरा आखिर यह कौन और कैसे देखेगा कि उसकी बिक्री मात्र 40-60 लाख तक बिक्री दो नम्बर में कर चुका होता है। परन्तु बिना खाते जांचे व्यापारी की इस बिक्री का कहीं कोई और क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता। यह बात सरकार अच्छी तरह से जानती है, फिर भी 30 से 33 प्रतिशत तक स्वकर निर्धारण करने का दबाव अधिकारियों पर डाला जाता है। मात्र इसलिए कि अधिकारी कर्मचारी व्यापारी से वसूली न कर ले। भले ही इस के चक्कर में सरकार हजारों करोड़ रुपए के कर प्राप्तियों से न केवल हाथ धोले वरन् व्यापारियों को जान बूझकर स्वय सरकार ही बेईमानी बना रही है। क्योंकि व्यापारी पर अंकुश समाप्त होने, उसके खातों की जांच न होने से वह अब जनता से करोड़ों रुपए टैक्स वसूल कर हजम कर जाने की खुली पात्रता रखता है। फिर करोड़ों रुपए की कर चोरी के बाद भी कोई भी वाणिज्यिकर अधिकारी सबकुछ जानबूझकर मीन तो उस वाणिज्यिकर परिसर में प्रवेश कर सकता है। न ही उसके खाते देख सकता है।

अकेले इंदौर में ही एंटी इवेजन के अ और ब दो कार्यालय हैं। जिनमें उपायुक्त से लेकर बाबुओं और चपरासी तक 20-25 का स्टाफ है। इसका कार्य कर चोरी को रोकना है। जो ऊंट के मुंह में जीरा है। जिन्हें भी ट्रांसपोर्ट से महीना मिल जाता है जो कि करोड़ों रुपए होता है। तो प्रोमी औपचारिकताएं निभाते हुए 5 से 10 ट्रक, बसे आदि पकड़कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। कुल 50 कर्मचारियों अधिकारियों का स्टाफ की औकात नहीं कि वह पूरे शहर में रुपए 10000 करोड़ से ज्यादा की कर चोरी रोक ले। दूसरी ओर जब से वेट लागू हुआ है, आंतरिक कर वापसी या जिसे आईटी आर कहा जाता है, व्यापारी, उसके कर सलाहकार से मिल कर कम से कम वर्ष भर में उन्हें ही रुपए 20000 करोड़ से ज्यादा का कर वापस वाणिज्यिक कर विभाग से ही वसूल कर रहे हैं। यह रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा का भी हो सकता है।

एक पार्टी के संबंध में जिसने करोड़ों रुपए का भाईटीआर का वाणिज्यिकर विभाग ने ही रिफंड मांगा है। उपायुक्त संभागीय कार्यालय क्र. 3 ने निम्नानुसार जवाब देकर अपनी भ्रष्ट कार्यशैली का खुला परिचय दिया है।

जब इसके संबंध में अपील की गई तो अपर आयुक्त इंदौर क्षेत्र ने उस अपील का जवाब देना भी उचित नहीं समझा है। सेकंड अपर आयुक्त के भी पुराने एमपीटीसी के लाखों के घोटाले को होने के बाद भी लगातार पदोन्नतियां दी गई है।

आईटीआर में झूठे बिल कटाकर और खरीदी दिखाकर भी सौ करोड़ व्यावसायी विभाग को हजारों करोड़ों का चूना लगा रहे हैं। इस पर भी विभाग की सूक्ष क्रॉस चेक प्रणाली न होने से भी इसमें भी भारी भ्रष्टाचार की संभावना है। अकेले धार रोड की लम्बाई में एक फर्म ने ही आईटीआर के फर्जीवाड़े से न केवल स्वयं का टैक्स नहीं दिया वरन् करोड़ों की आईटीआई भी मांग रहा है, जिसमें सुनील मिश्रा अधिकारी ने लाखों के वारे-न्यारे किया इसी तथ्य को उपायुक्त जानकारी देने की उपेक्षा जबकि वह जन धन के घोटाले का प्रश्न है, जिसकी अपील अपर आयुक्त ने भी 1 माह से ज्यादा समय से इसलिए लंबित रखी है ताकि घोटाले की पर्ते समय माया के माध्यम से सामने न आ जाए। एक तरफ पूर्व आयुक्त शैलेन्द्र सिंह ने भ्रष्टाचार को रोकने की कोशिश की जो सफल हो रही पर इसके विपरीत व्यापारियों को करचोरी की शासकीय स्तर पर पूरी व्यवस्था कर दी गई। फिर शैलेन्द्र सिंह भले ही अपने आप को ईमानदार होने का ढोंग करते रहे हो, परन्तु दूसरी तरफ बिंदास महिला अधिकारियों को एक-एक करके पहले इंदौर लाए फिर उन्हें दूसरे पात्र अधिकारियों की सुविधाएं न देकर उन महिला अधिकारियों को केबिन के साथ गाड़ियां भी दी गई। भले ही उन्होंने वहां कोई कार्य पद दायित्व का न भी सम्पन्न किया हो आखिर आयुक्त थे तो विभागी पंचोलियों को अपने दरबार में सजाने की पात्रता तो रखते ही थे। इसी कड़ी का एक हिस्सा है। सहा आयुक्त मधुमिता सिंह जिसके जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र फर्जी सिद्ध हो चुके हैं। फिर भी वह सारी सुख सुविधाएं भोगते हुए सेवा में हैं, उसे न निलंबित किया गया है न ही सेवा से मुक्त।

यहां पर चेलियों का सुख प्राप्त करने और पदोन्नति देने के चक्कर में पुराने अनुभवी वरिष्ठों की वरिष्ठता को भी खुलकर नजर अंदाज किया गया। इसलिए वरिष्ठ दो वर्षों से बैठे पदोन्नतियों का इंतजार कर रहे थे। कुठित है क्योंकि सन् 2000 के बाद आए अधिकारियों को पदोन्नतियां मिल गई और पूर्व के वरिष्ठ इनकी तुलना में पदोन्नत नहीं हुए। अब जबकि नए आयुक्त अमित राठौर ने पद संभाल लिया है। सत्ता का सारा केन्द्रीय करण भोपाल में वित्तमंत्री राघवजी के पास यहां से संचालित हो रहा है। स्थानांतरण की वसूली की उक्त में चूंकि सत्ता का मात्र एक वर्ष और बचा है। इसलिए माल लाओ मन चाही पोस्टिंग पाओ का खेल फिर शुरू हो गया है, जो 30 जून चलेगा।

जीएसटी 2013 से, राज्यों को कंगाल करने की साजिश

केन्द्र की सत्ता में बैठे धूर्तों की गिद्ध फौज को कमीशन और कमाई दिखो तो वो राष्ट्र की संसद को भी गिरवे करने से भी न चूकें। वैसे कमीशन खोरी के हर दिन नए कांड खुलते रहते हैं। इसके विपरीत के हर दिन नए कांडों को फिर भी अंजाम देते रहते हैं। उनकी बला से पूरा देश कहीं से भी कैसे भी बर्बाद हो। उसी की कड़ी का महत्वपूर्ण हिस्सा है राष्ट्र की निश्चित अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ धकेलना ताकि पूंजीपतियों से सीधा मोटा कमीशन उकारा जा सके। सरकार या सरकारें चले न चलें, इसी कड़ी का एक श्रृंखला है, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स जो बड़े पूंजीपतियों, उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कम्पनी के हितार्थ बनाई गई है। जिसे पिछले कई वर्षों से राज्यों के वित्त मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने रोक रखा था। 2013 से सैद्धांतिक रूप से लागू करने पर सहमत हो गए हैं।

ये राज्यों को उनके अपने वित्तीय साधनों को धीरे-धीरे कमजोर करने और उन्हें कंगाल बनाकर राज्यों की आर्थिक व्यवस्थाओं यहां तक कि शासकीय कर्मचारियों अधिकारियों के वेतन बांटने के लिए भी केन्द्र की तरफ मुंह उठाकर मांगने के लिए मजबूर कर देंगे। कुल करों की वसूली का दिल्ली के वित्तमंत्री को खिलाकर खुलकर जनता को नोंचते हुए राज्यों का वित्त व्यवस्था को बर्बाद करेंगी।

अब जबकि पूरे राष्ट्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लाभ और एकाधिकार की दृष्टि से खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 लगा दिया गया है। तो स्वभाविक है, साल दो साल में मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी प्रदेश कोटे खाद्य उत्पादक और विक्रेता समाप्त हो जाएंगे तो सारा खाद्य व्यवसाय इन बहुराष्ट्रीय कम्पनी के हाथ में केन्द्रित हो जाएगा। फुटकर बिक्री में भी केन्द्र और इस राष्ट्र का भ्रष्ट मीडिया जो 51 प्रतिशत की वकालात कर रहा है, वह भविष्य में कितनी घातक होगी। यह ज्यादा नही 20 से 16 तक सबके सामने आ जाएगा। अब चूंकि जीएसटी लागू करने में जिस केन्द्र में प्रलोभन में आकर ये लागू करने के लिए तैयार हुए हैं। राष्ट्र के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री और वित्तमंत्री यह प्रलोभन अधिकतम 3 से 5 वर्ष ही कार्य करेगा। उसके बाद पूरी जालसाजियां पूर्ण नीतियां दिल्ली से लागू की जाएंगी, जिसका भारी भुगतान राज्यों को करना ही पड़ेगा।

सबसे बड़ा रोना इस देश की धरती के सत्ताधीशों का ये है कि यहां के न केवल सत्ताधीश और जनता की घोर स्वार्थी मानसिकता की है वे तत्काल के लोगों को प्राप्त करने के लिए सदा ही भविष्य की बलि चढ़ाकर मूंछों को ताव देते हैं।

जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनी के लिए ये जीएसटी लागू किया गया है। वो दूर की कोड़ी खेल चुकी हैं। कुछ वर्षों तक तो सबको मुंह मांगी कमीशन और रिश्वत खिलाएंगे, जब सारे नियम-कानून उनके पक्ष में बन जाएंगे तो पहले राज्यों की सरकारों और फिर केन्द्रीय सरकार को अपनी तरह से नचाएंगे। जैसा कि इन जालसाज बहुराष्ट्रीय कम्पनी वालों ने विदेशों और पूरे यूरोप में किया। वहां जब इनके विरुद्ध माहौल बना तो वहां से भागकर भारत में पैरजमा रहे हैं। इन्हें जनता के शोषण से ही अधिकतम लाभ भी। दूसरी ओर जीएसटी भले ही राज्य सरकार विक्रय कर विभाग के जो म.प्र. में वाणिज्यिक कर के नाम से जाना जाता है। वसूल करेंगे। परन्तु उसके सारे नियम कानून वस्तुओं और सेवाओं पर दरें आदि सबका निर्धारण केन्द्र सरकार ही करेंगी। अर्थात राज्य सरकारों का इस जीएसटी पर से सारा नियंत्रण और क्षेत्रीय व प्रादेशिक आधार पर कर की दरों का निर्धारण किस वस्तु और सेवा पर कितना किया जाए यह सारा कार्य केन्द्र का अप्रत्यक्ष कर निर्धारण मंडल अपने कमीशन और वसूली के आधार पर करेगा। अब यदि बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने जिसमें रिलायंस, टाटा, निरक आटीसी, पेप्सी, हिन्दुस्तान लीवर जिनकी मासिक बिक्री रुपए 5 लाख करोड़ है वो रुपए 5000 करोड़ प्रति माह बांटकर रु. 50,000 करोड़ कर बचाएंगी और किसी भी तरह, किसी तथ्य का सहारा लेकर वहीं से अपने पक्ष में नीति निर्धारित करवा लेंगी, जिसका असर पूरे देश पर पड़ेगा। स्वाभाविक है राज्य सरकारों को भी इस कर से वंचित होना पड़ेगा या कर आय का राजस्व काफी कम हो जाएगा।

वर्ष दो वर्ष सब कुछ सामान्य सब कुछ सामान्य चलेगा। उसके उपरांत जब राज्यों का नियंत्रण जीएसटी से समाप्त होकर केन्द्र के पास केन्द्रीत होगा तो अधिकांश पूंजीपति, उद्योगपति, उत्पादन कर्ता बहुराष्ट्रीय कम्पनी व अन्य सभी जालसाज दिल्ली में बैठकर ही सुरा-सुंदरी और रिश्वत देकर सारी नीतियां कर की दरें, रिवेट, रिफंड, भुगतान, वसूली सब दिल्ली से ही करवा लेंगी, जिससे उन्हें प्रदेशों के वित्तमंत्री, मुख्यमंत्री को बिना मोटी भेंट दिए नीतियां अपने पक्ष में करवाने की जरूरत ही नहीं पढ़ेगी। केन्द्र सरकार दरें जो निर्धारित करेगी, जनता से तो उसकी वसूली पूरी होगी।

म.प्र. रोड डकैत कार्पोरेशन व राष्ट्रीय राजमार्ग लूट प्राधिकरण

राजमार्गों पर सरकारी डकैती फिर भी मौत का तांडव

सड़कों पर लूट में ठेकेदारों के साथ केन्द्र व राज्य तंत्र की भागीदारी हर प्रकार की क्षति के लिए परिवाद लगाओ

भारत में चारों तरफ केन्द्र और राज्यकी सरकारों द्वारा वाहन धारकों से हर कदम-कदम वसूली की जाकर जनता की जेब भर डकैती डाली या सरकारी ठेकेदारों से डलवाई जा रही है।

जब पेट्रोल पर ही 32 प्रतिशत कस्टम एक्साइज 2 प्रतिशत शिक्षा कर, 2 प्रतिशत सड़क उपकर, 2 प्रतिशत अन्य उपकर केन्द्र सरकार द्वारा वसूला जा रहा है। वहीं राज्यों द्वारा वेट 27 प्रतिशत से 35 प्रतिशत वसूला जा रहा है। इसके बाद भी न केवल राज्यों के राजमार्गों पर वरन् राष्ट्रीय राजमार्गों पर बिना बनाए ही सड़कों हर 30 से 40 किमी पर रुपए 2 प्रति किमी कारों पर से लेकर बसों ट्रकों से रुपए 3 से लेकर पहियों के हिसाब से रुपए 5 रुपए किमी तक वसूला जा रहा है। जबकि हर वाहन के पंजीयन के रूप में कुल बिक्री कीमत का जिससे राज्यों का वेट, केन्द्र का विक्रय कर, नगर पालिकाओं निगमों का पार्किंग टैक्स, कस्टम एक्साइज आदि मिलाकर कुल कीमत का 7 प्रतिशत रोड टैक्स वसूली जाता है अर्थात जनता से टैक्स देने पर भी उसे शामिल कर टैक्स देना पड़ता है। इसके उपरांत भी गाड़ी चलाने पर फिर टोल टैक्स देना पड़ता है। सबसे पहले गाड़ी के पंजीयन पर टैक्स वसूला जाने वाला रोड टैक्स तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए वो राज्यों के हों या केन्द्रीय राजमार्ग हो, देना ही पड़ रहे हैं।

केन्द्रीय भूतल परिवहन मंत्रालय के नियमानुसार किसी भी 4 लेन मार्ग पर और नगर निगम की सीमा में किसी प्रकार का टोल टैक्स नहीं लगाया जा सकता। इसके विपरित इंदौर के ही एमआर 10 पर रेलवे क्रासिंग पर खुले आम न केवल बाहरी वाहनों से वरन् इंदौर के एमपी 09 से पंजीकृत वाहनों पर भी टोल वसूला जा रहा है। उस टोल नाके को समाप्त किए वर्षों बीत जाने के बाद भी नगर निगम इंदौर के माफिया नेताओं इंदौर जिलाधीश राघवेन्द्र सिंह की आंखों के सामने वर्षों से यह कारनामा चल रहा, जिसे उद्योगमंत्री की साझेदारी और ठेकेदार पुनीत अग्रवाल की दोस्ती के चलते अवैध कार्य किया जा कर लाखों रुपए की वसूली चल रही है। पर भ्रष्ट भाजपाई मुख्यमंत्री सब जानकर भी चुप है। रुपए 4 करोड़ के पुल का 14 करोड़ का इस्टीमेंट बनवाया गया। वह भी 5 वर्ष में दोगुने से ज्यादा वसूलने के बाद भी चल रहा है। क्यों चुप है कांग्रेस इस पर। वैसे बात-बात पर आंदोलन करते हैं। पर जब सारे भ्रष्ट एकजुट हो वसूली में जुटे हैं तो कोई कैसे बोले।

म.प्र. सड़क डकैती निगम के अन्तर्गत प्रदेश के अधिकांश वीओटी सड़कें एक लेन, दो लेन हैं, जो सारे न केवल अवैध है। वरन् जानबूझकर जनता को लूटने के लिए अधिकांश ठेकेदारों को जिनसे न केवल मोटा कमीशन डकार कर सड़कों पर शासन की तरफ से भी धन देकर साथ ही मोटरेबल सड़के देकर ठेकेदारों की वधक कर जनता को लूटने के लिए छोड़ दिया। जबकि ठेकेदारों ने सड़कों पर थोड़ी सी लीपा-पोती कर दोनों हाथों से लूटना शुरू करने के 10 वर्ष वर्ष बाद भी वास्तविकता में न तो अच्छी सड़कें दी हैं और न ही सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था। विवा हाइवेज ने शासन से 2002 में मोटरेवल सड़कें लेकर वसूली तो शुरू कर दी, परन्तु 24 किमी से 36 किमी अधिकतर घाट के भाग में कई वर्ष बाद भी हरामखोर शूकरों की फौज ने पुल-पुलियों के साथ ही सड़क से लगे ढालों पर अभी तक न तो बेरिकेट्स ढंग से लगाए न ही सड़कों पर संकेतक लगाए गए, जबकि पुलियों और ढाल नाचे 2-3 मी. से 25 मी. तक गहरे हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। यहां तक कि सड़कों के दोनों ओर 5-5 फुट की कच्ची पट्टियां भी नहीं भरी गई। यह 2 लेन मार्ग पर वसूली 4 लेन की जा रही है। जबकि इस मार्ग पर भी यातायात का दबाव ज्यादा होने से तत्काल इस 4 लेन किया जाना चाहिए। इस मार्ग पर ठेकेदार अशोका बिल्डकॉन को रुपए 124 करोड़ का प्राक्कलन में शासन ने रुपए 45 करोड़ दिए थे। इन जालसाजों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्गी दानव और लोनिवि मंत्री को मोटा पैसा खिलाकर जो अनुबंध किए। उसने मात्र शासन से मिले रुपए 45 करोड़ में से भी रुपए 25 करोड़ बचाकर रुपए 10 लाख प्रति किमी खर्च कर ही वसूली शुरू कर दी थी, वर्तमान में पूर्ण किए डकैत कार्य के 20 परियोजना में से मात्र 4-5 सड़के हीं 4 लेन हैं। वे भी कोई भारतीय सड़क मानकों के हिसाब से नहीं बनाई गई। जिन पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। कई सड़कें तो दिलीप बिल्डकॉन जो मुख्यमंत्री शिवराजसिंह के निकट रिश्तेदार की है। जो शासन की देखरेख में शासन के खर्च से पूरी कर सौंप दी गई, जिससे शिवराज का भी दो नं. का काला धन लगाया गया। अब दिलीप बिल्डकॉन उस पर अगले 15 से 30 वर्ष तक वसूली करेगा। इसलिए इन हरामखोर रोड डकैत कार्य के प्र.सं. विवेक अग्रवाल ने सड़कों के ठेकेदारों के नाम हटा दिए ताकि अपना आका बचा रहे। नाम जगजाहिर न हो। वैसे दो नं. के काले धन वालों के लिए वीओटी एक अच्छा व धन को सफेद करने का परिवर्तन माध्यम बन चुका है। पूरे म.प्र. में उन सड़कों पर अभी वीओटी वसूली जा रहा है, जिसमें पहले 20 में 2312 किमी में से मात्र 500 किमी सड़के हैं 4 लेन है। जिनके दो गुना प्राक्कलन बनाकर डकैत कार्यों के तहत प्र.सं. सुलेमान ने कम के कम रुपए 1 अरब डकारा आंख मीचकर मन चाहे अनुबंध किए गए। 20 सड़कों के 2312 किमी पर रोड डकैत कार्य का एमडी प्रति माह रुपए 1 लाख प्रति कि.मी.औसतन भी ठेकेदारों से वसूल रहा है तो रुपए 35 करोड़ प्रति माह की तो चौखी व्यवस्था इस इंडियन एक्यूसिंग सर्विस अधिकारी की तो हो ही रही थी स्वाभाविक है। ठेकेदारों को वसूली की पूरी छूट है। चाहे सड़कों पर वाहन चालकों की मौत का अंबार लग जाए सड़के कैसी भी हैं, गड्ढो हो, बेरिकेट्स हो न हो। यहां तक की ठेकेदारों की हरामखोरी का नया नमूना है कि वे शुकर मार्ग संकेतक 10 वर्ष बाद भी नहीं लगा पाए, फिर सड़क डकैत कम्पनी के प्रबंध संचालक आए ही डकैती वसूली करने, न तो कोई इंजीनियर है न ही तकनीशियन इन्हें मतलब नहीं सड़कों से या उन पर होने वाली मौतो से।

दूसरी ओर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के दिल्ली स्थित प्रमुख कार्यालय से लेकर नीचे तक क्षेत्रीय परियोजना ईकाइयों तक, सारे हरामखोरों की फौज है। यहां के अधिकांश इंजीनियर अनुभवहीन होने के साथ ही ठेकेदारों की कठपुतली बन नाचने के आदि है। यहां तक कि इंदौर का कार्यालय भी ठेकेदार ने अपने पड़ोस में ही शिफ्ट करवा लिया है उनके पूरे देश में 232 परियोजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। सब ही परियोजनायें तयशुदा समय सीमा से दुगुनी समय सीमा पूरी करने के बाद भी अधूरी है। म.प्र. में रा.रा.मार्ग क्र. 3 आगरा-बंबई जो मुरैना से ग्वालियर-शिवपुरी-गुना-देवास - इंदौर- सेंधवा तक म.प्र. में से जाता है। इंदौर-सेंधवा ही कार्य पूरा करके टोल वसूली शुरू कर चुका है। इंदौर देवास 55 कि.मी. मार्ग जिसका ठेकेदार दक्षिण

भारत का खनन माफिया जगन की कंपनी गायत्री है। जिसने रा.रा. लूट प्राधिकरण के साथ मोटा धन खिलाकर कार्य शुरू करने के साथ ही वसूली शुरू कर दी थी घोंघे की गति से काम कर रहा है। इस मार्ग को बनने में 2013 पूरा लग ही जायेगा। यहां भी हर दिन होने वालीऔसतन 10-20 दुर्घटनाओं में लोगों की जानें जा रही हैं। पूरे म.प्र. में चाहे वो इंदौर-अहमदाबाद रा.रा.मार्ग क्र. 59 हो या इंदौर बैतूल रा.रा.मा.क्र. 59 अ हो, इंदौर से झाबुआ तक ही 31 मार्च 2010 तक 300 से ज्यादा मौतें हो चुकी थी, यहां पर कार्यरत ठेकेदार आईएसव्हीएल के साथ यहां का क्षेत्रीय कार्यालय प्रबंधक शैलेन्द्र सिंग की अच्छी दोस्ती है। 31 मार्च गुजर जाने के बाद भी शंख के कीड़े की भांति रेंग-रेंग कर कार्य चल रहा है। म.प्र. में इस लूट प्राधिकरण के कार्यों की मंथर गति के पीछे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़े गांवों, नगरों और उपयोगकर्ता जनता को पीड़ित कर म.प्र. शासन में बैठे भाजपा को बदनाम और निकम्मा साबित करना ही है।

विश्व बैंक के इशारों पर नाचकर भारत शासन में बैठी डकैत कांग्रेस और उसका संप्रग गिरोह सत्ता में बैठे सांसदों और उनके रिश्तेदार पूंजीपतियों, राज्यों में विधायकों, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों उनके रिश्तेदारों या अन्य मोटे पूंजीपतियों के हाथ में ये खरबों रु. की सड़कों की संपत्ति गिरवी कर जनता को लूटने का माध्यम बनती जा रही है। राज्यों की संपत्ति जो जन-धन से निर्मित की गई थी अब जन को लूटने और पूंजीपतियों को अरबपति से खरबपति बनाने का साधन राष्ट्र को पूंजीवाद की तरफ धकेल घोर शोषण का माध्यम बन रही है। जिस पूंजीवाद के रास्ते पर चलकर पूरा अमेरिका और यूरोप के आने को देशों की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। हमारे गिद्ध नोच की सोच वाले कर्णधार, सत्ताधीश पूरे देश की व्यवस्थाओं को उसी पूंजीवाद की ओर धीरे-धीरे धकेल रहे हैं। वाहन चालक जो टोल सड़कों का उपयोग करते हैं, टोल भुगतान करते हैं। यदि सड़कों पर पहिया भी पंचर होता है से लेकर हर प्रकार की टूट-फूट, दुर्घटनाओं के लिए राज्यों के राजमार्गों पर उस टोल ठेकेदार जिसका वाहन चालक उपयोग टोल देकर कर रहा है, किसी भी नुकसान जिसमें सड़क पर गड्ढों, बनावट, संकेतक के न होने, साइड देने पर दायें बाये वाहन पलटने से यदि दुर्घटना घटती है, तो न केवल ठेकेदार फर्म, मुख्य सचिव और मुख्य मंत्री को पक्षकार बनाकर व राष्ट्रीय राजमार्ग के मामले में संबंधित ठेकेदार, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पक्षकार बनाकर न्यायालय में परिवाद लगाया जा सकता है।

वाहन के पंजीयन के समय वाहन मालिक ने 7% टैक्स दिया होता है। इसलिए परिवहन मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग जो सड़कों के विकास के लिये जिम्मेदार हैं या सड़क विकास निगम या टोल वसूली ठेकेदार जो जिम्मेदार है, क्षतिपूर्ति के लिये दावा लगाने के लिये पात्र है। जब तक वाहन चालक या मालिक इन जालसाजों, सरकार, सरकार के जिम्मेदार विभागों, परिवहन विभाग, टोल वसूली, ठेकेदारों पर परिवाद दायर नहीं करेंगे ये लूट बंद होना संभव नहीं। फिर यदि सरकार रोड टैक्स ले रही है। टोल ठेकेदार सड़कों पर वसूली कर रहा है, तो सुरक्षित अच्छी सड़कें देने के लिये या केवल लूट के लिए। सड़कों पर सर्वोच्च न्यायालय ने यहां तक कि स्पीड ब्रेकर लगाने को भी प्रतिबंधित कर दिया है। जिन सड़कों पर स्पीड ब्रेकर लगाने से वाहन चालकों को क्षति और परेशानी होती है। जो अ सड़कों के रखरखाव के लिये जिम्मेदार है चाहे वो नगर निगम-पालिकायें हो, टोल ठेकेदार हो, लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़कें बनाई गई हो वाहन मालिक और चालक दोनों ही न्यायालय में संबंधित के विरुद्ध परिवार दायर कर सकने और क्षतिपूर्ति, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का परिवाद लगाकर सभी प्रकार की क्षति के लिये दावा ठोंक सकते हैं। इसमें बीमा कं. पर क्षति के लिये अलग से परिवाद लगाकर क्षतिपूर्ति की मांग अलग से की जा सकती है। आखिर शासन किस बात का 7% रोड टैक्स, 27% वेट टैक्स केंद्रीय शासन 38% जिसमें 2% सड़क उपकर शामिल, कस्टम व एक्साइज वसूल रहा है।

पुनः न चुने अमेरिकी ओबामा को राष्ट्रपति

पेज 1 का शेष

जिसकी पैरवी स्वयं राष्ट्रपति ओबामा उनकी विदेश मंत्री गौरांग चेली पूर्व राष्ट्रपति बिल की बीवी हिलेरी क्लिंटन भी कर रही हैं। जबकि इन बहुराष्ट्रीय कम्पनी को पहले अमेरिकी जनता को रोजगार देकर पहले अपने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए ओबामा का दबाव बनाना चाहिए था न कि पूंजी समेट कर विदेश में व्यापार करने के लिए स्वयं पैरवी करने पहुंचने लगे, बेशक कमीशन देकर ही बहुराष्ट्रीय कम्पनी ये पैरवी कर रही है। उनके कमीशन का विदेश में कहीं भी बैंक खाता खोलकर जमा करवा दिया गया होगा। करवा दिया जाएगा।

समय माया की साइट से अमेरिकी राष्ट्रपतियों अमेरिकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए संदेश दिया गया था कि अपनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को निश्चित अर्थव्यवस्था में बदलकर इस संकट से सदा के लिए मुक्ति पाई जा सकती है, जिसमें सभी बड़े सेवा उत्पादन उद्योगों को राष्ट्रीयकृत कर छोटे व्यवसायियों को सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित किया जाए ताकि बेरोजगारी और घाटे की व्यवस्था कम किया जा सके। बेशक आंशिक रूप से यह न केवल मानी गई वरन् ओबामा ने छोटे व्यवसायियों को अपने उद्योग धंधे लगाने के लिए खुले मंच से अपने भाषणों में प्रोत्साहित कर भ्रष्हान भी किया। पर संकर प्रजाति के लोगों में ये क्षमताएं अन्य न केवल समाप्त वरन् मानसिकता से ही बाहर हो चुकी है, जिसे ओबामा पुनः तत्काल तो पैदा नहीं कर सकते। बेहतर यही होगा कि अमेरिकी जनता इसे वोट न दे और पुनः राष्ट्रपति न चुने।

साप्ताहिक समय माया

सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नतियों के निर्णय का पालन नहीं

संसद में पदोन्नतियों में प्राथमिकता का कानून बकवास

फिर केन्द्रीय नेताओं में क्यों नहीं लागू, तो राज्य क्यों दे रहे हैं प्राथमिकता शासकीय सेवाओं में पदोन्नतियों आरक्षण के आधार पर कनिष्ठों को वरिष्ठों और अनुभवि व वरिष्ठों को कनिष्ठों के अन्तर्गत कार्य करने की पद्धति से इन जालसाज वोटों और सत्ता के भूखे राजनीतिज्ञों को जिन्हें मात्र पांच वर्ष के लिए केन्द्र और राज्यों में सत्ता सौंपी जाती है, को जनता और राष्ट्र के भविष्य से बिल्कुल भी मतलब नहीं होता, कैसे राष्ट्र की बर्बादी हो रही है। यह जानने के लिए शासकीय विभागों के अन्दर झांक कर देखो तो मालूम पड़ता है कि किसी भी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी को काम से मतलब नहीं, जो भी किया जा रहा है, बस मजबूरी में। अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित कार्यों को ढो रहे हैं। चारों तरफ भारी आक्रोश है कि हम से 10-15 वर्ष कनिष्ठ अन्य हम पर रोब एंठकर कार्य ले रहा है। कार्य भी कार्य की पद्धति और नियमानुसार ईमानदारी से नहीं, अपनी मन मर्जी और भ्रष्टाचार पूर्ण तरीके से। ताकि फंसे तो कनिष्ठ और भ्रष्टाचार से माल कमाए खाए तो अधिकारी इस मानसिकता के चलते काम नहीं येन-केन प्रकरण व्यतीत कर वेतन ले रहे हैं। पिछले अंक में सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय प्रकाशित किया था, उसका उद्देश्य भी यही था कि जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरे देश पर लागू है तो म.प्र. की सरकार जानबूझकर क्यों अनदेखा कर लगभग 3 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां देकर सम्मान जनक तरीके से वेतन के बदले कार्य को सम्पन्न करवाए।

उ.प्र. में सपा के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आते ही अपनी ठोस राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को शिरोधार्यकर पदोन्नति में आरक्षण के मायावती के निर्णय को रद्द कर, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नतियां देने की प्रेरणा कर सामान्य वर्ग के लिए उपेक्षित कर्मचारियों और अधिकारियों की पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त किया।

केवल इसके विरुद्ध कांग्रेस और बसपा ने भले ही लोक सभा में संशोधन लाने की पहल की हो जो कि कोरी बकवास ही सिद्ध होगी। क्योंकि केन्द्र की सत्ताधारी कांग्रेस और उसके सहयोगी राजनैतिक गिरोह के लोगों में दम था, तो सन् 2004 से क्या कर रहे थे। दूसरी ओर पदोन्नतियों में आरक्षण केन्द्र शासन के सभी विभागों में क्यों इतने वर्षों से लागू नहीं किया। साथ ही अगर वे पद्धति लागू होती राष्ट्र को चलाने, हांकने और ढकेलने वाली जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केन्द्रीय मंत्रियों से लेकर मुख्यमंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों और सचिवालय तक को टोकती है। यदि केन्द्र में सत्ता में बैठकर लोकसभा में संशोधन करवाकर सभी केन्द्रीय सेवाओं जिसमें महत्वपूर्ण सेवाएं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस से लेकर कर्मचारी चयन आयोग में भी लागू कर दिया जाता था कर दिया जाए कौन सा पीड़ित आईएएस, आईपीएस, आईएफ (फोरन) सर्विस, कहां देश में विदेश में सरकार की धज्जियां बिखेरता या बिखेरेगा। सरकार में बैठे मंत्रियों, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के भी समझ नहीं आएगा।

बोये राजनीति के चलते सामान्य वर्ग से ही पूरे देश में सबसे ज्यादा टेक्स चाहे तो आयकर विक्रय कर कस्टम और एक्साइज सम्पत्ति कर आदि अधिकांश राष्ट्रीय राज्यों और क्षेत्रीय कर सरकार चलाने के लिए देते हैं। इसके विपरीत सबसे ज्यादा वेतन और शोषण हर क्षेत्र में चाहे वह शासकीय हो या निजी सामान्य वर्ग का ही होता है, तो मानलिए इस लिए कि सारे मेंढक ज्ञानी, प्यानी और महान होने का दंभ पाले रहते हैं। इसलिए इकट्ठा होने की उपेक्षा हर कोई अपनी दिशा में उछलते-कूदते रहते हैं। जिस दिन ये इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तथा फिर सरकारों को चाहे वो केन्द्र, क्यों की हो या क्षेत्रीय नगर निगम, पालिकाओं से लेकर पंचायतों का कांग्रेस गिरोह ने जब देश की सत्ता संभाली थी तो जाते हुए अंग्रेजों से पूझा कि आखिर इस देश पर 300 वर्ष कैसे शासन किया तो जवाब था कि फूट डालो और राज्य करो कांग्रेस के सफेद पोश जालसाज डकैत चाहे तो प्रधानमंत्री हो या कांग्रेस अध्यक्ष इटालियन सोनिया, गाते नगाते थे मुस्लिमों को ऊपर उठाकर या उनको सुविधाओं की घोषणा करके सामान्य हिन्दुओं को नीचा दिखाने से ये जालसाज शूटरों की फौज बाज नहीं आती आती, जबकि उनके भुगतान किए हुए करों पर ही यह मौज करती हैं। उ.प्र. में कांग्रेस अब इसलिए नहीं आती, क्योंकि ये वहां पर हिन्दू-मुस्लिमों को आपस में लड़वाने का ही कार्य करती रही है। जब तक वहां कांग्रेस रही मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, फैजाबाद, लखनऊ, गाहे वगाहे दंगों और कर्फ्यू की आग में जलते रहे। अब जब उसका यह तरूप का इक्का नाकामयाब रहा हो अब वह यह प्रयास कर रही है कि अगले-पिछड़े और हरिजन ही लड़ते रहे हो तो उनके खून से होली खेलते हुए राष्ट्र की सम्पत्तियों को नोंचकर विदेशों में जमाकर जीम रहे, इन्हें राष्ट्र की जनता और उसके उज्जवल भविष्य की चिंता कभी नहीं रही। इनका तो शगल रहा है, येन-केन प्रकरेण जनता को आपस में लड़वाओ। इसके लिए संविधान के संशोधन भी करना पड़े तो कर दो। विश्व के किसी भी संविधान में शताब्दियों में इतने संशोधन नहीं किए गए, जितने भारतीय संविधान में 62 वर्षों में कर दिए गए। तो मात्र वोटों की राजनीति के लिए इस प्रकार समानत का अधिकार समान अवसरों का अधिकार समान रूप से आगे बढ़ने, व्यवसाय करने के अधिकार की मूल आभाव ही अनेकों बार दुर्भावना पूर्ण तरीके से परिवर्तन और संशोधन किए गए, इसमें विपक्ष में बैठे धूर्तों और वोटो के भुखेरों ने भी बिना किसी परेशानी पूछताछ के उन संशोधनों को आंख मीच करक हां कर दी है।

भाजपा जिसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का राजनीतिक संगठन है, ने तो कभी वोटों की खातिर असमानता की बात नहीं उठाई, अब जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट फैंसला देकर सामान्य जाति के कर्मचारियों अधिकारियों को वर्षों से लंबित पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त कर दिया तो भी प्रदेश भाजपा का धूर्त मुख्यमंत्री शिवराज कोई कदम उठाने को तो दूर महीनों बाद भी कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि इन सत्ताधीश चुनावों को डर है कि कहीं ऐसा न हो कि अगले चुनाव में पिछड़े उन्हें वोट न दें तो सत्ता का निवाला छिन जाए, जबकि इसके विपरीत तो यह अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछड़ों के अधिकांश वोट न केवल कांग्रेस के खाते में जाने हैं और ये सत्ता में अगड़ो के वोटों के दम पर ही सत्ता में आते हैं। आते समय बड़े मासूम बनकर दिवास्थान दिखाते हैं।

आ जाने के बाद मुख में राम और बगल में अगड़ों पर छुरी चलाते हैं। उनसे ही सबसे ज्यादा टेक्स वसूल कर पिछड़ों पर लुटाने के नाम स्वयं लूट कर खा जाते हैं। उन्हें शासकीय सेवाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों को 25 से 35 साल तक एक ही पद पर सड़ाते हैं। उनसे कनिष्ठों को जो उनसे 10-15 वर्षों बाद सेवा में आए। उनके सिर पर बैठाते हैं। शासकीय सेवकों में कुंठा बढ़ाते हैं। फिर चिल्लाते हैं कि शासकीय सेवक काम नहीं करते। अपने वरिष्ठों से नहीं डरते, क्यों डरेंगे, क्यों काम करेंगे? क्या आपने उन्हें अनका समय पर हक दिया। अपनी अक्ल पर वोटों का पर्दा था, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन किया, नहीं किया।

दूसरी ओर सत्ताधीश गिद्धो तुम्हें वर्तमान से लूटने की पड़ी है। भविष्य की चिंता किसे पड़ी है। अनेकों विभागों में अरबों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है। अधिकांश काम कागजों पर आंकड़ों की हेरा-फेरी से ही सम्पन्न हो जाता है। वास्तविकता में कहीं कुछ नजर नहीं आता। जो जिम्मेदार हैं, उन्हें कुछ नहीं आता-जाता बस लूटो-खाओ और लुटाओ जब पकड़ा जाता है, तो पैसा खर्च करके न्यायालय से स्थलन ले आता है, जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी का प्रमुख अभियंता डामोर। दिवंगत प्रजापित पूर्व में प्रमुख अभियंता जब संसाधन था, दोनों जब तक रहे, लूट और बर्बादियों के आवाम स्थापित करते रहे। यह भी देखो कि भविष्य कहां जा रहा है। प्रदेश के 95 से ज्यादा शासकीय विभागों में वर्तमान आंतरिक स्थिति क्या है। भले ही विडियो कांफ्रेसिंग समीक्षा बैठक नियमित से हो रही हो। इस विडियो कांफ्रेंसिंग और समीक्षा बैठक केवल आंकड़ों का ही खेल चल रहा है। इससे मुख्यमंत्री शिवराज, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त, प्रमुख अभियंता, संचालक आदि सभी विमानों के भले ही खुश हो जाए परन्तु वास्तविकता में जहां 20-30 प्रतिशत कार्य भी नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? अनुभव हीतो मूढो को पदोन्नति दे-देकर ऊपर तो बैठा दिया अब कार्य करे तो कौन? दूसरी ओर झूठ आंकड़ों, व्हाफचरों बिलों से आपूर्तिकर्ता, ठेकेदारों के साथ मिलकर पैसा हजम करना ही जिनकी नियति बन गई हो, कोई भी जांच चली अंकेक्षण हुआ। पूछताछ चली तो बस जो लुटा है उसे कुछ को बांट दो। चारों तरफ घूसखोरों की फौज है। मंत्री से लेकर बाबूओं तक सब चुप।

इसदा दुखद पहलू यह भी है। सामान्य वर्ग तरीके कर्मचारी अधिकारी दुखद होकर न केवल क्षेत्रीय वरन् प्रदेश स्तर पर इकट्ठे होकर आगाज बुलंद करने में सक्षम नहीं है। इनकी यही घोर स्वार्थी मानसिकता, निकमेपन और अजगरों की भांति जहां है, वहीं रहने की बत्तमीजियां इनका और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बबार्द करने पर तुली है। जिसकी लाठी भैंस वही चराएगा। अनादिकाल से पृथ्वी पर जीवन रहने तक यही नियम चलेगा। आखिर क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते ये सामान्य वर्ग के कर्मचारी-अधिकारी शायद यही इनकी घोर स्वार्थी मानसिकता का कारण था। हमारी हजारों वर्षों की गुलामी और अब भी अपने ही वोट से चुनी सरकार की ज्यादितियां के विरुद्ध सिर न उठाने की नपुंसकता का लाभ ले रहे हैं। सभी सत्ताधीश हमारे हे धन की होली खेलकर, हमें जोत रहे हैं। फिर भी हम कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। मत बोलिए, पूर्वजों ने आक्रांताओं को ढोया है, वर्तमान में इन जालसाजों को वोट देकर सत्ता सौंपी अब उनको आप ढो रहे रहे हैं। अपनी पीढ़ी को भी यही संस्कार दे ताकि वो भविष्य में जालसाजों और नोंचकर खाने वाले सत्ताधीशों का ढो सके। यहां अपना कानूनी हक भी मांगने से नहीं मिलेगा। दंभी, स्वार्थी मानसिकता के सामान्य वर्ग वालों। क्या किया इतने वर्षों में।

आईटीसी सिगरेट कम्पनी के इशारे पर तंबाकू पाउच बंद

तंबाखू पाउच घातक, सिगरेट, धुआं सबको अतिघातक

म.प्र. में 31 मार्च 12 से तंबाखू युक्त गुटखे और पाउच बंद कर दिए गए। क्या वास्तविकता में सरकार को युवा पीढ़ी के स्वास्थ्य की चिंता थी। या सिगरेट कम्पनी के बाजार को बढ़ाने की जंग और मोटे कमीशन और करों से प्राप्ति का कारोबार में गुटखा कम्पनी को बिक्री बंद करवाई गई, यहां किसी भी सत्ताधीश को जनता के स्वास्थ्य की चिंता नहीं. अपनी कमाई तीमाई और बैंक बैलेंस की चिंता ज्यादा सताती है। इसलिए यहां पर सत्ताधीश जनता की पूंछ पकड़कर इस लोकतंत्र में लूट का खेल चलाया जाता है।

वर्तमान सत्ताधीश चुने भले ही जनता के द्वारा जाते हों, पर सत्ता में आते ही पूंजीपतियों की रखैल बनकर जनता की बर्बादी करने के लिए उल्टे-सीधे, कानून बनाने. जनता को भ्रमित कर न केवल उनका शोषण वरन् उनके भविष्य की बर्बादी करने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय बनाने, जानवर मान कर उन पर ड्रग ट्रायल करने, मौत का सामान इकट्ठा करने में इन हरामखोर सत्ताधीशों को बिल्कुल भी हिचक नहीं होती। इसका सीधा सा उदाहरण है, तंबाखु युक्त गुटखा पाउचों को युवा पीढ़ी की सेहत के आधार पर बंद करना, जिससे केवल खाने वाले व्यक्ति को स्वास्थ्य पर ही असर पढ़ता है।

इसके विपरित सिगरेट-बीड़ी पर प्रतिबंध न लगाया जाना। जबकि सिगरेट-बीड़ी या धूम्रपान करने वाला व्यक्ति सिगरेट-बीड़ी पीकर जो धुआं छोड़ता है, उससे उसके साथ रहने

युवा पीढ़ी पाउच बंद किए तो धोंकने लगे

वाले मित्रों सहेलियों के साथ ही परिवार के लोग भी आक्रांत होते हैं। क्योंकि अब सिगरेट पीने का चलन छात्राओं में भी तेजी से बढ़ रहा है। फिर वह धुआं वायु मंडल से भी फैल जाता है। अर्थात धूम्रपान तंबाखु चबाने वालों से ज्यादा घातक होता है।

आखिर सिगरेट-बीड़ी पर क्यों प्रतिबंध नहीं लगाया गया, क्योंकि सिगरेट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इंडियन रोनेक कम्पनी जिसके 51 प्रतिशत शेयर्स ब्रिटिश रोनेको कम्पनी के पास है। आईटीसी वहीं आईटीसी जिसने पूरे राष्ट्र के अधिकांश शहरों के बाहर अपने आईटीसी चौपाल के बाड़े कृषि उत्पादों को खरीदी करने के केन्द्र खोल रखे हैं। यह चौपाल खो हमे किसानों ,की 5 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन पर अपनी तरह से पैदावर करने और अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कम्पनी की तरह राष्ट्र को पुनः गुलाम बनाने के लिए ये बड़े सत्ताधीशों को खरीदकर जेब में डालकर चलते हैं, इन्हीं हरामखोरों और अंबानी बंधुओं की जालसाजी षड्यंत्रों के चलते ही पूरे राष्ट्र में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 बनाया गया व लगाया गया ताकि सारे राष्ट्र का खाद्य व्यवसाय इन बहुराष्ट्रीय कम्पनी के कंधों में चला जाए और छोटे-छोटे मझोले सारे विक्रेता उत्पादक, जिसमें खाद्य पदार्थों से लेकर पाउच तक सभी कुछ हैं। जो इस आईटीसी, पारले, रिलायंस, मेक्डावेल जैसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को अपनी मनमानी कीमतों पर माल नहीं बेचने देते उनसे प्रति स्पर्धा को मजबूर करते हैं। सदा के लिए समाप्त हो जाए ताकि फिर से ये न केवल जनता वरन् सरकारों को भी अपनी तरह हांके और लूटे, पाठक समझ चुके होंगे कि आखिर पूरे राष्ट्र में रुपए 2000 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय करने वाली आईटीसी जिसका इस राष्ट्र के 80 प्रतिशत सिगरेट बाजार पर कब्जा है कैसे सिरगेटों का उत्पादन और बिक्री बंद कर केवल तंबाखु युक्त पाउचों के निर्माण और बिक्री पर म.प्र. सरकार ने 31 मार्च 12 से प्रतिबंध लगाया, ये वहीं भाजपा सरकार है जिसने 2004 में सत्ता में आते ही आईटीसी को प्रदेश की मंडी व्यवस्था को धता बताते हुए किसानों से मंडी के बाहर हर शहर के बाहर खुले आईटीसी चौपालों की कृषि उपज खरीदने की छूट दे दी तो फिर आईटीसी सिगरेट कैसे बंद की जा सकती है। बेशक उसके इशारे पर हमारे धूर्त सत्ताधीश पाउच तो दूर जनता के मुंह से निवाला छीन सकते हैं।

सभी राजनीतिक दल चाहे कांग्रेस, भाजपा या अन्य सभी काली कमाई से ही चुनाव जीतते हैं। जीतकर इन पूंजीपतियों की काली कमाई के लिए काली लेकर, उनके काले कानून बनाते हैं स्वयं काली कमाई करते हैं और जनता को मुफ्त कफन दान कर अपनी जय-जयकार करवाते हैं।

बुहराष्ट्रीय कम्पनी के कमीशन और लूट के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधि. 06

पेक्ड खाद्य के नाम, लूटा जाएगा जनता को

बेचा जाएगा मिलावटी, पुराना अस्वस्थ कर खाद्य सामग्री

राष्ट्र की सत्ताधारी कांग्रेस और उसमें शामिल गिरोह के साथ ही राष्ट्र के सभी राज्यों के सत्ताधारी राजनेताओं को मोटा कमीशन बांटो और जैसा चाहो जो चाहो कानून बनाकर राष्ट्र की जनता सिर पर थोप दो, जिसके अनेकों उदाहरण है, जिसमें सबसे ज्वलंत उदाहरण है, राष्ट्र की जनता के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनी जिसमें रिलायंस इंडियन कम्पनी आईटीसी, हिन्दुस्तान लीवर, टाटा, पेप्सीको, पारले, मेक्डोनेल जैसी बड़ी और जालसाज कम्पनी को मोटे लाभ दिलवाने और बदले में मोटी दलाली व कमीशन हड़पने के लिए शोपा गया खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है।

हर बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी का इतिहास रहा है कि उन्होंने भारत के सत्ताधीशों की भ्रष्ट, कमीनशखोरी और हरामखोरी की मानसिकता को समझा। भारत में कदम रखने से पहले ही उन्होंने अपने पक्ष में जनता को लूटने और अपनी महानता व श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए पैसा फैंका और कानूनी मजबूरी प्राप्त करने का तमाशा देखा। अपना कारोबार कैसे जनता को बर्बाद करने के लिए, कदम बढ़ाए, जैसा कि खाद्य, बीज और कृषि में कीटनाशकों के उपयोग के लिए बीज अधि. 1967 खाद्य अधि. और कीटनाशक अधि. 1970 से पहले ही लागू करवा दिए। इसके बाद डोउ केमिकल्स ने अपने यूनियन कार्बाइड की यूनिट भोपाल में प्रारंभ की जिसका कि समझदार सत्ताधीशों ने अधिकारियों ने विरोध भी किया, पर जिन्होंने विरोध किया उन्हें खदेड़कर भ्रष्टों ने धन हजमकर भोपाल में उसका कारखाना चालू कर ही दम लिया, जिसने कृषि में सभी खाद्यान्नों, दलहन, तिलहनों, कपास, सब्जियों और मसालों की फसलों में कीटनाशकों को बढ़ावा दिया और वह उस बहुराष्ट्रीय के व्यापार को दिया गया। बढ़ावे ने सारी फसलों को विप्रेला बना दिया। अब इस नए कानून खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 में ऐसे कीटनाशकों के प्रयोग से उत्पन्न फसलों की जांच और उन पर प्रतिबंध लगाकर एक तरफ आम किसानों को तो दूसरी तरफ इस अदृश्य विष की आड़ में छोटे और मझौले व्यापारियों को समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया जो इन बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को ऊंचे दामों पर माल बेचने में प्रतिस्पर्धा में पटखनी देते है और उनके षडयंत्रों को जो एक तरफ जनता को लूटने के षड्यंत्रों को तो दूसरी तरफ उनके एकाधिकार स्थापित करने के मंसूबे पर पानी फेर देते हैं।

इसी डाऊ केमिकल्स की यूनियन कार्बाइड 40000 से ज्यादा की मौत और लाखों को शारीरिक रूप से बीमार कर दिया था, जिसके बीमार अभी भी दवाओं के दम पर जिंदा है। जबकि अपराधियों का 28 साल बाद भी कुछ नहीं बिगड़ा और तो शान से जिन्दगी गुजार रहे हैं। उसके बने कीटनाशकों के विष युक्त भोजन का करोड़ो लोग सेवन कर रहे हैं। इसका सबसे दुखद तहल यह है कि 30 प्रतिशत फसलों के 42 वर्षों में सभी प्रकार के बीजों में कीटनाशकों के अंश हैं।

खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 में बाजार में खुले खाद्य पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। उसके इतिहास की तरफ और वर्तमान में बाजार से पैकेड खाद्य पदार्थों की स्थिति की तरफ दृष्टिपात करें तो हम पाते हैं कि इस खेत की शुरुआत सबसे पहले 1972 में टाटा धूर्तों ने की थी जब उसने अपनी घाटे में चलती टाटा केमिकल्स के लिए धन खर्च करके नमक में आयोडिन मिलाकर बेचने के लिए न केवल नमक अधि. ही बनवाकर पूरे राष्ट्र में सादा नमक बेचने को कानून अपराध का दर्जा दिलवाकर पूरे देश में बिकने वाले 5 पै. प्रतिकिलो के नमक को सीधा 2 रुपए किलो बेंचकर करोड़ों रुपए का लाभ कमाकर टाटा केमिकल्स लि. की डूबती नैया का पार लगाया। पेकैड फूड में यह कदम नींव का पत्थर साबित हुआ। जबकि उस समय भी 50 करोड़ की आबादी के इस देश में मात्र 15 लाख लोगों को ही घेंघा रोग के कारण इसकी जरूरत थी। पर उस समय की कांग्रेस के कमीशनखोर चुरकटो ने अपने मोटे कमीशन के लिए 49.85 करोड़ की जेबें ढीली करवाने के लिए पूरा अधिनियम ही बनवाकर आयोडिन नमक खाने पर मजबूर कर दिया। जबकि आयोडीन की अधिकता शरीर की नसों में मस्तिष्क में रक्त रगाव पैदा कर देती है। यही कारण है कि 1975-76 के बाद से मस्तिष्क रक्तस्त्रावों के मरीजों की संख्या प्रकाश में आने लगी। बाद में नमक में आयोडीन का मात्रा को अत्याधिक कमकर दिया गया और अब विज्ञापनों में स्पष्ट कहा जाने लगा कि आयोडीन तो उड़ जाता है। तो हरामखोर टाटा के जालसाजों, जब उड़ ही जाता है तो मिलाए जाने का नाटक मात्र लूटने के लिए ही नहीं किया जा रहा। पिछले 40 वर्षों से। ये पेकैड फूड की ऐतिहासिक कड़ी है। बेशक कांग्रेस की इस चाल के विरुद्ध पहले जनसंघ, फिर जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी ने मंचों से तो कई बार लोगों को बताया आंदोलन किए वादे किए और सत्ता में बैठते ही कमीशन बांध कर सब भूल गए। जैसा कि तत्काल में भाजपा सरकार ने किया, जब म.प्र. के सभी छोटे बड़े खाद्य विक्रेता खाद्य सुरक्षा और मानक अधि. 06 के विरोध में हड़ताल पर 9.10.11. अप्रेल को गए तो भाजपाई सरकार ने एक तरफ तो व्यापारियों से वादा किया कि किसी के हितों का भी नुकसान नहीं किया जाएगा। जबकि दूसरी और बहुराष्ट्रीय कम्पनी से मोटा कमीशन डकारने के लिए इस अधिनियम को लागू करने के लिए प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने प्रदेश के सभी खाद्य निरीक्षकों जो अब खाद्य सुरक्षा अधिकारी बना दिया गया है और 11,12,13 अप्रैल को भोपाल की प्रशासनिक संस्था में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। वास्तविकता यही है कि न केवल केन्द्र सरकार वरन् देश की सभी राज्य सरकारें भी चाहती है कि 5 करोड़ से ज्यादा खाद्य विक्रेताओं को शीघ्र समाप्त कर सारी सामग्री की विपणन व्यवस्था इन बहुराष्ट्रीय कम्पनी के हाथों में चली जाए ताकि इन सबको अरबों रुपए का कमीशन हर महीने मिलता रहे।

पेकैड फूड में जो शुद्धता का शिगुफा छोड़ा जा रहा है, उसका अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब से बहुराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कम्पनी पानी को शुद्ध बनाने के लिए खेती में उपयोग किए जाने वाले घातक रसायनों का उपयोग कर पानी को कीटनाशकहीन बनाती और बेंचती है। तब विष शरीर में एकत्रित होकर युवा अववस्था में ही ब्रेन हेमरेज, हृदयघात, किडनी फेल, लकवा, कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर रहा है। इन सब बातों पर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं जब शीतल पेय पिलाने के नाम यह घातक विषकांड पकड़ा गया तो इन जालसाज कोक, पेप्सी, थम्सअप, पारले से मोटा धन डकार कर उस विष को भी अमृत बनाकर कानून ही बदलवा डाला । भारत में विष की 0.00045 प्रतिशत तक उपयोगी है तो ये सब यूरोपीय देशों में क्यों नही?

खाद्य तेलों में 38 प्रतिशत मूंगफली, सोयाबीन में मिलावट का कानून यह कह कर बनवा लिया कि असली तेल पचता नहीं तो है हरामखोर जालसाज धूर्तों अभी 25-40 वर्षों से पचना बंद हो गया। इसके पूर्व सहस्त्रों वर्षों से सबकुछ पच रहा था। अब किसी भी ब्रांड के खाद्य तेल में शुद्धता की तो दूर, असली तेल की खुशबू तक नहीं जैसे, सरसों के जो तेल इंदौर में पेक होते हैं, उसमे कीमत भी तिगुनी अर्थात 80 रुपए लीटर का तेल पेकैड 100 ग्राम की शीशी 20 रुपए में मिलती है, जिसमें सरसों तो नाम को भी नहीं। बदबु आवश्य मिलेगी। मूंगफली, सोया और रेपसीड की रंग मिलाकर गहरा पीला अवश्य कर दिय जाता है। ये हे पैक्ड फूड और खाद्य सामग्री की हकीकत।

अब जरा बहुराष्ट्रीय कम्पनी की यह बहुविधि भारी विज्ञापन करने वाली दूध से बनने वाली चॉकलेटों, बार दो देखें, जब-जनावर ही नहीं, गाय, भैंसों का असली दूध बाजार में ही क्या सांची और अमूल वाले नहीं पिला पा रहे तो इनके पास चाकलेट, आइस्क्रीम बनाने के लिए कहां से आ रहा है। कुछ वर्षों पूर्व मालनपुर जिला भिंड के केडबरी प्लांट में 7 टैंकर नकली दूध पकड़ा गया था। अर्थात क्रीम, बटर, बिस्कुट आदि सब खूबसूरत पैकिंग का छलावा है, जिससे रंग, अधिक समय तक स्वाद खुशबू बनाए रखने के प्रेजरबेटिप्स भी मिलाए जाते हैं। जिन्हें बच्चे चाब के खाते हैं और छोटी उम्र में ही बीमारियों के शिकार होते हैं, जिसमें अपच, उल्टी, दस्त, जैसी साधारण बीमारियों से लेकर हार्निया, एप्रेडिंग्स तक सब शामिल हैं। विदेशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनी के साथ हमारे देश के भुखेरे सांसदों और विधायकों को भी यही मंशा है कि उन्हें तो इन के नौनिहाल और युवा चिकित्सालयों में सड़ते रहे। अकाल मृत्यु के शिकार होते रहे। कम से कम बहुराष्ट्रीय कम्पनी की दवाएं बिकेंगी तो उस पर भी तो ये कमीशन खाएंगे। भारत में इसे पेकैड खाद्य सामग्री के कारण हमारे राष्ट्र में चिकित्सालयों का गोरखधंधा भी खूब फल फूल रहा है।

पैक्ड फूड की पैकिंग सामग्री बढ़ाएगी भारी प्रदूषण

पूरा विश्व बढ़ते पॉलिथीन के प्रयोग से भारी प्रदूषण फेल रहा है। इससे हमारा देश भी अछूता नहीं है। दुधारू पशुओं की मौत के साथ ही यह नाले, नालियों के पानी को रोककर बाढ़ की स्थिति तक पैदाकर देता है। जैसा कि पिछले कई वर्षों से मुंबई में हो रहा है। पर यह समस्या केवल मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर और चेन्नई की ही नहीं शहरों से लेकर पूरे देश से लेकर ढाई लाख से ज्यादा गांवों तक पैर पसार चुकी है। जिसके पीछे मूल कारण यही पैकिंग की एल्युमिनियम फाइल से लेकर साधारण पॉलीथिन तक पैकिंग में उपयोग की गई सामग्री से ही है। जो वर्षों तक नष्ट नहीं होती। यदि एक लाख टन कचरा प्रतिदिन भी निकलता है, जिसमें 60 प्रतिशत कचरा अर्थात 60 हजार टन केवल देश के 20 महान नगरों का ही होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा पैक्ड खाद्य इन्हीं महानगरों में बेंचा जाता है। 30 प्रतिशत कचरा देश के 500 नगरों और 10 प्रतिशत कचरा जिसकी आबादी कुल देश की आबादी का 30 प्रतिशत है। गांवों में निवास करती है और न्यूनतम पैक्ड सामग्री का उपयोग करती है। पर इस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के आने के बाद पूरी तरह से लागू होने के बाद यह कचरा 1 लाख टन से बढ़ कर 3 लाख टन प्रतिदिन हो जाएगा, जिसे पूरे भारत की धरती पर आसानी से ढांका जा सकता है, जिससे कृषि भूमि को सदा के लिए समाप्त किया जा सकता है। 2 से 5 वर्ष तक इस चादर को बिछाए रखिए धरी का सारा पानी सूख जाएगी और धरती, आसानी से बंजर बन जाएगी। क्योंकि धरती के अंदर पानी नहीं जाएगा तो कुछ उगेगा नहीं। वर्तमान में पूरे विश्व में धरती हरियाली, सूखते नदी तालाब, बदलता मौसम के भय से पूरा विश्व आक्रांत है। हमारे सत्ताधीश गिद्ध आक्रांता क्लो अपने कमीशन डकारने के लिए भारी बैचेन हैं। मीडिया के बड़े-बड़े प्रकाशक न केवल पैक्ड फूड की शुद्धता के नाम पर भांडों की भांति धूर्त घोर प्रशंसा करने पर तुले हैं। इनके पास अपनी अक्ल तो होती नहीं। धूर्तों, बहुराष्ट्रीय कम्पनी के जालसाज और सत्ताधीश जैसा इनको बनाते हैं तो छाप दिया और दूरदर्शन पर प्रसारित कर दिया जाता है। चाहे खाने वाला मरे या धरती बंजर हो इनकी बला से, क्योंकि इनकी अक्ल तो सत्ताधीशों और पूंजीपतियों के पास गिरवी होती है। इसलिए जैसा वो नचाते हैं। ये नाचने में बड़ा गर्व महसूस करते हैं। इन्हें तो विज्ञापन मिल जाए, मोटी शराब कबाब की पार्टी और लिफाफा मिल जाए, फिर इनसे अपराधियों का भगवान बनाकर पूजाकरण देते हैं। पैक्ड सामग्री की पैकिंग की ये घोर विकट समस्या कौन सत्ताधीश धूर्त समझेगा। पैसा खुदा तो नहीं पर धरती पर खुदा से कम भी नहीं। इसके लिए 90 प्रतिशत बिकने को तैयार, आने वाली थी ही रोये तो रोये।

रुपए के अवमूल्यन से काली पूंजीलाने वालों का भारी लाभ

पेज 1 का शेष

जो सब अमेरिकी डॉलर की विश्व मान्य मुद्रा के रूप में ही लगाया गया है। यह अघोषित रु, का भारी अवमूल्यन डॉलर के साथ ही है अवमूल्यन के भारी शुभ एवं लाभकारी परिणामों के रूप में जब घोषित तौर पर अवमूल्यन किया जाता है। इसके पीछे कारण होते हैं निर्यात को बढ़ावा देना जो वर्तमान में न केवल अघोषित है, वरन् उसे बाजार की गतिविधियों से नियंत्रित माना जा रहा है। निर्यातकों को भारी मुनाफे का सौदा है बशर्ते उनके निर्यात मूल्य पहले से ही बुक हो। स्वामित्व है जो डालर मिलेंगे उसको रु. से परिवर्तन होने पर 10 प्रतिशत डॉलर की बढ़ी हुई कीमत कैसे मिल जाएगी। दूसरी ओर आयात को घपना होता तो भी अवमूल्यन भारी लाभकारी होता है। आयातो को हतोत्साहित करना होता है तो बढ़ावा मिलता है। इस अवमूल्यन से हमारे क्रूड के आयात की लागत सीधे ही 10 प्रतिशत बढ़ गई। साथ ही जो दवाएं और माल अमेरिका व अन्य राष्ट्रों से अन्तरराष्ट्रीय मुद्दा डॉलर के रूप में क्रय किए जाते हैं। स्वाभाविक ऐसे सारे आयात जैसे चीनी सामान आदि 10 प्रतिशत ज्यादा महंगे पढ़ेंगे। पर यह भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि चीनी सामान पहले ही इतना स्तरहीन होने से सस्ता होता है कि उसके सामाने स्तरीय या ब्रांडेड माल की कीमतें दुगुनी होने से कोई बिक्री पर असर नहीं आएगा। अब जहां तक डॉलर की कीमतें बढ़ने को कोई अन्तरराष्ट्रीय कारण भी स्पष्ट रूप से सोचने नहीं आता जबकि अमेरिका और अधिकांश यूरोपीय राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था स्थाओं को पटरी पर लाने की कोशिश में लगे हैं। वहां की अर्थव्यवस्थाओं को भी इन बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने नोंच कर न केवल बर्बाद कर दिया वरन् एक घंटे में आने की स्थिति में लाखों कर्मचारियों को बेरोजगार कर बाहर निकाल दिया और पूंजी लेकर वहां से भागकर भारत जैसी सदाबहार बाजार व्यवस्था पर कब्जा जमाने के लिए जो पूंजी भारत में निवेश कर रहे हैं उसका भी भारत में अपने आप ही 10 प्रतिशत बढ़ोतरी हो गई। अर्थात काले धन और विदेशी पूंजी जो कि जालसाज बहुराष्ट्रीय कंपनियों की पूंजी भारत में निवेशित की जा रही है। वह भी 10 प्रतिशत बढ़ कर निवेशित हो रही है। वह कमीशन की वसूली भी इस अवमूल्यन से आसानी से हो जाएगी। भारत का वित्तमंत्री प्रणव और प्रधानमंत्री मनमोहन जो कि अर्थशास्त्री भी हैं और विदेशी विश्वविद्यालयों में व्याख्याता रह चुके हैं चाहें तो आधा घंटे में इस अनावश्यक अवमूल्यन का बाजार में कुल दैनिक लेन-देन में लगने वाले अमेरिकी डॉलर की मांग से मात्र 10 प्रतिशत ज्यादा रिजर्व बैंक से आपूर्ति कर उसकी मांग को समाप्त कर अवमूल्यन को आसानी से रोककर डॉलर की बढ़ती कीमतों को हतोस्ताहित कर सकते हैं मात्र एक सप्ताह भी 10 प्रतिशत से ज्यादा डॉलर की आपूर्ति से आसानी से घटाए जा सकते हैं। जो बहुत छोटा खेल है।इसके विपरीत जब नियत हो खोटी हो दोनों धूर्तों की, उनका उद्देश्य ही काले धन वालों को लाभ पहुंचाना ही है तो जानबूझकर रिजर्व बैंक यूएस डॉलर की घरेलू विदेशी व्यापार में कमी उत्पन्न कर मांग की आधिक्य बनाए रखकर रुपए को जान बूझकर निम्नता की ओर धकेल रहा है। इससे अरबों रुपए हर दिन का लाभ स्वयं वित्तमंत्री और मनमोहन कमीनश के रूप में स्वयं या उनकी जालसाज फौज कमा रही है।

साप्ताहिक समय माया

एमपी एनर्जी रेग्युलेटरी कमीशन- कमीशन खोरों का अड्डा

हर वर्ष 2 बार बढ़ाती कीमतें- विद्युत कं. फिर भी घाटे में

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाने मंडल की कं. बेचने की तैयारी

भारत की आजादी के बाद नेहरू गांधी ने राष्ट्र में जिस मिश्रित अर्थव्यवस्था को लागू किया था, उसी के कर्णधार वर्तमान कांग्रेसियों ने मोटा कमीशन डकारने और अपना काला धन निवेशित करने के लालच और विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन की आड़ में उन सब निगमों, कंपनियों, विभागों जो सरकार के अंतर्गत कार्य करते थे, पहले सरकारी कंपनियां बनाने, फिर उनकी अंश पूंजी बेचने फिर घाटे दिखाकर निजी हाथों में पूंजीपतियों को सौंपने के षड्यंत्र का हिस्सा था, म.प्र. विद्युत मंडल का 5 कंपनियों में विखंडन, विखंडन के बाद उसमें देश की सबसे हरामखोर, जालसाज, निकम्मी इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारियों की फौज बैठाने और हजारों करोड़ हजम कर इन कंपनियों को हर वर्ष घाटे में दिखाकर रिलायंस के अंबानी, टाटा, हिंडाल्को, जिंदल जैसे जालसाजों को सौंपने इन गिद्ध, जालसाज पूंजीपतियों को अत्यधिक कम कीमतों पर जमीन, पानी व अन्य सुविधायें उपलब्ध करवाकर बिजली उत्पादन की इकाईयां लगाने के न केवल अवसर दिये गये वरन 60-70 पै. यूनिट की बिजली को मोटा कमीशन रु. 1 से 2 प्रति यूनिट के हिसाब से ये भाजपाई मुखेरे रु. 5 से 8 रु. प्रति यूनिट बिजली खरीदने का सौदा कर चुके हैं।

खरबों रु. की जनता के धन से निर्मित संपत्तियों का सौदा जिसमें विद्युत लाइनें, खंभों से टावर तक, सब स्टेशन वितरण प्रणालियां, शहर के बीचों-बीच अरबों रु. की जमीनें आदि तक ये हरामखोर, निजी कंपनियों का बेचकर या अन्य तरीकों से अंतरित करोड़ों रु. डकारने का मंसूबा पाले हुए जिसमें इन सत्ताधीश हरामखोर मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों का कालाधन भी निवेशित होगा या बदले में अपना मोटा शेयर ऐंठ लेंगे। धीरे पूंजीपतियों को हस्तांतरित कर दिया जायेगा जैसे सकों को इन जालसाज शूकरों की फौज ने जो जनता के पैसे से बनाई और विकसित की गई थी। टोल टैक्स ठेकेदारों को सौंप कर अरबों रु. प्रति माह का कमीशन डकारते हुए, कुछ सड़कों में जिसे दिलीप बिली कौन को सौंपा गया है यथार्थ में मुख्यमंत्री का ही काला धन लगाया गया है। बीओटी के नाम पर जनता को लूटने के लिये छोड़ दिया गया है। वही हाल विद्युत मंडल की 5 कंपनियों का भी किया जा रहा है।

मंडल के बनाये ताप और जल विद्युत केन्द्रों को कोयले और पानी की कमी बताकर भ्रष्टाचार की गंदगी में लोट लगाने वाले शूकरों की फौज ने अच्छे रागसे सारणी, वीरसिंगपुर पाली के कई ताप विद्युत केन्द्र इसीलिए कभी कोयले की कमी, कभी प्लांट पुराना हो गया है, कभी रखरखाव पर ज्यादा खर्च आ रहा है और हम निजी कं. से कमीशन डकारकर बिजली खरीदी नहीं कर पा रहे हैं। 1250 में वा के प्लांटों को कबाड़ बनाकर रख दिया। जल विद्युत केन्द्रों, बरगी, इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, सरदार सरोवर को बैंकिंग के तहत बेची जा रही है। प्रदेश के उपयोग के लिये बिजली मोटे कमीशन डकार कर महंगी खरीदी जा रही है।

कमीशनखोर, हरामखोर और जालसाजों से म.प्र. विद्युत नियामक कमीशन में भी बैठे तो सेवानिवृत्त इंडियन एव्यूसिंग सर्विस अधिकारी पूर्व मुख्य सचिव राकेश साहनी ही है। जिन्हें विद्युत कंपनियों की बैलेंसशीट तक 5 वर्ष के बाद भी समझ नहीं आई,. महीना करोड़ों में डकारकर घाटे की लाभ-हानि और चिट्ठों को आंख मींचकर मंजूरी देकर 8 वर्ष में दो बार कीमतें बढ़ाने की अनुशंसा कर देता है। घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक जो औसतन रु. 5 प्रति यूनिट घरेलू व्यावसायिक रु. 8 से 15 प्रति यूनिट बेची जाने के बाद भी हजारों करोड़ का घाटा दिखा रही है। जबकि वहां भ्रष्ट आईएएस खुले में रु. 1 अरब से ज्यादा प्रतिमाह की कमाई करने में जुटे हैं। अनाप-शनाप खरीदी, रखरखावों के झूठे बिलों के ठेकेदारों को जो कि वहां बैठे इंजीनियरों, सेवानिवृत्त इंजीनियरों की फर्जी

फर्मों ने पूरे प्रदेश की तीनों विद्युत वितरण, पारेषण और उत्पादन कं. को इन प्रबंध संचालक आईएएस के साथ मिलकर नोंच खसोंट का अड्डा बना रखा है।

उपभोक्ताओं को ठगने, यांत्रिकीय विद्युत मीटरों को जो 25-25 वर्षों से लगे रहकर सही खपत बता रहे थे, जानबूझकर दिग्गी दानव ने उन्हें बदलवाकर 1998 में 40 से 200 प्रतिशत तक तेजकरण कर ऐसे इलेक्ट्रानिक मीटर रु. 900/- की औसतन खरीद दिखाकर जबकि उनकी वास्तविक कीमत बाजार में मात्र रु. 150 से 200 रु. थी, अपने रिश्तेदार की फर्म से लगवाये, जिनका जीवन मात्र 10 वर्ष था, जिनकी आयु 2008 में पूरी हो गई।

1 यूनिट विद्युंत की परिभाषा में 1000 बाट का विद्युत बल्व 1 घंटे जलाने पर 1 यूनिट बिजली, 5 से 15 एंपियर के करेंट और 230-250 वोल्ट की शक्ति का उपयोग कर होनी चाहिये, एल्डरनेटिव करेंट के स्तर पर, विश्व के अधिकांश राष्ट्रों में अधिकांश घरेलू उपकरण अर्थात बल्ब, ट्यूब्स, पंखे, कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, मिक्सी, विद्युत मोटरें, टीबी, चार्जर्स, कम्प्यूटर्स इसी स्तर पर अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर बनाये व उपयोग किये जाते हैं। हर विद्युत उपकरण पर उसका वाट लिखा होता है, उपयोग के लिये विद्युत की मानक स्थिति 230-250 वोल्ट एसी, 5 से 15 एंपियर लिखा होता है। अर्थात 100 वाल्ट का पंखा जब लगातार 10 घंटे चले तो 1 यूनिट की बिजली की खपत होनी चाहिए। परन्तु वास्तविकता में 3 से 5 घंटे चलने पर ही 1 से 2 यूनिट खपत दिखाने लगते हैं। मीटर अर्थात मीटर 200 % तेज चल रहा है, मतलब यह है कि उपभोक्ताओं से न केवल बिजली की कीमतें बढ़ाकर वसूली की जा रही है, स्वयं शासकीय स्तर पर कंपनियों ने जो मीटर लगाये हैं तो भी स्वयं चोरी कर उपभोक्ताओं से दुगुनी वसूली कर रहे हैं।

फिर अधिकांश गंदी बस्तियों से लेकर पॉश कालोनियों में सीधे तारों पर हेकड़ी बनाकर बिजली चोरी करवाई जा रही है, जिसका घाटा आम ईमानदार उपभोक्ताओं को जेब से वसूला जा रहा है। क्यों नहीं इनका सतर्कता विभाग हर बस्ती में शाम 6 बजे से लेकर 12 बजे रात तक ऐसे लोगों को पकड़ता, पर ठेके पर काम कर रहे मीटर रीडर्स से लेकर ऊपर उपयंत्री, सहा. यंत्री तक सबका महीना बंधा हुआ है जो कुल कंपनियों के चिट्ठे में भी घाटा बढ़ाने और दिखाने के काम आता है, यही हजारों करोड़ का घाटा कुछ समय बाद इन कंपनियों को बेचने का मुद्दा बनकर बड़े। पूंजीपतियों को हस्तांतरित करने के बहाने बेचने के काम आयेगा,

जब पूंजीपतियों के हाथ में होगी ये कंपनियां तब जनता का घोर शोषण करेंगे, फिर रु. 10 से 25 रु. प्रति यूनिट भी बिजली मिल जाये सन् 2025 तक भी तो भी जनता धन्य मानेगी, कर्मचारियों, अधिकारियों, इंजीनियरों, मजदूरों को भी ठेके पर न्यूनतम वेतन ही मिलेगा फिर ये यदि वेतन, भत्तों की मांग करेंगे तो सीधे ही बाहर का रास्ता दिखा दिया जायेगा, तब न केवल विद्युतकर्मियों वरन लंगड़ फंसाने वालों से लेकर आम उपभोक्ता को भी समझ आयेगा, कि क्या होता है पूंजीवाद, सारे नियम कानून शोषण के लिये पूंजीवादियों के होते हैं।

निजी क्षेत्रों में पूंजीपतियों ने विद्युत कंपनियां खरीदने से पहले ही ऐसे कानून अपने पक्ष में बनवा लिये हैं कि वो कितना भी झूठा अनाप-शनाप दें, उपभोक्ता को भरना ही पड़ेगा अन्यथा सीधी गिरफ्तारी की व्यवस्था है। ऐसे करोड़ों रु. के अनाप-शनाप बिलिंग को औने-पौने वसूलने के लिये ये जालसाज झूठे ही लोक अदालतें भी लगा लेते हैं। जिसमें सारे कर्मचारी अधिकारी बिजली कं. के ही होते हैं। जो उपभोक्ताओं को डरा-धमकाकर वसूली करते हैं। वैसे ही जैसे फोन कं. बीमा व्यवसायियों, बैंकिंग कं. अपने झूठे बिलों, क्षतिपूर्तियों, मनमाने ब्याज, शुल्क लगाकर इन लोक अदालतों में करती हैं, जबकि लोक अदालतों में वास्तविकता न्याय विभाग के कर्मचारी, अधिकारी और न्यायाधीश इन जालसाजों से दूर, बैठते ही नहीं, लोक अदालत में, गौर करने की बात ये है कि आसानी से इन्हें लोक अदालतों के नाम अपने कुकर्मों को ढंकने और वसूली करने के लिये लोक न्यायालय परिसर कैसे और क्यों उपलब्ध करवाये जाते हैं। जो सिद्ध करता है, पूंजीवाद में कैसे सब कुछ पूंजीपतियों के इशारों पर चलकर सत्ताधीश जनता के शोषण के लिये कैसे नाचते हैं।

जिस पूंजीवाद के विरुद्ध सन् 2003-04 से समय माया ने प्रकाशित करना शुरू किया, उसकी सत्यता और शोषण के विरुद्ध पूरे यूरोपीय राष्ट्रों में दंगे, धरने-प्रदर्शन हो रहे हैं। हमारे भ्रष्ट, जालसाज सत्ताधीश कैसे पूंजीपतियों के सामने नतमस्तक हो मोटा कमीशन डकार कर पानी, बिजली, सड़क, रेल जो भारत में सरकार के अंतर्गत आती थी बेचने पर तुले हैं।

दे.अ.वि.वि. दलालों और जालसाजों का अड्डा

इंदौर का देवी अहिल्या विश्वविद्यालय चपरासी से लेकर रजिस्ट्रार और कुलपति तक अधिकांश व्याख्यता, प्राचार्य तक अधिकांश विद्यार्थियों से नोच खसोट करने के और जिंदगियां बर्बाद करने वालों का अड्डा बन चुका है, कहीं 17-17 वर्ष से परीक्षाओं के परिणाम घोषित नहीं हो रहे हैं। सोच सकते हैं जिन विद्यार्थियों के 17 वर्ष से परिणाम घोषित ही नहीं हुये उनकी जिंदगियां उनके माता-पिता के न केवल पैसे वरन् सपनों को इन हरामखोर, जालसाजों ने कैसे बर्बाद किया, न वो बेचारे पढ़े-लिखे कहलाये न नौकरियां मिली। सेमेस्टर के नाम पर छः माह तो दूर वर्षभर परीक्षायें नहीं होती और या फिर 1 सेमेस्टर समाप्त हुआ नहीं कि 1 माह बाद ही दूसरा सेमेस्टर शुरु चाहे पढ़ाई हुई हो न हुई हो। पूरे देअविव में दलालों, यौनलोलुपो, जालसाजों का जाल बिछा हुआ है, जिसमें पुराने छात्र नेता, जो अब राजनीति में बैठे हैं। किसी ने फोटोकापी के बहाने वर्षों से दलाली का साम्राज्य चला रखा है। तो कोई किसी बहाने वसूली कर रहा है। वि.वि. के कार्यालयों में बैठे चपरासी स्तर के कहीं बाबुओं का काम कर रहे हैं। तो कहीं आगंतुक कक्ष में बैठे हैं। विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर पास करवाने तक सारे कार्य अवैध तरीके से करवाने के लिये चारों तरफ गिद्धों की फौज मंडराया करती है। जिसके आये दिन समाचार-पत्रों में समाचार छापा करते हैं। पर देवी अहिल्या के कुलपति से लेकर नीचे तक किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती, सारे के सारे मोटी चमड़ी के भ्रष्टों को कोई कहीं असर नहीं होता, न किसी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होती है। जबकि इनके इन कृत्यों के विरुद्ध आसानी से साक्ष्य एकत्रित कर धारा 120बी, 169, 196, 217, 218 के साथ 420 भारतीय दंड संहिता में प्रकरण दर्ज करवाया जा सकता है। जानबूझकर न केवल विश्वविद्यालय वरन शास. महाविद्यालयों में भी किसी भी विषय, किसी भी डिग्री कोर्स चाहे साधारण बी.ए., बी.कॉम, बी.एस.सी. बीबीए, बीसीए, एमए, एमकॉम, एम.एससी के साथ ही प्रबंधन, कम्प्यूटर साइंस, चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी जैसे पाठ्यक्रमों की पढ़ाई पूरी हो न हो, परीक्षायें घोषित कर दी जाती है।

प्रायोगिक परीक्षाओं से लेकर सैद्धांतिक प्रश्नपत्रों तक में पाठ्यक्रमों के बाहर के जानबूझकर प्रश्न पूछ लिये जाते हैं। सेमेस्टर परीक्षाओं में भी हर छह माह में परीक्षायें लिये जाने के स्थान पर कभी-कभी वर्षभर परीक्षायें नहीं होती और कभी 1 सेमेस्टर के बाद 1 माह का भी अंतराल पूरा नहीं होता कि अगले सेमेस्टर की परीक्षायें घोषित कर दी जाती हैं। ये सब वहां बैठे जालसाज दलालों के इशारों पर वहां के व्याख्याता संकाय अधीक्षक, प्रभारी अधिष्ठाता जिन्हें इस दलाली में से मोटा हिस्सा मिलता है। घोषित करते रहते हैं। इसके बाद परीक्षा परिणामों में भी ये सब गिद्ध मोटे दलाल जानबूझकर अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को जिन्होंने पूरे प्रश्नपत्र हल किये भी होते हैं उन्हें भी 2-3 प्राप्तांक दिये जाते हैं। जब पुर्नमूल्यांकन, कुलांक योग, पुनर्निरीक्षण की बात करते हैं तो मोटी फीस मांगी जाती है। उत्तर पुस्तिकायें देखने पर मालूम पड़ता है कि हरामखोरों जालसाजों की फौज ने मात्र एक प्रश्न जांच कर ही अंक दे दिये, जब विद्यार्थी पूछते हैं कि बाकी प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं जांचे गये तो जहां उत्तर पुस्तिकायें दिखाई जाती हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं। यहां तक देखा गया कि एक उत्तर जांच कर जानबूझकर कायपीटी कर दी गई, उत्तरों के पन्नों पर लाल लकीर खींच दी गई, कुछ विद्यार्थियों के कहने पर सूचना के अधिकार में उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कापी मांगी गई तो जवाब आया वह प्रस्तुत है। इस प्रकार हर सेमेस्टर में 1-2 विषय में ऐटीफेटी दे दी गई। ऐटीकेटी देने के बाद उस विषय में पुनः ऐटीकेटी दे दी गई और बाद में विद्यार्थियों से कहा गया कि आप पुनः पूरा डिग्री कोर्स करें, ये शूकरों की गंदी नीच फौज कैसे हजारों विद्यार्थियों का जीवन, कीमती समय और धन नष्ट कर रही है, इस पर आये दिन समाचार-पत्रों में छपने के बाद भी कोई खोज खबर तो ली ही नहीं जाती, उन्हें ही पूरी प्रणाली में भी बदलाव नहीं किये जाते। अनेकों विद्यार्थियों ने जो इन सबको लेकर विश्वविद्यालय के चक्कर काटते हैं। इस बीच में अनेक दलाल प्रगट हुये और कहाकि रु. 8-10 हजार लगेंगे और हम गारंटी से पास करवा देंगे। छात्राओं से कहा जाता है कि रु. 5 हजार लगेंगे परन्तु कुछ समय हमारे साथ अकेले में गुजारना होगा, हम गारंटी से पास करवा देंगे, जब हमने पूछा कि उस दल्ले का नाम पता और मोबाइल नं. लेना था, तो उन्होंने हमें बताया कि उसने नाम पता और मोबाइल देने से मना कर दिया और बोला कि इसकी क्या जरूरत है आप तो पास हो जायेंगी, सोच लो वरना ऐसे ही चक्कर काटना पड़ेंगे।

यह शिक्षा जगत का घिनौना चेहरा है। एक बात गौर करने वाली यह रही कि यह सब अधिकांशतः शासकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय के पास में ही ज्यादा हो रहा है। जिसमें निजी महाविद्यालयों के व्यवसाय बढ़ाने ज्यादा प्रवेश देकर मोटी कमाई करने के षड्यंत्रों का ही हिस्सा है। निजी महाविद्यालयों के जालसाज संचालक भी इन षड्यंत्रों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ताकि शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थी परेशान हो, उनके परीक्षा परिणाम जानबूझकर बिगाड़े जायें, बार-बार एटीकेटी दी जाये, यही कारण है म.प्र. विवि अधि. के अध्यादेश 3 के अनुसार परीक्षा परिणाम की घोषणा के उपरांत 6 माह बाद कापियां नष्ट कर दी जाती हैं। ताकि इन हरामखोर श्वानों ने कहां कैसी जालसाजियां कर विद्यार्थियों के भविष्य और धन बर्बाद किये हैं। 6 माह बाद विवाद होने पर रिकार्ड नष्ट कर दिया के नाम पर मूल्यांकनकर्त्ता जेल न पहुंचा दिये जायें।

आखिर क्यों विद्यार्थियों या अन्य के द्वारा फोटोकापी मांगने पर नहीं दी जायेगी अपने बाप की जागीर नहीं, जब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दे दिये हैं कि उत्तर पुस्तिकाओं की फोटो कापी दी जाये। उत्तर पुस्तिका परीक्षा के उपरांत शासकीय दस्तावेज है। जब म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल रु. 100/- लेकर उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकाफी घर भेज सकता है, तो विश्वविद्यालयों को अपनी पारदर्शिता और निष्पक्षता सिद्ध करने के लिये,

(शेष पेज 11 पर)

नर्मदा घाटी लूट प्राधिकरण

कदम-कदम भ्रष्टाचार, नियम कानून ताक में अधिकारी संविदा पर

162 कि.मी. लंबी नहर में वर्म नहीं, फिल्टर नहीं, भराई काली मिट्टी से

म.प्र. की एकमात्र जीवन दायिनी नदी पूर्वी म.प्र. के अमरकंटक से निकलकर म.प्र. के पश्चिमी छोर से गुजरात से निकलकर कच्छी की खाड़ी में गिरती है। इस महानदी नर्मदा पर प्रदेश के दो संभागों जबलपुर में बारगी बांध और इंदौर संभाग के खंडवा जिले के पुनासा में इंदिरा सागर और खरगोन जिले के औंकारेश्वर में जो बांध बने हैं। उसमें हर कदम-कदम पर भ्रष्टाचार किया गया। प्राक्कलन, सैद्धांतिक तौर पर नियम कानूनों और मैन्यूलर के हिसाब से संरचना तैयार कर धन की गणना की गई, परन्तु कार्य को ठेकेदारों के हिसाब से, इंजीनियरों और ठेकेदारों की कमाई के हिसाब से येन-केन-प्रकरेण कार्य किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री, नर्मदा घाटी मंत्री, प्रधान सचिव, सचिव, उपाध्यक्ष, अभियांत्रिकीय सदस्य, प्रशासनिक सदस्य से लेकर मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण, कार्यपालन यंत्री, सहा. यंत्री, उपयंत्री सबको के साथ बाबुओं तक ने लाखों रुपये हजम किये, जिसमें बाबुओं तक के लाखों रु. कीमत के कई प्लांट और मकान है। तो अंदाज लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्रियों जिसमें स्व. अर्जुनसिंग, भाजपाई सुंदरलाल पटवा, कांग्रेसी दिग्गी दानवों से लेकर मंत्रियों, सचिवों, सदस्य अभियांत्रिकीय से लेकर उपयंत्रियों तक ने कैसे बटोरा होगा। यही कारण है कि नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण में एक कार्यालय से पड़ोस के दूसरे कार्यालय तक में स्थानांतरण तक के लाखों रु. लगते हैं। तो उपयंत्री, एसडीओ और कार्यपालन यंत्रियों का खेल रु. 10 लाख से 1 करोड़ तक में होता है। जो मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर उपाध्यक्ष, सदस्य अभियांत्रिकीय तक में बंटता है। फिर सबसे मोटी मुर्गी ठेकेदार ऐसे नकारा निकम्मे इंजीनियरों को बैठाता है जिन्हें एमबी तक भरना नहीं आता फिर ठेकेदार के आई भी ही एम बी भरते हैं। बिल बनाते हैं जिस पर संबंधित इंजीनियर केवल चिड़िया बैठाता है।

मई 2006 में टर्न आधार पर औंकारेश्वर नहर दायीं तट नहर का 178 करोड़ का ठेका हुआ था, जिसे नव. 06 से नव. 08 में पूरा करना था, जिसकी नर्मदा नदी के ऊपर से सीमेंट कांक्रीट की एक्वाडक्ट से बड़वाह में नहर से जोड़ा गया था। यहां पर नहर को तल पर भराई करके नहर बनाई जाना थी जिस की भराई पीली मिट्टी से की जाना चाहिए, महा भ्रष्ट, हरामखोर, धूर्त इंगले जो उस समय कार्यपालन यंत्री था पूरी काली मिट्टी को पलटाकर ही नहर की भराई कर दी थी जो 2007 की बरसात में ही जगह जगह से 15-15 इंच लंगी 1 से 2 फुट चौड़ी दरारें पड़ गई थी। जिसमें न कंस्ट्रेक्शन किया गया, उस पर ही लाल मिट्टी डालकर उस पर न तो निरीक्षण मार्ग बनाया गया, ढंग का और न ही नहर जो कि 9.775 कि.मी., 68.92 कि.मी. में इतनी लंबी होने के बाद भी दोनों तरफ वर्म बनाये गये। तल पर न ही फिल्टर है। अब यदि नहर में धूल, मिट्टी, कचरा गिरेगा तो सीधे ही तल पर गिरकर पूरे नहर के बहाव को रोक देगा, फिर ये चालाकी गांववाले भी स्वयं भरपूर पानी प्राप्त करने के लिये भी कहीं पर भी जानबूझकर भी कर सकते हैं। जबकि बिल में स्वाभाविक तौर पर भराई के लिये पीली मिट्टी को लाना दिखाया गया, भराई, कांट्रेक्शन के बिल लगाये गये, या इस्टीमेट में तो बताया ही गया जबकि जो काली मिट्टी खेतों की पलटाई और भराव किया गया उसमें कांपेक्शन मशीन चल ही नहीं सभी वर्म बनाने के लिये तल से 15 फुट के बाद 5 फुट अर्थात 20 फुट ऊपर उठाना था तो मात्र 15 फुट उठाकर ही काम चला दिया गया जिसका ठेकेदार सोम बिल्डर्स नई दिल्ली था पर उसकी आड़ में महाधूर्त ठेकेदार कर्णसिंग ने सारा जालसाजी पूर्ण कार्य किया और जानबूझकर भूअर्जन, रेलवे पुल, नहर निकालने आदि के कार्यों को विलंब से पूरा किया गया ताकि नहरें जो नवं.08 में पूरी की जाकर 3 वर्ष की गारंटी समय को पूरा किया जा सके, नहरें फूटने, जबकि सीमेंट कांक्रीट में भी नहरों के चालू होने से पूर्व ही दरारें आ चुकी है कि भरपाई के रूप में ठेकेदार फर्म का भुगतान न रोका जा सके, टर्न की प्रोजेक्ट के नाम पर ये भ्रष्टाचार न केवल 32 नं. संभाग में, वरन संभाग क्र. 25 नर्मदानगर में भी हुआ। नर्मदा नगर में तो ठेकेदार ने कार्य जल्दी करने के स्वरूप वहां के ए. इंजीनियर ने उन्हें ही करोड़ों रु. ईनाम दिलवाकर 75% स्वयं और 25% नर्मदा उद्वहन सिंचाई परियोजना में दिलवा दिये, यही हाल खरगोन के नर्मदा विकास सं.क्र. 24 में भी हुआ, ठेकेदार की अनेकों अनियमितताओं, लंबे पत्राचार और शिकायतों और चेतावनियों के बाद भी यहां के भ्रष्ट अभियंता तिवारी ने रु. 16 करोड़ का भुगतान कर दिया और लंबी बंदरबांट कर डाली।

नर्मदा घाटी भ्रष्टाचार विकास प्राधिकरण के ऊपरी नर्मदा परियोजना के जबलपुर में दो मुख्य अभियंता अवंतीबाई सागर बरगी, और अ. बाई सागर के दायीं और बाई तट नहरों से लेकर इंदौर संभाग के 8 जिलों में से 6 जिलों नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण 5 बड़े बांधों जिसमें इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, मान और जोबट परियोजना के 3 बांध ऊपरी नर्मदा परिक्षेत्र के अंतर्गत मुख्य अभियंता ए.के. शुक्ला जो भ्रष्टाचार का धन खर्च करके संविदा नियुक्ति पर बैठाया गया है। जिसके अंतर्गत 2 अधीक्षण यंत्री खेड़ीघाट और धार आते हैं। जिनके अंतर्गत 6 संभागों के अंतर्गत ओरएसपी धामनोद, 32 नं. बड़वाह जिसके पास दायीं बाई नहरें सं. क्र. 16 कुक्षी, संक्र. 8 सनावद, सं.क्र. 20 मंडलेश्वर, सं.क्र. 30 मनावर हैं। जिसके अंतर्गत रु. 2504.80 करोड़ के प्रशासनिक स्वीकृति की परियोजनायें 2009 के मूल्य स्तर पर केंद्रीय जल आयोग ने स्वीकृत कर दी है। उनके पत्र क्र. म.प्र./ 24 / 2009 / एएसी/ 283/ दिनांक 15.07.2009, जिसके अंतर्गत कॉमन जलवाहक के रूप में 12.393 कि.मी. नहरें जो 960 हे. सिंचाई करेंगी, बाई तट नहर 64.11 कि.मी. लंबी नहरें, 20580 हे. सिंचाई, दायीं तट नहर हरण वेग से 162.95 कि.मी. लंबी नहरें 70630 हे. सिंचाई और दायीं तट नहर 32 वहन, 125 कि.मी. लंबी नहरें 54630 हे. सिंचाई करेगी, इसप्रकार 14,6,800 हे. सिंचाई की जाना अनुमानित है, परन्तु यथार्थ यह है कि इससे 1 लाख हे. सिंचाई भी हो जाये तो भी जन-धन का सदुपयोग मान लिया जाना चाहिये, ये सच सिंचाई के पिछले 50 वर्ष के आंकड़े उठाकर सत्यापित किये जा सकते हैं।

यह जालसाजी सर्वे करते समय ही शुरू कर दी जाती है 25% आंकलन जानबूझकर ज्यादा बताया जाता है। उसी आंकलन के अनुसार प्राक्कलन निर्माण में खर्च और उसके लाभ के डाटा तैयार किये जाते हैं ताकि भविष्य में धन डकारने के पर्याप्त अवसर बने रहें। फिर जब इस्टीमेट बनाया जाता है, तब सारे स्तरों का पालन किया जाता है। सैद्धांतिक स्तर पर उसका खर्च बढ़ा-चढ़ाकर बनाया जाता है। जैसे काली मिट्टी खोदने, पीली मिट्टी, दूमट, मुरम, हार्ड मुरम, चट्टान लाल, चट्टान काली, चट्टान खोदने की दरें हर किसी में अलग-अलग होती है। जिसमें इंजीनियर और ठेकेदार मिलकर करोड़ों रु. हजम कर जाते हैं। जैसा कि हर बांध नहरें, गुफाओं, पुलों, सड़कों, मकान और निर्माण कार्यों में घोटाले किये जाने का इतिहास, वर्तमान और भविष्य बना रहेगा और भ्रष्टाचार से धन हड़पने का अनंतकाल तक सिलसिला भी बना रहेगा, फिर इनमें कांक्रीट करने का जो स्तर था न केवल औंकारेश्वर की कॉमन वाटर केरियर दायीं नहर 162.95, दायीं नहर उद्वहन 125 कि.मी., बायीं नहर 64.11 में 10 से.मी. मोटी, दोनों बाजू में तल पर मोटा स्लेब डालने की अपेक्षा उसमें मात्र 7 से 8 से.मी. जो डाली गई और जो डाली जायेगी ही रहेगी। यहां तक कि नीचे पालीस्टर की जो काली मिट्टी डाली जाती है उसकी मोटाई भी स्तर से 25 से 50% तक पतली होती है। यह हाल न केवल औंकारेश्वर में वरन इंदिरा सागर की सैकड़ों कि.मी. लंबी नहरों, माइनर्स और डिस्ट्रीब्यूटीज से लेकर राष्ट्र में अरबों रु. के सिंचाई परियोजनाओं में होता है। औंकारेश्वर के इस नहरों के रु. 2504.8 करोड़ की परियोजना में मात्र कार्य होगा रु. 1200 से 1300 करोड़ का बाकी पैसा ठेकेदार, इंजीनियर्स से लेकर मंत्री कन्हैयालाल और मुख्यमंत्री तक सब दोनों हाथ हजम करेंगे। ठेकेदारों की ऐसी तूती बोलती है कि अपनी पसंद के बाबुओं से लेकर उपयंत्री, सहायक यंत्रियों, कार्यपालन यंत्रियों, अधीक्षण यंत्री और मुख्य अभियंता तक कार्यालयों में बैठाते हैं। स्वाभाविक है हर पदस्थापना में जिसमें बाबुओं को रु. 25-50 हजार, उपयंत्री कार्य के हिसाब से रु. 1 से 3 लाख सहायक यंत्री रु. 10 से 20 लाख, कार्यपालन यंत्री रु. 50 लाख से करोड़ों तक में धन खर्च करके ही बैठाये जाते हैं। स्वाभाविक है भ्रष्टाचार तो हर कदम किया ही जायेगा, पूरी नर्मदा घाटी जालसाज ठेकेदारों की कठपुतली बन नाचती है, चाहे बाबु, उपयंत्री, सहायक यंत्री से लेकर मंत्री और सदस्य इंजीनियरिंग तक, यही कारण है कि महाभ्रष्ट कर्णसिंग, बियाणी जैसे गिद्ध हजारों प्रकार की जालसाजियां करने के बाद भी बैठे हैं। वर्षों से कुंडली मारे और अरबों रु. के काम इन्हीं के हाथों में चल रहे हैं। यही कारण कि समय विस्तार, महंगाई, सीडब्ल्यूसी की डिजाइन, स्तर व कार्य बदलकर इन ठेकेदारों की स्वयं सदस्य इंजीनियरिंग से लेकर मुख्य अभियंता, अधीक्षण यंत्री, कार्यपालन सहा. और उपयंत्री लाभ पहुंचाते रहते हैं। क्योंकि जालसाज ठेकेदार इन हरामखोरों को महीना, प्रतिशत बांटते रहते हैं और वास्तविक लाभार्थी किसान अपने खेतों को सिंचित करने से वंचित होता रहता है।

सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि इन हरामखोर, गिद्धों की फौज नर्मदा घाटी के मंत्री से लेकर उपयंत्री और बाबुओं के बैंक बैलेंसों की सिंचाई जब तक होती रहेगी, जब तक सारे निर्माण कार्य निर्माणाधीन रहेंगे, इनका निर्माण पूरा किसानों की सिंचाई शुरू होगी तो इन श्वानों को रिश्वत के टुकड़ों का भी सूखा पड़ जायेगा।

जानकारी मांगने पर रिकार्ड में आग लगा दी

लो.स्वा.यां. जानकारी के नाम के बल छल

इंदौर। मप्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय का परीक्षण कार्यालय यशवंत क्लब के सामने इंदौर में है। जहां इंदौर संभाग के 14 जिलो के 20 से ज्यादा संभागीय कार्यालय और दो वृत कार्यालय इंदौर उज्जैन के नियंत्रित किये जाते हैं। लोक स्वास्थ्य का मुख्य कार्य नगर और ग्रामीण बसाहटों मे पेयजल की आपूर्ति को निकासी की प्रबंधन भी करना है। पेयजल के नाम पर राज्य और केन्द्र शासन अरबों रुपया खर्च करता है। यहां पर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आवंटन मिलता जिसमें पेट्रोल डीजल खरीदने से लेकर गिट्टी सीमेंट पाईप लाईन पानी की मोटरें वाल्व विद्युत सामग्री की अरबों रुपये की खरीदी की जाती है। जिसमें 10 % न्यूनतम कमीशन से लेकर 100% प्रतीशत झूटे बिलों को लगाकर भुगतान कर पैसा हजम कर लिया जाता है। रुपये 2 लाख से कम की खरीदी और निर्माण कार्य बिना निविदा बुलाए संभागों के कार्यपालन यंत्री अपने चहेतों को बांटकर धन हजम करना यहां का प्रिय सगल रहा है। बड़े बडे कार्यो को छोटों में बांट कर 2 लाख रुपये से लेकर 10 से 50 लाख तक खरीदी और निर्माण कार्य को इस ऐतिहासिक जालसाजियों 90 % आंकड़े झूठे होते हैं। अधीक्षण यंत्रीयों और मुख्य यंत्रियों और मुख्य अभियंता से कुछ मामलो मे लेनी होती हैा ऐसी खरीदी जो बड़ी होती है। लघु उद्योग निगम के माध्यम से होती है। इसे इंडेन्ट सन 2004 से 2012 मई तक मु आ. सोनगरा जो मई 2012 तक इंदौर में था और सोनगरा के पूर्व महा जालसाज अपराधी सन 2004 से 2007 तक मुख्य अभियंता जी एस डामोर था। जिन्होंने फर्जी इंडेन्ट 20 का. आ. को जारी कर करोड़ों रुपये डकारे जिसमे् कुछ तथाकथित पत्रकारों ने भी भूमिका अदा की। जिसमे एक जालसाज विभाग का पूर्व कर्मचारी जो वर्षो से मूसाखेड़ी के वृत कार्यालय में बैठा रहा अब पत्रकार बन गया है। उसके नाम से भी इंडेन्ट जारी किये गए हैं। मुख्य अभियंता जी एस डामोर के कार्यकाल में अरबों रु. के 2004 से लेकर 2008 तक हर कदम कदम भ्रष्टाचार योजना आयोजना मदों के खर्चो में हर खरीदी में निमार्म में 20संभागों में बड़े पैमाने् पर किया गया। उस पर सन 1986 में अपनी पत्नी को मारकर साइट पर चला गया और पैसा खर्च कर उसे आत्महत्या करार करवाने से लेकर 4 हत्याओं के प्रकरण भी चले। विभागीय स्तर पर जब से वो विभाग में आया और काम करने् की समझ आई एसडीओ के समय से लेकर प्रमुख अभियंता बनने तक लुटों और लुटाओं का खेल चलाता रहा है।

1992 में खरगोन का अ के समय भी इसने भारी घोटाले किये जिसके प्रकरण अभी तक लंबित है।

सूचना के अधिकार के पत्र 24.10.11 को विभाग को प्राप्त धन आवंटन और उपयोग जानने किस परियोजना मे योजना में तकनीकि और प्रशासनिक स्वीकृति दी, लघु उद्योग निगम को कितने इंटेन्ट जारी किये गये और तीसरा बिन्दू था 07-08,08-09,09-10,10-11 में क्रय पंजी की छाया लिये मांगी गई थी जिसके जवाब में पत्र क्र. 9660/सा. /मुअ/ लो नि वि /2001 इंदौर दि. 22.11.11 भेजा गया जो 28.11.11 को भेजा गया था तो पत्र वाहक के हाथ से भी भेजा जा सकता था चूंकि समय बाधित होने के बाद भेजा गया 26 या 27.11.11 जो 28.11.11 को ही मिलेगा पत्र क्या दिया ये देखें।

अपील 29.11.11 को की गई जिसकी सुनवाई 24.12.11 को की गई और वादा किया गया कि आपको सारी जानकारी मुफ्त दे दी जाएगी। इसके बाद एक पत्र क्रमांक 551/सामा./मुअ/ मप्र लो स्वा यां/2012 दि. 17.01.12 जिसे अपीले अधिकारी मुख्य अभियंता को हस्ताक्षर करना था लो सू अ का अ उबकारा ने हस्ताक्षरित कर रुपये 99,8/- मांगे गये इसके बाद पुनः एक पत्र क्र. 609 /सा. मआ/लो स्वा. यां/ 2012 इंदौर दि 18.01.12 पंजीकृत डाक से भेजा जिसमें रुपये 166314/- मांगे गये थे जो 01.02.12 को प्राप्त हुआ जब इसकी शिकायत मुख्य अभियंता से की गई पांच धाराओं के अंतर्गत प्रकरण को अदालत मे ले जाने के लिए लिखा गया और बताया गया कि ये तीनों पत्र आपकी जालसाजियों के पर्याप्त सबूत हैं तो मार्च अप्रैल और मई तक लगातार यह कहा जाता रहा कि प्रकरण मत लिखवाइये जानकारी आपको मिल जाएगी। 2.06.12 को डीबी स्टार में छपा कि 2004 से 2009 तक का रिकार्ड जलाने की तैयारी कर ली गई।

जब पूछताछ की गई तो पता चला कि रिकार्ड को लगातार जला कर नष्ट किया जा रहा है। जो मुख्य अभियंता डामोर के कार्यकाल का था जिसके निर्देश संभवतः डामोर ने ही संकुल और वर्तमान मुख्य अभियंता सोनगरा को दिये थे जो इसके खास चेले थे। यह तो लो.स्वा. यां. की एक बानगी थी।

साप्ताहिक समय माया

कदम-कदम पर जालसाजियां, जन-धन की लूट का खेल

जेएनआरयुम, एडीबी, ऋण सबका पैसा हजम

सड़कें, पानी, नालियां कुछ भी नहीं, नये करारोपण, खुदी सड़कों की सौगात

इंदौर। नगर-निगम के आये दिन समाचार-पत्रों में जालसाजियों अवैध निर्माणों, धन लूटने और लुटाने, खुदी सड़कें, बदहाल चौराहे, कभी यातायात, घोटाला, कभी स्ट्रीट लाइट घोटाला, निगम की गाड़ियों में पेट्रोल-डीजल भरने से लेकर रख-रखाव और सुधार कार्य घोटाला, सीमेंट की सड़कों पर डामर की सड़कों पर अनावश्यक गतिरोधक, पेंशन, सफाईकर्मियों की भर्ती से लेकर 400 से ज्यादा कर्मी जो कभी निगम आते ही नहीं उपस्थिति दिखाकर वर्षों से वेतन भत्ते निकाले जा रहे हैं। बाजार शुल्क से लेकर, दुकानों के निर्माण, आवंटन, किराये में भी भारी लूटपाट की गई है। कालोनी सेल, नक्शे सेल, स्वीकृति सेल, भवन अनुज्ञा सेल के भ्रष्टाचार, नियम विरुद्ध स्वीकृतियां, अतिक्रमण कर होटल, दुकान, मकान बनाने के 50000 से ज्यादा घोटाले कदम पर मिलेंगे, जिसमें सब ही भ्रष्ट इंजीनियरों, बाबुओं से लेकर पार्षद तक आकंठ लिप्त हैं। फिर बेचारे आयुक्त, अधिकांश महापौर ने तो जो इन लोगों ने हिस्सा दिया होगा वो ही मिला होगा, अनेकों मामले ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त से लेकर, निम्न न्यायालयों, उच्च न्यायालयों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक चला करते हैं। निगम के भ्रष्ट, जालसाज, अधिकारी भी फर्जी कार्यवाहियां, झूठे शपथ पत्र देकर न्यायालयीन व्यवस्था को ही झूठे सिद्ध करने पर अपनी महानता समझते हैं। यह भी इनके कारनामों का छोटा सा हिस्सा है। अभी दुकानों के लायसेंस उसके ठेके को अपने चहेतों को बांटकर पत्रों की सुर्खियां बटोर रहे हैं। चुने हुये और चयनित होकर आये हुए सभी अधिकारी भी, पार्षद भी अपने अपने हिस्से बटोरने में जुटे हैं।

बच्चों के जन्म और लोगों की मृत्यु प्रमाण पत्रों में भी लेन-देन के बिना कोई कार्य आसानी से नहीं होते। स्वास्थ्य विभाग में भी जब 5 अगस्त 11 से सारे खाद्य निरीक्षकों की सेवायें मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वास्थ्य सेवायें म.प्र. शासन के खाद्य एवं औषधि विभाग के अधीन कर दी थी, तो वहां के पार्षद, स्वास्थ्य विभाग प्रभारी व खाद्य निरीक्षकों ने उसके बाद भी 250 से ज्यादा नमूने लेकर रु. 10 लाख से ज्यादा की कमाई की, जिन दुकानदारों से लेनदेन नहीं हो पाया। ढंग से ऐसे लिये गये नमूनों की सूची सूचना के अधिकार में प्राप्त की गई है, इस भ्रष्टाचार और गैर कानूनी कार्यों पर जिलाधीश, संभागायुक्त, मुख्य चिकित्साधिकारी से लेकर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन तक ने इन ठगों से कोई पूछताछ नहीं, साथ ही खाद्य विक्रेताओं से उनके नमूने भरने का अधिकार पत्र भी नहीं मांगा, अभी भी खाद्य निरीक्षक नगर निगम में बैठकर वसूली कर रहे हैं। जबकि इनकी सेवा में पूर्णकालिक रूप से खाद्य एवं औषधि विभाग को सौंप दी जानी चाहिए थी। नगर की साफ-सफाई, वर्षा के मद्देनजर नालों-नालियों की सफाई का जिम्मा भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। जिसकी औपचारिकतायें भारी बिल बनाकर भुगतान के लिये अवश्य की जा रही है।

पूरे नगर में अरबों रु. खर्चकर जिसमें जनता की भी भागीदारी थी हर गली-मोहल्ले में सीमेंट की सड़कें बिना नालियां बनाये बना दी गई, अब थोड़ी सी बरसात में भी चारों तरफ ताल-तलैय्या भर जाती है। जिससे मलेरिया और हैजा फैलने का तो खतरा बना ही रहता है। साथ ही रात्रि में सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था के अभाव में जनता के न केवल कपड़े खराब होने है और गिरने-पड़ने और चोट लगती रहती है पर पानी निकासी की व्यवस्था के अभाव में महानगर में भी ग्रामीणों सी जिंदगी जीने के लिये मजबूर हैं। पूरे शहर में कांक्रीट की सड़कों के दोनों ओर जो सीमेंट ब्लाक्स लगाये गये थे, उन्हें पुनः उखाड़कर फिर उल्टे-सीधे तरीके से लगाया गया ताकि हर पार्षद को बिल लगाकर रु. 2-5 लाख कमाई का मौका मिल सके, सड़कों पर जो कि सीमेंट की थी जानबूझकर डामरीकरण करवाया गया, स्पीड ब्रेकर बनाये गये ताकि जनता के हाथ-पैर टूटे और ये डामरीकरण स्पीड ब्रेकर सीमेंट ब्लाक्स के बिल भी लाखों रु. में बनाकर हजम कर सकें।

यह कहानी नगर के 69 वार्डों की ही नहीं पूरे प्रदेश के हर नगर की हर गली-मोहल्ले की है, ताकि पार्षद मोटी कमाई कर सकें। इंदौर में एडीबी से व जेएनआरयूएम में सीवरेज प्रोजेक्ट क्या स्वीकृत हुआ, जालसाजों ने बिना कांटूर मेप और रोपो मेप के अरबों रु. के प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृत करवा लिये। जहां मुख्य सड़कों से लेकर गली-मोहल्ले तक की सड़कों के दोनों ओर जालियां युक्त छोर पर नालियां होनी और बननी चाहिए थी वहां हरामखोरों, जालसाजों ने केवल मुख्य मार्गों मुख्यतः एबी रोड पर स्टार्म वाटर लाइन भर डालकर अपने कर्त्तव्यों की इतिश्री कर ली जबकि नियमित रूप से सड़कों के दोनों ओर नालियां होनी चाहिये थी और उनका नियमित बहाव कबीटखेड़ी के सीवरेज प्लांट की तरफ जाना चाहिये,बरसाती पानी के तेज तूफानी बहाव के लिये स्टार्म लाइन होती है, जो बरसाती पानी को तेजी से प्राकृतिक नालों और नदी की तरफ ले जा सके, ताकि नगर में बाढ़ के हालात निर्मित न हो, पर इंदौर नगर निगम के इंजीनियरों की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय के का.अ.डी.के वर्मा, परियोजना कार्यान्वयन इकाई के बघेल व प्रशासनिक अधिकारियों ने करोड़ों रु. डकारने के लिये नियमित सीवरेज की महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृत अवश्य कराया होगा परन्तु ठेकेदार कं. के साथ मिलकर केवल स्टार्म लाइन डालकर नियमित लाइन को उसमें जोड़ने का षड्यंत्र नियोजित किया, जबकि नियमित सीवरेज में आने वाले कचरे से स्टार्म पाइप लाइन में भी कचरा जमेगा और बरसाती पानी का बहाव सड़कों से बहकर साफ होने की अपेक्षा नीचे वाले स्थानों पर उल्टा बहकर बड़े-बड़े तालाबों की शक्ल ले लेगा, इससे निचली बस्तियां और सड़कें बरसात में न केवल जलमग्न हो जायेगी वरन बदबू से महामारी फैलने का भी अंदेशा बढ़ेगा, बेशक वह महामारी भी सभी के लिये कमाई के रास्ते अवश्य खोलेगी, फिर निगम कर्मियों अधिकारियों को तो बूढ़ा मरे या जवान उन्हें तो लूटने से काम।

दूसरी ओर पीने का पानी की कहानी भी वैसे तो हर दिन समाचार पत्रों में, मारपीट लड़ाई-झगड़ों से लेकर पानी के लिये कत्लेआम तक न केवल इंदौर में वरन प्रदेश के देश छोटे-बड़े नगरों से लेकर महानगरों तक में आये दिन छपती व टीवी न्यूज चैनलों पर दिखाई जाती है। इसलिए महत्वपूर्ण मुद्दा होकर भी कोई महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी इंदौर में इसलिये महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि महापौर कृष्णमुरारी मोघे भले ही काजल की कोठरी में बैठकर पाक-साफ होने का ढोंग करें, पर मुझे ये पेपर वाले महापौर जी की पत्नी द्वारा कमाई और पानी टैंकर वितरण की कहानी भी छाप दिये रहे, किस प्रकार सत्ताधीश भाजपा के पार्षदों को भी पानी के टैंकर खरीदकर अपनी और अपने रिश्तेदारों को नाक बचाने का प्रयास कर रहे हैं और महापौरन बाई पानी से कैसे कमाई कर रही है, सच भी है घर के आटे के कनस्टर को महापौर नहीं, उनकी पत्नी ही देखती है, अगले वर्ष चुनाव हैं। जब महापौर नहीं रहेंगे भूख तो तब भी लगेगी, मोघे जी पद से हट जायेंगे तब यदि बैंक बैलेंस नहीं हुआ तो नेतागिरी कोई सरकारी नौकरी थोड़े ही है, जो करो या न करो, जाकर बैठ जाओ तो भी वेतन तो मिलेगा, सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन, इसलिए नर्मदा का तीसरा चरण आने के बाद भी पानी की जानबूझकर लाइनें फोड़ी जाना, टंकियां किसी भी बहाने न भरना, फिर टैंकर से पानी की आपूर्ति के नाम निगम से इस वर्ष भी रु. 3 करोड़ ज्यादा खर्च कर टैंकर दौड़ाये गये ताकि 69 वार्डों के पार्षदों को कम से रु. 2 से 3 लाख की करवाई जा सके, गर्मी के मौसम में।

भारी दावे किये जाने के बाद भी कहां गया 90 एमएलडी पानी तीसरे चरण का, 360 एमएलडी पानी आने के बाद भी कहां पी गयी पूरी फौज सब नई कालोनियों को करोड़ों रु. हजम कर अवैध कालोनियों में मोटे-मोटे 6 इंची कनेक्शन देकर उनका भला किया जा रहा है, फैक्ट्रियों, पानी के पाउच भरने वालों जिसकी 170 से ज्यादा गली मोहल्लों में पैकिंग मशीनें लगी है। क्यों रिंगरोड और बाईपास से घुमाकर लाई गई लाइनें इसलिये ताकि महापौर, आयुक्तों से लेकर निगम के, नर्मदा के इंजीनियर्स हर महीने मोटी कमाई कर सकें, जो पानी तृतीय चरण आने के पूर्व एमआईजी, अंबेडकर नगर, नेहरु नगर, उत्तरी-पूर्वी, मध्य, पश्चिमी और दक्षिणी इंदौर की बसाहटों को मिल रहा था, तृतीय चरण आने के बाद वह आधा रह गया कहां डकार गयी हरामखोर, जालसाजों की फौज पूरा पानी।

वसूली के नाम पर आमजन को ही परेशान किया जाता है। उन्हीं पर सारे टैक्स थोपे जाते हैं पर खास जन बड़े पूंजीपति, नेता, उद्योगपति, सरकारी अधिकारी से चुप्पी मार ली जाती है। आखिर रेडियो कालोनी में बैठे अधिकारियों के बंगलों पर 24 घंटे मुफ्त पानी क्यों बांटा जाता है? उनसे मिल क्यों नहीं वसूले जाते, क्या उन्हें जनधन से वेतन नहीं मिलता फिर करोड़ों रु. के घोटालों के जिम्मेदार रु. 200-500 का अपने कनेक्शन के हिसाब से बिल क्यों नहीं भरते? परन्तु अधिकारी होने का दंभ सरकारी संपत्ति अपने बाप की जागीर है, बस केवल बैंक में बैलेंस भरते हैं। नल, बिजली आदि की जरूरत ही नहीं हैं। आखिर धारा 4 में परियोजना कार्यान्वयन इकाई सारे नक्शे, प्राक्कलन, ठेकेदारी फर्मों के नाम, टंकियां बनाने और उनके बिल भुगतानों की प्रतियां सार्वजनिक निरीक्षण इसीलिये नहीं रखते क्योंकि हरामखोर अधिकारियों और फर्मों की जालसाजियां जनता के सामने आ जायेंगी। सूचना के अधिकार में पत्र दिये गये, जवाब पत्रानुसार न दिये जाने पर अपील लगाई गई जो न केवल परियोजना कार्यान्वयन इकाई में वरन नगर निगम इंदौर में भी महीनों बाद अटकी पड़ी है। क्योंकि जालसाजियों के दस्तावेजी सबूत कैसे दिये जायें, सूचना के अधिकार में मांगी गई जानकारी कभी समय पर नहीं दी जाती तो सूचना अधिकार अधि. 05 की धारा 4 के ब बिन्दु के 17 बिन्दुओं की जानकारी नगर निगम की साइट पर 7 वर्ष बाद भी कैसे डाली जा सकती है, अन्ना धूर्त और मूर्ख धारा 4 की जानकारी को विभागीय इंटरनेट साइटों पर डालने की लड़ाई लड़े तो अवश्य ही देश की जनता को इन हरामखोर चयनित शासकीय सेवकों और चुने गये पार्षदों, विधायकों, सांसदों के भ्रष्टाचारों पर लगाम लगाने और पकड़ने का मौका मिल सकता है। फिर हर विभाग के, नगर निगमों पालिकाओं में भ्रष्टाचार और जालसाजियों पर हर सप्ताह, पाक्षिक और मासिक पुस्तिकायें और पुस्तकें प्रकाशित कर चयनित और चुने हुए दोनों के चाल, चरित्र जनता को प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

निजी व शास. शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों का धन व समय की घोर बर्बादी

लूट, शोषण और अय्याशी के अड्डे हैं शिक्षण संस्थायें

परीक्षा व परिणाम क्यों नहीं किये जाते पूर्णतः कम्प्यूटराइज्ड और पारदर्शी

राष्ट्र में शिक्षा के नाम पर पेट्रोल,डीजल से लेकर अधिकांश सेवाओं पर शिक्षा अधिभार की वसूली पिछले 25-26 वर्षों से की जा रही है। बेशक केन्द्र व राज्य सरकारें शिक्षा के नाम पर हजारों करोड़ हर राज्य में खर्च कर रही हैं। इसके दूसरे ओर का सच यह भी है, अकेले म.प्र. में जन शिक्षा केन्द्र के आयुक्त और सचिव वर्णवाल जो धन वितरण कर रहे हैं, रु. 250 करोड़ से ज्यादा के बजट के हर गांव-गांव में जो स्कूलों का निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं, उसका सबसे भारी मजाक देखिये कि उन अधिकांश स्कूलों की आधारभूत संरचना और नक्शे का कार्य के नाम से श्रीमती वर्णवाल ही करोड़ों रु. हजम कर रही है। इसके नक्शे और प्राक्कलन के बाद भी सारा कार्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को करना पड़ता है। अब चूंकि आयुक्त की पत्नी का ही नक्शा है, जो उनकी शान में गुस्ताकी भी नहीं की जा सकती।

दूसरी ओर राज्य सूचना केन्द्रों के केन्द्र प्रभारियों को ही करोड़ों रु. का बजट देकर उनसे ही निर्माण कार्य करवाये जा रहे हैं। जो पूर्णतः गैर तकनीकी सरकारी, शिक्षक से जिसका कार्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाना था, स्वाभाविक है करोड़ों रु. का बजट हजम किया जा रहा हैं पर किसी को देखने-सुनने की फुर्सत केन्द्र से राज्य सरकारों तक किसी को नहीं हैं कि आखिर जन-धन का क्या सदुपयोग किया गया, यह धन की बर्बादी शासकीय अधिकारियों द्वारा शिक्षा के नाम पर की जा रही है। इसके दूसरी ओर का शिक्षा का व शिक्षण संस्थानों का परिदृश्य और भी गंदा और घिनौना है। प्राथमिक से पूर्व प्रि नर्सरी, नर्सरी से लेकर लूट का सिलसिला प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक से होता हुआ महाविद्यालयीन, विश्व विद्यालयीन शिक्षा तक केवल लूट, शोषण और अय्याशी की पूंजीवादी दुकानदारी में बदल चुका है। लोकतंत्र में शासन में बैठाये गये चुने हुए प्रतिनिधि सांसद, विधायक, पार्षदों से लेकर पंचों तक सब को वसूली चाहिए, इसलिए हर शासकीय सेवाओं यथा मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य को पूंजीपतियों के हाथ सौंप कर उनसे मोटी वसूली कर या स्वयं के संस्थानों की स्थापना कर जनता का हर तरह से शोषण करना चाहते हैं। शिक्षा का जबसे निजीकरण होना शुरू हुआ है, तब से जानबूझकर न केवल शहरों में वरन जहां-जहां निजी स्कूलों की दुकानदारी चलने लगी है, गांवों में सरकारी स्कूलों के बंद होने की भी परंपरा शुरू हो चुकी है। क्योंकि वहां के हरामखोर शिक्षकों को घर बैठे वेतन मिलता रहता है तो क्या जरूरी है स्कूल जाने की, फिर यदि युवा शिक्षक-शिक्षिकायें हैं तो विद्यार्थी आ भी जायें तो शिक्षक-शिक्षिकायें अपनी मस्ती और अय्याशी में व्यस्त रहते हैं। भाड़ में जाये सरकारी स्कूल और उनके विद्यार्थी, बेशक निजी शिक्षण संस्थाओं में भी खेल तो चलता है परन्तु बदनामी के डर से ये बातें ज्यादा सामने नहीं आतीं, वही हाल माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से लेकर महाविद्यालयीन शिक्षा के भी हैं। फिर निजी शिक्षण संस्थाओं में तो एक-एक कमरे में ही नर्सरी से कॉलेज तक की शिक्षा व केवल इंदौर में वरन अधिकांश छोटे से लेकर बड़े महानगरों तक में चल रही है। सरकारी शिक्षा विभाग, जिला शिक्षा अधिकारी तक बिना विद्यालयों के परिसर देखे, वहां की सुविधायें और शिक्षण स्टॉफ देखे बिना ही मान्यतायें तक वर्षों से खुले में धन लेकर बांट रहा है। जबकि शहरीय क्षेत्रों में विद्यार्थियों की विद्यालय शुरू होने से वाली प्रार्थना और राष्ट्रगान तक वर्षों से सड़कों पर हो रहे हैं। फिर भी जालसाजों की मान्यतायें बरकरार हैं। ऐसे अनेकों स्कूल संचालक हैं जिन जालसाजों ने खुले में फर्जी अंकसूचियों और शाला छोड़ने का प्रमाण-पत्र बांटे और बेचे हैं। और अभी भी तो मान्यतायें लेकर न केवल स्कूल चला रहे हैं और लाखों रु. की छात्रवृत्तियां आदिम और अनुसूचित जाति की डकार रहे हैं। 90% निजी संस्था ये भ्रष्ट और जालसाजों के अड्डे हैं। जिनमें मोटी फीस वसूली जाकर भी शिक्षण घटिया है। 5वीं के बच्चे को हिन्दी पढ़नी नहीं आती है। तो 8वीं के बच्चों को 13 का पहाड़ा, इंग्लिश हिन्दी पढ़ने की तो दूर की बात है। बस सबके राजनीतिज्ञों से संबंध है। किसी पार्षद का स्कूल है तो कोई किसी नेता का रिश्तेदार है। शासकीय स्कूलों में भी अब भ्रष्टाचार के लिए अनेकों शाखायें जिसमें मध्याह्न भोजन, गणवेश पुस्तकें, सायकल वितरण में लाखों रु. के घोटाले करने के अवसर मिल रहे हैं। केन्द्र व राज्य शासन अरबों रु. हर वर्ष खर्च कर रही है। परन्तु शिक्षक भी क्या करे, कभी निर्वाचन में तो कभी जनगणना में कभी पोलियो मिशन में लगा रहता है तो छात्रों को कौन पढ़ायें।

राष्ट्र के मानव संसाधन विकास मंत्री वैसे तो कानूनी जालसाजियों का बड़ा पिटारा है, जो निजी शिक्षण संस्थाओं, निजी महाविद्यालयों, उच्च शिक्षा तकनीकी, प्रबंधन, कम्प्यूटर साईंस, चिकित्सा आदि के निजी शिक्षण संस्थाओं की दबे-छिपे लाभांवित करने के लिये कानून तक बनवा लेता है, जिसमें निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से लेकर मोटा कमीशन डकारकर राष्ट्र में विदेशी महाविद्यालयों, विश्व विद्यालयों को खोलने और चलाने की छूट की पैरवी कर शिक्षण सुधारने का दावा करता है, तो दूसरी ओर शिक्षकों की शिक्षा और प्रशिक्षण का सच भी उजागर कर वास्तविकता भी बयान करता है। यथार्थ में शिक्षा और शिक्षण कार्य को सबसे ज्यादा बर्बाद किया आरक्षण ने, जो स्वयं कृपांक से उत्तीर्ण होकर आये शिक्षक हों तो उनकी कृपांक की शिक्षा से विद्यार्थियों को शिक्षण और भविष्य निर्माण की उम्मीद की जा सकती है।

फिर आरक्षित वर्ग को जब सब जगह से कृपाओं, अनुदानों और नौकरियां मिल रही हैं। उसे वो अपना जन्मसिद्ध मानकर वेतन प्राप्त करना भर चाहते हैं। अगर कमाई और भ्रष्टाचार का अवसर नहीं तो क्या जरूरत है पढ़ाने और काम करने की। सरकार को वोट चाहिए तो वेतन देने की कृपा बनाये रखे काम करने और पढ़ाने की उम्मीद त्याग दें। दूसरी ओर जो प्रतिभाशाली सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं, उन्हें तो उच्च कुल में पैदा होने का अभिशाप जिंदगी भर भोगना है। इसलिये उन्हें सरकारी नौकरियों की 25% में कोई पात्रता नहीं यदि उन्हें सरकारी नौकरियां मिल भी गई तो मंत्री से लेकर वरिष्ठों तक सबकी जीवन भर गालिया सुननी है पढ़ाई और काम तो करना ही है, बच्चों के फेल होने पर उनकी नौकरियां चाटने से लेकर सारे दंड भुगतने के लिये तैयार भी रहना है, इसलिये प्रतिभाशाली विद्यार्थी सरकारी शिक्षा या अन्य विभागों की नौकरियों से बच कर ही चलते हैं। तो विद्यार्थियों को पढ़ाये कौन, फिर सरकारी नौकरी मौज-मस्ती और अय्याशी के लिये है या गधों की तरह जीवनभर 24 घंटों दिमाग पर बोझ लेकर घूमने के लिये, विद्यार्थी पढ़े तो पढ़ें नहीं तो जाये भाड़ में, ये सब निजी संस्थानों की उन्नति और कमाई का कारण भी है और सरकारी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के लिये वरदान, शिक्षा के कुछ क्षेत्रों में अरबों रु. की बर्बादी तो हो रही है, पर सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं।

स्वच्छंदता और आधुनिकता से युवा पीढ़ी में बढ़ता बांछपन

पेज 12 का शेष

यह विष शरीर में सीधे ही पहुंचकर सबसे ज्यादा शुक्राणुओं को नष्ट कर पूरी भारतीय युवा पीढ़ी जो इन शीतल पेयों का उपयोग नियमित रूप से करते हैं न केवल गंभीर बीमारियों जिसमें हृदयाघात से लेकर किडनी खराब होना, मस्तिष्काघात, रोग तक युवावस्था में सामने आने लगे हैं। इसके साथ ही पैकेट बंद खाद्य पदार्थ, पिज्जा, बर्गर, पेक्ड ज्यूस जिनमें घातक रसायनों का प्रयोग भी शुक्राणुओं को समाप्त करने और युवा पीढ़ी को नपुंसक और महिलाओं को बांछ बनाने में उत्प्रेरक की भूमिका अदा कर रहे हैं। जिसकी सत्यता की पुष्टि गाहे-बगाहे विदेशी चिकित्सीय संस्थानों की दैनिक समाचार-पत्रों में छपी सूचनायें करती रहती हैं।

भारतीय विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद ने स्पष्ट लिखा है, प्राणी का जन्म यौनाचार से यौनाचार कर अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देना है, यथार्थ में किसी भी प्राणी, वनस्पतियों का यहां इससे ज्यादा कोई उपयोग नहीं। हमारे ऋषियों मुनियों ने न केवल चिकित्सा शास्त्रों में वरन् 'अनेकों' पुराणों में स्पष्ट लिखा है, कि जो नर-नारी पूर्ण रूप से स्वास्थ्य हों वे ही यौनाचार और समागम से अगली पीढ़ी को जन्म दें, अन्यथा यौनाचार ही न करें और करते हों, तो संतानोप्रति के कदापि न करें क्योंकि वह कमजोर पीढ़ी आने वाली भविष्य की पीढ़ियों को दुर्बल और विकलांग बनाकर पूरे समाज को बर्बाद करेगी। जबकि वर्तमान में हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रोग से पीड़ित हैं, हर चौथा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है और ये रोग वंशानुगत चलते चले आ रहे हैं। उस परीभ आधुनिकता के नाम पर पेक्ड फूड, शीतल पेक्ड पेय आदि हम धड़ल्ले से न केवल कर रहे हैं वरन् उसका बढ़ावा देने के नाम पर हमारे धूर्त, गिद्ध सत्ताधीशों ने बहुतराष्ट्रीय कं. से मोटा कमीशन डकारने के लिये कानून तक बना दिये हैं। जिसे नाम दिया है, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 06, जो घोर असुरक्षित, घातक रसायनयुक्त विषयुक्त खाद्य पदार्थ पैक करने के लिये विश्वभर में बदनाम हो चुकी है। और भारत में भी कोक, पेप्सी, केडबरी, आईटीसी, वालमार्ट, युनिलीवर, भारतीय नाम हिन्दुस्तान लीवर, मेक्डाल्ड, भारतीय कं. में रिलायंस सहारा आदि अभी तक उनके वर्षों से पेक्ड फूड को हमारी युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को अपने अधिकतम लाभ के हिसाब से परोसकर नपुंसक, बांझ बनायेंगी। हमारे राष्ट्र के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रिश्वतखोर, कमीशनखोर गिद्धों की फौज से लेकर कृषि मंत्रालय की फौज भी सब जानकर भी चुपचाप है। उल्टे ही वो तो अपने मोटे कमीशन के लिये आंख मींचकर इन कंपनियों को मोटा व्यवसाय मिलता रहे, कानून बनाने, सारे खाद्य पदार्थों को पेक्ड बेचने के लिये छोटे खाद्य पदार्थ विक्रेताओं पर कानून की सख्ता दिखाकर भारी अर्थदंड लगाने जेल पहुंचाने पर आमदा है। युवा पीढ़ी में नपुंसकता और बांछपन के चलते न केवल बहुराष्ट्रीय दवा कंपनियों से लेकर चौराहे-चौराहे पर खुली बच्चा पैदा करवाने के लिये टेस्टट्यूब बेबी सरोगेट मदर, इंफर्टीलिटी सेंटरों की बहुत अच्छाकर लगी है। जिनके यहां 25-30 वर्ष के युवा जोड़ों से लेकर 45-50 वर्ष के बच्चे पैदा करने वाले जोड़ों की भीड़ लगी रहती है। ये एक-एक जोड़े से 5 लाख तक का सौदा कर सीधे ही किसी भी युवा का वीर्य और स्त्री के अंडाणु लेकर परख नली में इकट्ठा कर स्त्री के गर्भाशय में प्रविष्ट करवा कर जिस स्त्री का गर्भाशय कार्यशली है पर अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया धीमी या समाप्त हो चुकी है। बच्चा पैदा करवा रहे हैं पर ऐसे भी प्रकरण सामने आये हैं जिसमें जोड़ों से लाखों रुपये बर्बाद भी कर दिये और वर्षों बाद भी चक्कर लगा रहे हैं और परिणाम शून्य रहे हैं। अकेले इंदौर में ही ऐसे 10 से ज्यादा केंद्र खुल चुके हैं। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में भी ऐसे ठगोरे-डॉक्टरों और क्लिीनिकों की कमी नहीं है। जबकि पूरे देश में ऐसे कम से कम 5000 से क्लीनिक काम कर रहे हैं। कुछ समय समाचार पत्रों में एक समाचार बड़ी शीर्षक के साथ छपा था, कि ऐसे बांझ दंपत्ति ब्राह्मणों के वीर्य की ज्यादा मांग करते हैं। बच्चे पैदा करने के लिये इस पर भारत में विकी डोनर नाम की फिल्म भी बन चुकी है। फिर सरोगेट मदर का व्यवसाय भी भारत में वर्तमान में खूब फलफूल रहा है। अर्थात इन हरामखोर जालसाज कं. के पेक्ड फूड ने पूरे विश्व में नपुंसकता और बांझपन की आधुनिकता भी फैलाई है। जो गंभीरता की ओर इंगित करता है। अभी भी वक्त है, संभालने के लिये कि हम प्राकृतिक रूप से प्रकृति के निकट रहकर अपने जीवन में भी शुद्धता लायें। आधुनिकता कैसा अभिशाप बन रही है। इसको गंभीरता से समझें, हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने हमारे लिये बहुत सी धरोहर छोड़ी हैं उसे अपनायें। स्वच्छंद यौनाचार की अपेक्षा शीघ्र विवाह हो युवा पीढ़ी के 30-35 वर्ष की उम्र तक पहुंचते जीवन नीरस, मस्तिष्क कुंठित और शरीर निस्तेज होने लगता है।

आत्यधिक शिक्षा अच्छा मोटी कमाई, ऐश्वर्य पूर्ण जीवन की लालसा आखिर किसके लिये जब घर में बच्चे ही न हों, आखिर ऐसी महत्वाकांक्षायें पूर्ण करते-करते जिंदगी समाप्त होने के कगार पर आ जाये या पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांछपन आ जायें, फिर शादी कर भी लें, तो स्त्रियों की गर्भित करने के लिये शुक्राणु युक्त वीर्य खरीदना पड़ जाये, या गर्भ निरोधक गोलियों का उपयोग करते करते सदा के लिये गर्भ निरोधित हो जाये और घर में किलकारी सुनने के लिये कोख और वीर्य भी किराये पर लेकर खरीदकर बच्चे पैदा किये जाये, सब कुछ होने के बाद भी यह दुःख जीवन भर सालता रहे कि न जाने किसके वीर्य से पैदा हुआ बच्चा हम पाल रहे हैं। आखिर क्यों नशैला जीवन, स्वच्छंद यौनाचार का कैसा आधुनिक जीवन जी रहे हैं हमारे युवा, माता-पिता, दादा-दादी, नाना-नानी के अतिरिक्त कौन युवाओं के सिर पर हाथ रखकर पूछेगा और समझायेगा।

निजी व शासकीय चिकित्सालय डकैतों के अड्डे

पेज 12 का शेष

उस सरकारी महिला चिकित्सक ने उसे गंभीर बताकर अपने इस ग्रेटर कैलाश में भर्ती करवा दिया गया, भर्ती करने के बाद इन हरामखोरों ने उसे पहले दर्द निवारक लगा दिया तो प्रसव पीड़ा बंद हो गई, बाद में उसे ग्लूकोज चढ़ाते रहे। दो-तीन दिन तक, उस महिला के पिता बाहर बैठे हुए थे, पड़ोस में से ही जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के पी.ए. जोशी जी लंच में बाहर निकले तो उनके पिता जो उनके गांव के पटेल थे उनसे पूछा कि यहां कैसे तो उन्होंने अपनी बिटिया के बारे में बताया कि दो-तीन से ग्लूकोज चढ़ रहा है, श्री जोशी का माथा ठनका, उन्होंने अपनी महिला वरिष्ठ डॉक्टर परिचित थी उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि अगर दो-तीन से ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो महिला के पेट में बच्चा तो मर चुका है तुरंत बच्चा नहीं निकाला गया तो महिला भी मर जायेगी, बाद में उस महिला चिकित्सक ने आकर दो ढाई घंटे तक आप्रेशन कर मृत बच्चे को निकालकर उस महिला की जान बचाई।

उपरोक्त कहानी सामने आने के बाद एक साथ कई रहस्य उजागर हुए कि अधिकांश सरकारी डॉक्टरों के अपने रिश्तेदारों के नाम से अपने निजी नर्सिंग होम और चिकित्सालय हैं। जहां पर सरकारी पैसे से आई न केवल अच्छी और महंगी औषधियां चिकित्सालय सामग्री में चादरें कंबर से लेकर लाखों रु. की मशीनें, यहां तक कि सरकारी कर्मचारी वेतन सरकार से लेकर सेवायें डॉक्टरों के नर्सिंग होम्स में देते हैं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है, इंदौर में ही वर्षों से कुंडली मारे महाभ्रष्ट, जालसाज मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शरद पंडित जो वर्तमान में इंदौर संभाग का संयुक्त संचालक भी है। पत्नी डॉ. आशा पंडित वह भी सरकारी सेवा में है। दोनों ही नॉन प्रेक्टिसिंग एलाउंस भी लेते हैं और उनका स्वयं स्कीम नं. 78 में अपना नर्सिंग आशा नर्सिंग होम के नाम से है। जहां सरकारी 12-15 कर्मचारी अपनी सेवायें देते हैं। उनका वेतन सरकारी खातों से निकल रहा है वर्षों से, अधिकांश दवायें, इंजेक्शन से लेकर आईव्हीएफ फ्लूड्स तक महंगी और सस्ती, अस्पताल की सामग्री में चादर से लेकर बड़ी-बड़ी मशीनें तक इस आशा नर्सिंग होम्स में सरकारी ही हैं। जब डॉ. पंडित का ये हाल है, जबकि पूरे संभाग के सभी सरकारी जिला चिकित्सालयों से लेकर दूर दराज के प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों में सारी औषधियों से लेकर अस्पताल सामग्री, मशीनों तक की खरीद में भी इसका 20% से 50% तक कमीशन ये वर्षों से डकार रहा है। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ग्रामीण बाल स्वास्थ्य जैसे स्वास्थ्य विभाग में भी विभाग और योजनाओं में जहां भर्ती से लेकर निर्माण कार्यों और औषधियों के रूप में भी पिछले 5 वर्षों में इसी डॉ. पंडित ने सबमें मोटी वसूली की है। बेशक स्वास्थ्य राज्यमंत्री महेन्द्र हार्डिया की न केवल सेवा चाकरी के साथ मंत्री की फर्मों जो उनके रिश्तेदारों के नाम से है, काफी खरीद की जाती है। वही हाल स्वा. मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी है सेवा चाकरी के बदले में यह महाधूर्त चाहे कांग्रेस की सरकारें रहीं हो या भाजपा की बंदा 20 वर्षों से कुंडली मारे बैठा है। कम से कम 1 अरब प्रति वर्ष का स्वास्थ्य विभाग की खरीदी और सेवाओं में कमीशन के माध्यम से तो रु. 1 अरब प्रतिवर्ष नगर में चल 300 से ज्यादा नर्सिंग होम्स व चिकित्सालयों से विभिन्न तरीके के कार्यों में यदि रु. 25000 प्रति नर्सिंग होम भी वसूला तो रु. 1 अरब हो जाते हैं। फिर ब्लड बैंक, खाद्य एवं औषधि विभाग के निरीक्षकों, से लेकर 8 जिलों के डॉक्टरों-कर्मचारियों के स्थानांतरण, संविदा नियुक्तियों, औषधि विक्रेता की दुकानों के पंजीयन, पुर्न नवीनीकरण, जांच आदि में भी हजम कर जाता है। फिर जननी सुरक्षा, गरीब मरीजों की चिकित्सा निधि, नसबंदी आदि में भी निजी चिकित्सालयों को भी धन बांटने में डकार लिया जाता है।

सूचना के अधिकार में जानकारी मांगने पर स्पष्ट ढंग से ये हरामखोर सफेद एप्रिन का ये गिद्ध लिखकर दे देता है कि कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई जा सकती है। आवेदक विभाग को परेशान करता रहता है। हाल ही में स्वास्थ्य संचालक डॉ. अमरनाथ मित्तल पर लोकायुक्त छापे ने यह सिद्ध तो कर ही दिया कि अरबों रु. की संपत्ति कहां से आई जो पकड़ी गई वह 10% भी नहीं थी, जहां हजारों करोड़ रु. की खरीदी में सीधा 30 प्रतिशत कमीशन का सौदा हो रहा हो, उससे अंदाज लगाया जा सकता है, वही हाल इसके इस चेले डॉ. पंडित का है। रु. 200 करोड़ प्रतिवर्ष की कमाई में रु. 50 करोड़ भी बांट दिये तो कौनसा मंत्री, कौन सा मुख्यमंत्री, करोड़ों रु. का दूध देती गाय को ठुकरायेगा, जिले के कलेक्टर, कमिश्नर, लोकायुक्त, आर्थिक अन्वेषण हैं तो सब मुसेरों की फौज मुंह से बड़ा टुकड़ा डालो, तो न केवल मुंह बंद कार्यवाही की तो दूर, न टुकड़ा खा सके, न उगल सकें, क्या हुआ नकली दवा फैक्टी कांड में, एक्सपायर्ड दवा कांड में, पीडीपीएल कांड में, चोइथराम के किडनी चोरी कांड में, ड्रग ट्रायल कांड में, ईपीएफ कांड में, लिंग परीक्षण सोनोग्राफी कांड में, जबकि इंदौर संभाग सीएमओ व संयुक्त संचालक कार्यालय कार्यालय में घोटालों और भ्रष्टाचार का अंबार लगा है। यहां तक कि शासकीय चिकित्सालयों में न केवल डॉ. शरद पंडित वरन आशा पंडित भी नॉन प्रेक्टिसिंग एलाउंस लेकर भी खुले में नर्सिंग होम चला रहे हैं। वही हाल प्रदेश के 90% सरकारी डॉक्टरों का है कि वे खुले में नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता लेकर भी खुले में शासकीय औषधियों और चिकित्सा सामग्री का उपयोग कर अपने क्लीनिक नर्सिंग होम्स व चिकित्सालय चला रहे हैं। वरन छोटे-बड़े सभी चिकित्सा केन्द्रों को सुबह 9 से 1 और शाम 4 से 7 खोलकर 7 घंटे सेवायें दी जानी चाहिये, जब इंदौर के ही चिकित्सालय शाम को नही खुलते तो छोटे नगरों और प्राथमिक स्वा. केन्द्रों की तो बात ही दूर है खुलने की, इन सफेद एप्रिन के गिद्धों को अपने नहीं तो दूसरों के निजी चिकित्सालयों में जाकर आप्रेशन करने, सेवायें देने से फुर्सत ही नहीं इस पर भी हड़ताल, भारी वेतन भत्ते चाहिये, सेवायें व सुविधायें चाहिये, तो जब ये सब ही शामिल है, तो कौन किसकी कहेगा, फिर म.प्र. सरकार के दो वर्ष भी नहीं बचे है, कमाई करें और कमाई भ्रष्टाचार से ही होती है न कि ईमानदारी से।

2012 का सबसे बड़ा दिन था 27 मई

पेज 12 का शेष

जीवों और वनस्पतियों के न केवल गुण, धर्म, व्यवहार, आकार-प्रकार में इस प्राकृतिक परिवर्तन के फलस्वरूप परिवर्तन भी अवश्य संभावी है। जो सूक्ष्म और स्थूल दोनों ही प्रकृति के होंगे। केवल वही वैज्ञानिक और प्रकृति प्रेमी ही समझ पायेंगे जो प्रकृति के निकट रहकर सूक्ष्मता से अध्ययन कर रहे होंगे, यह सूक्ष्म के साथ स्थूल परिवर्तन यथा सूर्य की गति का बदलना बड़े दिन का 23 जून से पीछे खिसककर 28 मई होना और छोटे दिन का 23 दिस. से खिसकर 28 नवं. होना है तो स्थूल पर दृष्टि में सूक्ष्मता होना चाहिए। पृथ्वी के झुकने से धरती पर पड़ने वाली चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, नेपच्यून, वरुण आदि की दृष्टि का भी प्रभाव बदला है, जिसे स्पष्ट रूप चंद्र राशियों के साथ देखा जा सकता है। आश्चर्य इस बात का है कि इतना स्थूल बदलाव आने के बाद भी भारतीय खगोलविद, भूवैज्ञानिक, मौसम विज्ञानी भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे, इसके साथ विश्व की जानी-मानी प्रयोगशाला नासा और रसियन, चीनी, फ्रांस और ब्रिटेन आदि देशों ने भी इस परिवर्तन पर अंगुली नहीं और न ही कोई टिप्पणी की है, पर हमारे दावों की पुष्टि आसानी से हमारा हर पाठक सूरज को और रात-दिन के घटने बढ़ने की स्थिति से लगा सकता है। दूसरी ओर यह भी सच है कि न हमारे पास साधन है न स्वयं विषय विशेषज्ञ, हम भी साधारण से सूक्ष्मता की तरफ दृष्टिपात है। जिसका अनुभव पृथ्वी पर न केवल हर मानव वरन हर प्राणी और वनस्पतियां, जलचर, नभचर भी कर रहें होंगे। पर वे व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं।

दे.अ.वि.वि. दलालों और जालसाजों का अड्डा

पेज 8 का शेष

सूचना के अधिकार के अंतर्गत विद्यार्थी की मांग पर तत्काल ही कापी उपलब्ध करवानी चाहिये ताकि विद्यार्थियों को भी अपनी सत्यता जानने का मौका मिले और विश्वविद्यालय को भी अपनी निष्पक्ष कार्यप्रणाली सिद्ध कर प्रदर्शन का मौका मिले, इसके साथ ही विद्यार्थियों के माता-पिता भी जान सकें कि उनके चिरंजीवी क्या गुल खिला रहे हैं अपनी शिक्षा में। वि.वि. में परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के समय अधिकांशतः विषय विशेषज्ञों का अभाव रहता है। पुस्तिकाओं को ऐसे शिक्षकों को भी जांचने के लिये दे दिया है जो विषय विशेषज्ञ तो दूर उस विषय से न केवल उनका वास्ता ही नहीं पड़ा तो दूसरी ओर वे जिस विषय की पुस्तिकाओं को जांच रहे हैं। वरन उनके पास न तो एम.फिल या मास्टर्स की डिग्री होती है, यहां तक कि 12वीं पास जो बाबुगिरी या साधारण स्नातक हैं। उनसे भी परिणाम जल्दी घोषित करने के उत्तर पुस्तिकाओं में नं. छोटे जाते हैं चाहे विषय की समझ हो न हो। विश्वविद्यालयों पर भी सूचना अधिकार अधि.05 लगता है। अधि. 05 लागू 7 वर्ष हो गये, विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक धारा 4 की जानकारी भी इंटरनेट साइट पर नहीं डाल पाया कुलपति से चपरासी तक अपनी निजी संपत्तियों की घोषणायें नहीं की गई है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी भ्रष्टाचारिता और जालसाजियों का, आखिर क्यों नहीं है पारदर्शिता। सूचना के अधिकार के जवाब में स बिन्दु में लिखा है। मूल्यांकन अवधि में नाम घोषित नहीं किये जा सकते हैं। मूल्यांकन तो मात्र कुछ मिनिटों में संपन्न हो जाता है। तो उसके बाद उसका नाम, पद, शैक्षिक योग्यता देने में क्या परेशानी थी विवि प्रशासन को, पर नाम इसीलिये नहीं दिये गये कि मूल्यांकनकर्त्ता की शिक्षा की योग्यता इतनी नहीं थी। अभी वक्त है तरुणाई शांत है अन्यथा अशांत होने पर प्रशासन का क्या होगा वैसे आये दिन धरने प्रदर्शन होते ही रहते हैं। परीक्षा परिणामों को लेकर पर जालसाजों शैक्षिक स्टॉफ के साथ दलालों की कमाई का सवाल है। धरने-प्रदर्शनों से कोई फर्क नहीं पड़ता विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद हो तो हो।

साप्ताहिक समय माया

बहुराष्ट्रीय कं. का विषैले रसायनयुक्त पेक्ड फूड के परिणाम

स्वच्छंदता और आधुनिकता से युवा पीढ़ी में बढ़ता बांछपन

सत्ताधीशों का लालच करेगा भविष्य की पीढ़ी बर्बाद

भारत में, भारतीय संस्कृति के मूल्यों के ह्रास के परिणाम अब सामने आने लगे हैं। प्रसार माध्यमों यथा टीवी, इंटरनेट, मोबाइल जैसे आधुनिक साधनों ने भौतिकवादी आधुनिकता का भ्रम पैदा किया है, जिसमें हमारी वर्तमान युवा पीढ़ी अपने आप को भारी धन्य समझ रही जिस नग्नता, स्वच्छंद यौनाचार की दीवानी हो रही है, उसके दुष्परिणामों में युवा पुरुषों के वीर्य में घट रही शुक्राणुओं की संख्या और युवा महिलाओं में घटती अंडाणुओं की संख्या के कारण बांछपन बढ़ रहा है। महिलाओं में बांछपन के कुछ महत्वपूर्ण कारण जो और सामने आ रहे हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण कारण जो और सामने आ रहे है, उनमें एक यह मुख्य रूप से जो सामने आया कि छात्रायें अपनी शिक्षाकाल में अपने सहपाठियों, प्रेमियों से खुलकर स्वच्छंद यौनाचार करती हैं। इस बहाने वो न केवल आधुनिक होने का प्रदर्शन करती हैं और सुरक्षा की दृष्टि से जो गर्भ निरोधक बाजार में मिलने वाली सैकड़ों गोलियां जिनका प्रचार-प्रसार टीवी पर स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार से लेकर राज्य सरकारें भी भरपूर करती हैं। जिसमें मालाडी के साथ कंपनियां भी अपने गर्भ निरोधक औषधियों का गैरकानूनी रूप से प्रचार-प्रसार करती हैं। स्वाभाविक है कि युवा छात्रायें और महिलायें इनका खुलकर प्रयोग कर रही है। हालात ये हैं, उच्च शिक्षा में अध्ययनरत सहशिक्षा में 10 में से 8 युवतियों के कहीं न कहीं शारीरिक संबंध स्थापित किये और सुरक्षा की दृष्टि से सभी प्रकार के गर्भ निरोधकों जिसमें कंडोम से लेकर निगलने वाली गोलियां भी 10 में 5 महिलायें नियमित रूप से सेवन कर रही थी। यह हालात भारत के छोटे शहरों के है। बड़े महानगरों में स्थिति और भी गंभीर है, माता-पिता अपने में व्यस्त और मस्त हैं। उनके युवा पुत्र-पुत्रियां यदि भविष्य के प्रति सचेत हैं तो वे भी पढ़ाई, दोस्तों और सहेलियों में व्यस्त हैं। नशा, किसी न किसी प्रकार का साथ ही आधुनिकता के झूठे दिखावे और स्वच्छंद यौनाचार में प्यार की आड़ में, दोस्ती की आड़ में सब चल रहा है। यदि माता-पिता दोनों ही नौकरियों में है तो पुत्र-पुत्रियां माता-पिता की ओर माता-पिता पुत्र-पुत्रियों की महीनों शक्ल तक नहीं देख पाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके पीछे उनके ही आशियाने में क्या रंग रैलियां,

नशाखोरी चल रही है, अहसास भी नहीं हो पाता है, नशीली दवायें, गर्भ निरोधक गोलियां, महिलाओं की शादी से पहले ही बांध बना रही हैं। क्योंकि नियमित रूप से गर्भ निरोधक गोलियां लेने से स्त्रियों के धीरे-धीरे अंडाणु बनना और गर्भाशय का मुंह सदा के लिये बंद हो जाता हैं, दूसरी तरफ युवा छात्रों में साथ में पढ़ने वाली लड़कियों के साथ, ऊंची सोसायटी, क्लबों आदि में बहुत साथ न केवल अपनी हमउम्र वरन् अपनी उम्र से दुगुनी भाभियों, आंटीयों के साथ स्वच्छंद यौनाचार वह भी 16 से 25 की उम्र में 24 घंटे में 3-4 बार उन्मुक्त यौनाचार के कारण फिर दोस्तों के साथ न केवल शराब, सिगरेट, नशे में कोकीन, चरस से ज्यादा खतरनाक नशीली गोलियां के नियमित सेवन, फिर यौन क्षमता बढ़ाने बनाये रखने के लिये 15 वर्ष से 25 की उम्र में इतना अधिक सेवन कर लिया जाता है, 30-35 वर्ष की उम्र तक पहुंचते-पहुंचते हमारी युवा पीढ़ी नपुंसकता की ओर बढ़ने लगती है और नपुंसकता पूर्ण रूप से न भी आये तो वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या 100-200 प्रति बूंद या प्रति मिली. भी नहीं बचती। बेशक पुरुष वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या जो प्राकृतिक जीवन शैली में 1910 में 90000 हुआ करती थी वह 1950 तक आते-आते 65000-70000 तक रह गई, 1970 तक 50000 से भी नीचे चली गई, 1990 तक मात्र 20,000-25000 और सन् 2000 में प्रति बूंद 10,000-12000 पर 20-30 वर्ष के युवाओं में ही सिमट गई, सन् 2005 9-10,000 और सन् 2010 तक 7 से 9000 हो रह गई, बेशक इन हजारों जीवित शुक्राणुओं में से 2-4 शुक्राणु ही स्त्री के गर्भाशय में पहुंच अंडाणुओं से मिलकर नये जीवन की रचना करते हैं।

पुरुष वीर्य के शुक्राणुओं को इस तीव्र गति से ह्रास होने में टीवी, इंटरनेट पर उन्मुक्त यौनाचार के प्रदर्शन के साथ ही हमारे भोजन में जिसमें दूध, सही से लेकर फलों-सब्जियों, अनाजों, तिलहनों और दलहनों में बढ़ता खाद का प्रयोग और अनाधुंध जहरीले घातक इंडोसल्फान जैसे विषैली कीटनाशकों के प्रयोग ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। फिर आधुनिकता के नाम पर शीतल पेयों यथा कोक, पेप्सी, थम्सअप, लिम्का आदि जिनमें कार्बन डाइआक्साइड मिलाकर दबाव पेक लिया जाता है और जिसे हम अपनी सांस में छोड़ते हैं, शरीर में पहुंचकर न केवल पाचन तंत्र, लीवर, हृदय और किडनी पर भी असर डालती है दूसरी तरफ शीतल पेयों के जल को कीटाणु रहित बनाने के लिये ये बहुराष्ट्रीय कं. भी कृषि के घातक कीटनाशकों का प्रयोग करती है। जिस पर 2006 में हल्ला मचा था परन्तु इन बहुराष्ट्रीय कं. के जालसाजों ने इस अत्यंत सूक्ष्म बताकर, शरीर की वहन क्षमता के अनुकूल बताकर कानून में ही परिवर्तन करवा दिया था, पर कानून के परिवर्तन से मानव शरीर की वहन क्षमता परिवर्तित नहीं हो गई।

(शेष पेज 11 पर)

11मार्च 11 के चीनी विस्फोटों से धरती 6.5 डिग्री झुकने से

2012 का सबसे बड़ा दिन था 27 मई

28 मई 2012 से दिन छोटे होने लगे, जो 24 जून से होते थे

पृथ्वी के सहस्त्रों वर्ष पुराने नियम सन् 2011 के 11 मार्च को चीनी विस्फोटों जो उसने जापान के निकट किये थे जापानी व्यवस्था का नष्ट करने के लिये उसके परिणाम स्वरूप जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्रों में आग लग गई थी भारी 8.3 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया और भारी समुद्री लहरों का तूफान उठा। जिसे सुनामी का नाम देकर प्राकृतिक सिद्ध करने की कोशिश की वास्तव में चीन ने अपने परमाणुवीय या नाभिकीय समय बाधित बमों का प्रयोग जापान के निकट किया जिसके परिणामस्वरूप अप्राकृतिक स्वरूप का भूकंप, तीव्र हजारों कि.मी. गति की लहरें आई, जापानी द्वीप 24 फुट तक खिसक गये, और पृथ्वी अपनी धुरी पर 6.5डिग्री ज्यादा झुक गई, पहले 23.5 झुकी हुई थी इस प्रयोग से 30 डिग्री झुक गई।

इसके परिणाम हजारों वर्ष पुराने नियम कि 23 दिसम्बर सबसे छोटा दिन और 23 जून सबसे बड़ा दिन हुआ करता था, 11 मार्च 2011 के बाद 28 मई 11 सबसे बड़ा दिन हो गया था, जिस भू वैज्ञानिकों, मौसम वैज्ञानियों का ध्यान भी नहीं गया, पर मौसम में आये प्राकृतिक बदलावों पर मेरी नजर रहने लगी, चूंकि मैं प्रातः सूर्य को जल अर्पित करता हूं, पहली बार ध्यान इस ओर गया कि 28-29 नव. को सूरज दक्षिण से पूर्व की तरफ जाने लगा, और शनैः दिन भी बड़े होने लगे और

23 दिसम्बर तक पहुंचते-पहुंचते यह बढ़ोत्री स्पष्ट होने लगी जो 24 दिसम्बर 11 से होनी चाहिये थी या जैसा कि सहस्त्रों वर्षों से पृथ्वी की प्रकृति थी।

पिछले वर्ष अप्रैल से ही सूर्य की दिशा बदलना समझ तो आ ही रहा था, कई अन्य लोगों से जो बगीचे में घूमने आते थे, पूछा कि यह अहसास और वास्तविक स्थिति में बदलाव आया है तो बुजुर्गों ने इस वास्तविकता की तरफ इंगित किया। 28 नव. 11 की घटना के बाद मेरा ध्यान मई पर था, कि किस दिन से उत्तरायण जाते जाते पलटी मारकर पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू करेगा, 29 मई को लगा कि 28 मई की तरह यह उत्तर की तरफ न जाकर कुछ पूर्व की तरफ आया, 30-31 मई व 1,2,3 जून को स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगा कि यह पूर्व की तरफ बढ़ने लगा है।

इस वर्ष आम की फसल भी बिगड़ी, गेहूं की फसल मार्च के पहले सप्ताह तक पड़ी ठंड और मार्च के तीसरे सप्ताह में पड़ी गर्मी से बहुत अच्छी आई पर आम में बोर फरवरी में दिखना शुरु हुये। अर्थात पूरा प्रकृति चक्र अवश्य ही शनैःशनैः इस बदलाव को स्वीकारते हुए और समायोजित करते हुए बदलेगा ही, कुछ फसलें बिगड़ेगी और कुछ अच्छी आयेंगी, जल-थल, नभचर जीवों, वनस्पतियों की कुछ प्रजातियां सदा के लिये नष्ट हो जायेगी और कुछ नई प्रजातियां आस्तित्व में आने की भी संभावना है।

(शेष पेज 11 पर)

डॉक्टर नहीं सफेद एप्रिन के गिद्ध

निजी व शासकीय चिकित्सालय डकैतों के अड्डे

मानव सेवा के नाम पर चारों तरफ लूट का हो रहा तांडव- मौत के बाद भी वसूली

शास्त्रों में और वर्तमान में भी सामान्य तौर पर रोगियों को जीवन देने वाले चिकित्सकों को भगवान मानकर जनता अभी भी पूजती है, पर अब 90% चिकित्सक सफेद अप्रेन के गिद्धों का गिरोह बन चुका है। जो रोगियों को मृत जानवर मानकर उसके चिकित्सालय परिसर में प्रवेश करते ही उसको स्वास्थ्य जीवन की आस के नाम पर नोंचने जुट जाता है। यह स्थिति शासकीय से ज्यादा निजी नर्सिंग होम्स और चिकित्सालयों में भयानक स्तर तक पहुंच चुकी है। शासन का इस अनावश्यक लूट-खसोट और नोचने की प्रवृत्ति पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है। जिसके कारण ये सफेद अप्रिन के गिद्ध डॉक्टर धड़ल्ले से रोगियों की वास्तविक मृत्यु के बाद भी कई-कई दिनों तक उसे अनावश्यक आक्सीजन लगाकर आईसीयू में रखकर लाखों रु. ऐंठते रहते हैं। यह हाल इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन में ही नहीं पूरे राष्ट्र के 20 महानगरों से चलकर छोटे-छोटे शहरों और नगरों का भी है। जिसमें अरबों रु. की लूट ये डॉक्टर्स प्रतिदिन पूरे देश में कर रहे हैं पर भारतीय लोकसभा के 543 धूर्त सांसद देख कर भी चुप बैठे हैं। वर्षों से स्वास्थ्य के नाम पर ये एप्रिन के गिद्धों को

खुली छूट दे रहे हैं। अभी तक कोई ठोस कानून इस लूट को रोकने या बीमारों की निजी या सरकारी अस्पतालों में पहुंचने के साथ ही दोहरी जांच व्यवस्था ताकि बीमारों की वास्तविक बीमारी का ही इलाज किया जाकर उसे अनावश्यक लूट से बचाया जा सके, नहीं कर पा रहे हैं। इसके विपरीत अधिकांश निजी नर्सिंग होम और चिकित्सालयों हर दिन लूट के नये तरीके सामने आते हैं। जिसमें यहां तक हुआ कि बीमार की अंत तक सारी जांचों के बाद भी रोग पकड़ में नहीं आया और मरीज के परिजनों से वसूली के लिये हजारों रु. की जांचे करवाई गई, उल्टा सीधा ईलाज आईसीयू में चलता रहा, मरीज मर भी गया तो भी उसके मुंह पर आक्सीजन मास्क लगाकर रखा गया और कृत्रिम सांसद के जरिये उसकी सांस चलती दिखाई जाती रही और हर दिन रु. 25 से 50 हजार का मीटर घुमाया जाता रहा, जब परिजनों ने बंद करने के लिये कहा तो उनको सांत्वना दी जाती रही और भावनात्मक दबाव डालकर इन हरामखोर डॉक्टरों ने दस दिन में ही रु. 6 लाख का बिल इंदौर के चेरिटी हॉस्पिटल लि. ने 6 अप्रैल 12 को एक जैन महिला के परिजनों से वसूल लिया, महिला को पेट दर्द की शिकायत में भर्ती किया। 11-12 अप्रैल को प्राणांत हो गया इसके बाद भी उसे 16 अप्रैल तक भर्ती रखा गया। ग्रेटर कैलाश नर्सिंग होम में भी एक महिला जो कन्नौद के आस-पास की रहने वाली थी सरकारी अस्पताल में ले जाया गया।

(शेष पेज 11 पर)

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक- अजमेरा एस.पी. कुमार द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13 प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 299, अम्बेडकर नगर, इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित।
भोपाल प्रतिनिधि- एस.के. भारद्वाज मो. 9074551045, इंदौर कार्यालय- 0731-2530859, मोबा. 9300755803